राष्ट्रीय संस्करण

भारत के पास इंग्लैंड से हिसाब चुकाने का मौका
>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 17

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 27 जून, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

विश्वास.News

गलत दावे के साथ नेहरू का वीडियो प्रसारित ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज-5

जागरण विशेष

बीएयू के हौसले से स्टार्टअप भरेंगे उड़ान

भागलपुर : बिहार कृषि वि. सबौर, भागलपुर ने नवाचारों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। यह अब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के स्टार्टअप को तराश कर उन्हें छोटे-बड़े उद्योग का रूप देगा। ● पेज-7

संपादकीय

द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर : पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार की आदर्श साझेदारी होनी चाहिए, उसे नरेन्द्र मोदी और शेख हसीना ने पुनः परिभाषित किया।

हर्ष वी. पंत का आलेख।

परीक्षाओं पर गंभीर चर्चा का समय : प्रतियोगी परीक्षाएं रद होने के सिलसिले से युवाओं के सपने तो मरते ही हैं, सरकारों की साख भी गिरती है।

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी का दृष्टिकोण। ● पेज-8

फिर से लोस अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला

राजग कामयाब ▶ पीएम मोदी की ओर से बिरला के पक्ष में पेश प्रस्ताव ध्वनिमत से हुआ पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में राजग उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर चुन लिए गए। करीब पांच दशक बाद हुए स्पीकर के चुनाव में बिरला ने विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के उम्मीदवार कांग्रेस सांसद के सुरेश के मुकाबले ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव के जरिये विजय हासिल की। बिरला को चुने जाने के ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव के बाद विपक्ष ने मतविभाजन की मांग नहीं की। इसलिए मतदान की नौबत नहीं आई। हालांकि, चुनाव बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दावा किया कि आम सहमति और सहयोग की भावना का ख्याल रखते हुए विपक्ष ने मतविभाजन पर जोर नहीं दिया। जबकि सत्तापक्ष के लोगों का मानना है कि विपक्ष में मतविभाजन को लेकर मतभेद था। इसीलिए वोटिंग की बात नहीं की गई।

लेकिन चुनाव के तत्काल बाद दोनों पक्षों के सुर अलग-अलग थे। पीएम नरेन्द्र मोदी ने पिछले पांच साल के कार्यकाल के दौरान सदन की मर्यादा और संतुलन बनाए रखने के उनके योगदान की सराहना की। विपक्ष से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सुदीप बंद्योपाध्याय समेत कई विपक्षी सदस्यों ने तंज के साथ बिरला को याद दिलाया कि उन्हें अपनी पुरानी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन पर बहुत बड़ा दायित्व है। उन्हें विश्वास है कि अपनी विनम्रता और कुशल व्यवहार से वह 18वीं लोकसभा में संसदीय कार्यकुशलता के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। पीएम के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम दलों के नेताओं ने बिरला को बधाई देते हुए उनसे निष्पक्ष होने की अपेक्षा की और उम्मीद जताई कि विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी।

पीएम मोदी ने सत्ताधारी राजग की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों और भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से बिरला के समर्थन और अनुमोदन में दर्जन भर प्रस्ताव रखे गए। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत ने केरल से कांग्रेस के आठ बार के सांसद के सुरेश को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने समर्थन किया। इसके साथ ही विपक्षी खेमे की ओर से सुरेश के पक्ष में दो अन्य प्रस्ताव पेश किए गए। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सबसे पहले पीएम मोदी की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर सदन की राय ली। सत्तापक्ष ने हामी भरते हुए प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया तो विपक्ष ने ना कहा। हालांकि, विपक्ष ने मतविभाजन की मांग नहीं की और महताब ने बिरला के अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की।

- आइएनडीआइए ने के सुरेश को मैदान में उतारा, मगर मतविभाजन की नहीं की मांग
- पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिरला को आसन पर ले जाकर बिठाया
- मोदी ने जताई उम्मीद, बिरला संसदीय कार्यकुशलता के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे

मतविभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अलग-अलग सुर

प्रेट्र के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मतविभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अलग-अलग सुर नजर आए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आइएनडीआइए के घटक दलों ने स्पीकर के चुनाव में मतविभाजन पर जोर इसलिए नहीं दिया, क्योंकि वे आम सहमति और सहयोग की भावना बनाए रखना चाहते थे। दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं दी, जबकि कई विपक्षी सांसदों ने मत विभाजन की मांग की। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं है।

संसद भवन में बुधवार को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला को बधाई देने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके पास गए। तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ओम बिरला से मिलने पहुंच गए। इस दौरान नरेन्द्र मोदी तथा राहुल गांधी ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेता, बिरला को आसन तक ले गए। एएनआइ

पीएम मोदी की ओर से पेश प्रस्ताव पारित होने से बाकी अर्थहीन पेज>>3

ईडी के बाद सीबीआइ ने भी केजरीवाल को किया गिरफ्तार

- आबकारी घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए मिला तीन दिन का रिमांड
- शुगर लेवल कम होने से तबीयत बिगड़ने पर दूसरे कमरे में ले जाए गए केजरीवाल

नई दिल्ली के कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के बाद उन्हें लेकर जाते सीबीआइ अधिकारी। प्रेट्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब इस घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल की पांच दिन का रिमांड मांगा। लेकिन अदालत ने केजरीवाल को तीन दिन के रिमांड पर भेजते हुए सीबीआइ को उन्हें 29 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। शुगर लेवल कम होने से तबीयत बिगड़ गई तो केजरीवाल को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थीं।

सीबीआइ ने मंगलवार को केजरीवाल से जेल में तीन घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद बुधवार को अदालत की अनुमति मिलने पर अदालत कक्ष में औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि आरोपित से सरकारी गवाह बने दक्षिण भारत में शराब लाबी के बड़े खिलाड़ी मगुंटा रेड्डी ने बयान दिया है कि आबकारी नीति तैयार होने से पहले उसने केजरीवाल से मुलाकात की थी और उसे पैसों के बदले दिल्ली में शराब कारोबार में मदद का आश्वासन दिया गया था। तथ्यों से पता चलता है कि अधिसूचना कितनी जल्दबाजी में जारी की गई थी। यह सब तब हुआ था, जब कोरोना महामारी चरम पर थी। सीबीआइ ने कहा, आखिर इन सबके पीछे कौन था? यकीनन मुख्यमंत्री। दक्षिण भारत के समूह से जुड़े लोग कोरोना के दौरान निजी विमान से दिल्ली आए थे। उनके कहने पर तैयार की गई रिपोर्ट सरकार के पास ले जाई गई और वह रिपोर्ट ही नीति बन गई। इसमें लाभ मार्जिन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

रेड्डी का बयान विश्वास करने योग्य नहीं : केजरीवाल पेज>>2

विमर्श

नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान का अर्थ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। यह विश्वविद्यालय समूचे विश्व में ज्ञान के प्रसार के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है।

प्रो. महेश चंद गुप्ता का आलेख।

वीआइपी संस्कृति से मुक्त हो रहा प्रदेश : मध्य प्रदेश में डा. मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद से ही वीआइपी संस्कृति से प्रदेश को मुक्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया है, जो अब कई रूपों में सामने भी आ रहा है। इसे ही रेखांकित करती **धनंजय प्रताप सिंह** की डायरी। ● पेज-9

आइसीसी टी20 विश्व कप 2024

आज के मैच (सेमीफाइनल)

अफगानिस्तान vs दक्षिण अफ्रीका	
सुबह 6 बजे	स्थान : तरुबा
भारत vs इंग्लैंड	
रात 8 बजे	स्थान : गुयाना

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

डार्क वेब इंटरनेट की काली दुनिया

गूगल जेमिनी व मेटा एआइ ● पेज-13

जल स्रोतों की दूसरी गणना में गिने जाएंगे झरने भी

नई दिल्ली : केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी तरह के जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार की गणना में जल स्रोतों के रूप में झरनों को भी शामिल किया जाएगा। (पेज-7)

आपातकाल के मुद्दे से लोस में टकराव की शुरुआत

आपातकाल प्रकरण को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते भाजपा सदस्य। प्रेट्र

अरविंद शर्मा ● जागरण

- सदन में प्रस्ताव लाकर स्पीकर ओम बिरला ने की आपातकाल की निंदा
- कहा- इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में थोप दी थी तानाशाही
- कांग्रेस ने किया विरोध, असमंजस में रहे आइएनडीआइए के सहयोगी

नई दिल्ली : ओम बिरला के दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद आपातकाल के मुद्दे पर सदन में बुधवार को तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। स्पीकर ने अपनी तरफ से प्रस्ताव लाकर विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की तीखे शब्दों में भर्त्सना की, जोकि कांग्रेस को रास नहीं आया। बिरला के पहले ही संबोधन में सख्त रुख से हतप्रभ विपक्षी खेमे से भी प्रतिक्रिया आई और हंगामा शुरू हो गया। संबोधन के आखिर में स्पीकर ने आपातकाल के योद्धाओं की स्मृति में सदन में सदस्यों से दो मिनट का मौन रखने का आग्रह किया, जिसे कई विपक्षी सदस्यों ने अनसुना कर दिया और अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। हालांकि जब अध्यक्ष अपना संबोधन पढ़ रहे थे तो कांग्रेस के सदस्य विरोधस्वरूप खड़े थे जबकि बाकी विपक्षी दलों के सदस्य बैठे थे।

देश में आपातकाल लागू होने के 50वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर लोकसभा में स्पीकर बिरला ने कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हम उनकी सराहना करते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष किया और लोकतंत्र की रक्षा की। युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के इस काले सच के बारे में जानने की जरूरत है।

कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए बिरला ने कहा कि भारत को दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर प्रहार किया। लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर तानाशाही थोप दी। मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कांग्रेस को कठघरे में किया खड़ा पेज>>3

हजारीबाग में नीट परीक्षा केंद्र रहे ओएसिस स्कूल के प्राचार्य सीबीआइ हिरासत में

जागरण संवाददाता, हजारीबाग

नीट प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक को आठ घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। प्राचार्य के साथ उस ई-रिक्शा चालक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसने तीन मई को कुरियर एजेंसी द्वारा बाइपास में प्रश्नपत्र उतार दिए जाने के बाद उसे ई-रिक्शा से हजारीबाग एसबीआइ की मुख्य शाखा में प्रश्नपत्रों से भरे ट्रंक पहुंचाए थे। सीबीआइ की टीम प्राचार्य व ई-रिक्शा चालक को शाम करीब पांच बजे हजारीबाग स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस ले गई, वहां उनसे पूछताछ की। बुकलेट का लिफाफा खुले होने को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए। बता दें कि ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के हजारीबाग के जिला को-आर्डिनेटर भी हैं।

नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में बुधवार को झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक (नीली शर्ट में) तथा ई-रिक्शा चालक को लेकर जाते सीबीआइ अधिकारी। जागरण

- पटना में साल्वर गैंग के पास से बरामद प्रश्नपत्र की फोटो कापी का मूल पेपर हजारीबाग में था
- सीबीआइ के आवेदन पर विशेष अदालत ने दो आरोपितों को रिमांड पर लेने की अनुमति दी

पेपर लीक मामले में जांच की सुई अभी ओएसिस को आवंटित बुकलेट पर अटकी है। यह वही बुकलेट है, जिसकी एक कापी अधजली हालत में पटना में परीक्षा से पहले बरामद की गई थी। इस बुकलेट नंबर के मूल प्रश्नपत्र पर ओएसिस स्कूल में एक छात्रा ने परीक्षा दी थी। सीबीआइ उस छात्रा से भी पूछताछ करने वाली है।

सीबीआइ टीम हजारीबाग एसबीआइ की मुख्य शाखा से बरामद फुटेज लेकर स्कूल पहुंची थी। बैंक की तीन मई की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर टीम ने पाया कि बैंक में ट्रंक सीलबंद हालत में पहुंचे थे। स्ट्रांग रूम से बाहर आने के बाद भी इन्हें सीलबंद ही पाया गया। टीम ने परीक्षा के दिन की पूरी गतिविधि की जानकारी लेने के साथ ही इसकी भी जांच की कि हक द्वारा किस स्कूल को कितने बजे ट्रंक सौंपे गए थे।

कटा हुआ था प्रश्नपत्र का एक लिफाफा पेज>>5

सीयूईटी यूजी के परिणाम में हो सकती है और देरी

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा सीयूईटी-यूजी का परिणाम आने में करीब दस से पंद्रह दिन का और समय लग सकता है। हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परिणाम को जारी करने की अनुमानित तारीख 30 जून दी है, लेकिन जिस तरह से अब तक परीक्षा कुंजी नहीं जारी की गई है, उससे साफ है कि इसका परिणाम आने में कम से कम दस दिन का और समय लगेगा। (पेज-5)

दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग सवा चार घंटे तक रहा बाधित

प्रयागराज : देश के सबसे व्यस्ततम दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार को अपराह्न 3.07 बजे बड़ा हादसा हो गया। गाजियाबाद से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर जा रही खाली मालगाड़ी प्रयागराज जंक्शन से आगे बढ़ते ही निरंजन पुल पर डिरेल हो गई। तीन वैगन पटरी से उतर गए। इससे इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन करीब सवा चार घंटे बाधित रहा। रेलवे ने घटना की जांच के लिए एक टीम बनाई है। (पेज-7)

पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती

जासं, नई दिल्ली : पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की बुधवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार, वयोवृद्ध भाजपा नेता आडवाणी को रात 10.28 बजे एम्स के ओल्ड प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। उन्हें यूरिन में संक्रमण से संबंधित परेशानी है। यूरोलाजी विभाग के प्रोफेसर डा. अमलेश सेठ के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है।

राजस्थान में मेडिकल के प्रथम वर्ष के छात्रों से रैगिंग, सात आरोपित निलंबित

उदयपुर : राजस्थान में डूंगरपुर जिला मेडिकल कालेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 50 से ज्यादा छात्रों के साथ रैगिंग की घटना सामने आई है। इस दौरान कई छात्रों की हालत बिगड़ गई। पहाड़ी पर बुलाकर उठक-बैठक कराने के दौरान एक छात्र की किडनी और लिवर दोनों प्रभावित हो गए। मामला सामने आने पर कालेज प्रशासन ने द्वितीय वर्ष के सात आरोपित छात्रों को निलंबित कर दिया है। (पेज-6)

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Scan QR CODE to get UPSC Preparation Insights from VisionIAS Topper's Talk

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
from various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम टॉपर

1 AIR ADITYA SRIVASTAVA — ABHYAAS PRELIMS 2023, 2022 & 2021, ABHYAAS MAINS 2023 & 2022

2 AIR ANIMESH PRADHAN — ABHYAAS, ALL INDIA GS TEST, SOCIOLOGY TEST, LAKSHYA, INTERVIEW

5 AIR RUHANI — ABHYAAS, INTERVIEW GUIDANCE

53 AIR मोहन लाल

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

हिन्दी माध्यम: 28 जून, 9 AM

English Medium: 28 JUNE, 8:30 AM

अधिक जानकारी, रजिस्टर या फ्री काउंसलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट से बात करें

निःशुल्क डेमो क्लासेस उपलब्ध | विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम
Lakshya
UPSC मेन्स 2024: 25 JUNE
UPSC प्रीलिम्स & मेन्स 2025: 2 JULY

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2024
THE REAL RACE BEGINS, ARE YOU READY?
विवक रिवीजन, कंटेन्ट एनरिचमेंट व सतत मूल्यांकन के लिए क्लासरूम प्रोग्राम
ENGLISH MEDIUM 25 JUNE 1PM | हिन्दी माध्यम 28 जून 1PM

DELHI: • 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, Delhi | CONTACT: 8468022022, 9019066066
• GTB Nagar Enquiry and Classroom Centre, Above GTB Nagar Metro Station Gate No. 2, Delhi - 110009

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

मुंबई का मामला

नौ मुस्लिम छात्राओं ने दी थी कालेज के फैसले को कोर्ट में चुनौती, कालेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी, बैज पहनने पर लगाई गई है पाबंदी

कालेज के हिजाब बैन पर दखल देने से कोर्ट का इन्कार

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई के एक कालेज के अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। चेंबूर ट्रांबे एजुकेशन सोसायटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कालेज के एक ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश को चुनौती देते हुए नौ मुस्लिम छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में बांबे हाई कोर्ट का रुख किया। इसके तहत छात्र-छात्राएं कालेज परिसर के अंदर हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी और बैज नहीं पहन सकते।

जस्टिस एएस चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि वह कालेज के लिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जो विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष की छात्रा हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अल्ताफ खान ने कहा कि इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अलग रखें। चूंकि यह मामला सीनियर कालेज के छात्राओं का है, जहां यूनिफार्म नहीं होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रेस कोड एक वाट्सएप संदेश के जरिये सब पर थोपा गया है। इससे याचिकाकर्ताओं की चुनाव करने की आजादी, शारीरिक पवित्रता और स्वायत्तता को ठेस पहुंचती है।

- हाई कोर्ट ने कहा, कालेज के फैसले में हस्तक्षेप करने को नहीं है इच्छुक

बांबे हाई कोर्ट ने नहीं मानी याचिकाकर्ताओं की दलील।

वहीं कालेज प्रशासन का कहना है कि यह अनुशासनात्मक फैसला सभी जाति व धर्म के छात्र-छात्राओं के लिए है। यह फैसला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ऐसा निर्देश उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार के खिलाफ है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले कर्नाटक में भी इस तरह के प्रतिबंध के खिलाफ जोरदार आवाज उठी थी और मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था। लेकिन ड्रेस कोड को स्कूल का अनुशासन बताते हुए बरकरार रखा गया था।

****

1 घंटे के लिए अब प्रस्ताव में उच्च श्रेणी के समूह (पाश कालोनी) के लिए कार पार्किंग दरें 30 रुपये, एक से तीन घंटे के लिए 75 रुपये तथा तीन घंटे से अधिक समय के लिए 30 रुपये प्रति घंटा प्रस्तावित की हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 27 जून, 2024

आज का मौसम

बादल छाए रहेंगे। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
27 जून	37.0	27.0
28 जून	37.0	25.0
नोएडा		
27 जून	39.0	28.0
28 जून	36.0	26.0
गुरुग्राम		
27 जून	39.0	33.0
28 जून	40.0	33.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

दिल्ली में 16 वर्ष बाद महंगी होगी वाहनों की पार्किंग

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग दर महंगी होने वाली है। एमसीडी ने सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव व प्रदूषण का हवाला देते हुए पार्किंग शुल्क बढ़ाने के साथ अलग-अलग पार्किंग दरें लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत एमसीडी ने पाश कालोनियों (श्रेणी ए-डी) में स्थित पार्किंग स्थलों के लिए अलग शुल्क तथा समय स्लैब व दरों में भी बदलाव का प्रस्ताव किया है। विशेष बात कि सड़क पर पार्किंग को हतोत्साहित करने के लिए उसने बहुमंजिला पार्किंग स्थलों के 500 मीटर के दायरे में स्थित पार्किंग स्थलों में वाहन खड़ी करने पर तीन गुना पार्किंग शुल्क वसूलने की योजना बनाई है। (जासं)

हथियार तस्कर गिरफ्तार, 10 अवैध पिस्टल बरामद

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से प्वाइंट 32 बोर की 10 अवैध पिस्टल बरामद की गई हैं। उक्त हथियार मध्य प्रदेश के खरगोन से लाए गए थे जिनकी आपूर्ति दिल्ली-एनसीआर के बदमाशों को की जानी थी। 19 जून को सेल को सूचना मिली कि एक हथियार तस्कर डिलीवरी के लिए समालखा बस स्टैंड, द्वारका लिंक रोड के पास आएगा। वहां से सेल की टीम ने हनुमानगढ़, राजस्थान के रहने वाले एक हथियार तस्कर को पकड़ लिया।। (जासं)

जेएनयूएसयू ने प्रवेश प्रक्रिया पर विचार के लिए सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया जेएनयूईई से करने के लिए कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। जेएनयूएसयू ने कहा है कि जेएनयू प्रशासन ने पिछले साल पीएचडी प्रवेश के लिए जेएनयूईई को सीयूईटी से बदल दिया था और इस साल जेएनयूईई को वापस लाने के बजाय उन्होंने नेट परीक्षा के साथ जाने का फैसला किया। (जासं)

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से लंबित याचिका वापस ली

अनुरोध ▶ दिल्ली के सीएम ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के निर्णय को दी थी चुनौती

मुख्यमंत्री ने कहा- अब वह नई याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के 25 जून के आदेश को देंगे चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक के बाद एक कानूनी मुकदमों में फंसते जा रहे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमानत पर रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि 25 जून को हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में वह अपनी लंबित याचिका वापस लेना चाहते हैं और नई याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को समग्रता के साथ चुनौती देंगे। कोर्ट ने याचिका वापस लेने का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपित अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की निचली अदालत ने बीते 20 जून को मनी लांड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी थी। ईडी ने अगले ही दिन जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई से पहले ही 21 जून को जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी और बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने आनन फानन में हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रोक लगाने के 21 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया था और हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी थी। इस बीच 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की जमानत पर रोक की अर्जी पर अंतरिम आदेश सुनते हुए केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। बुधवार को केजरीवाल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष लगी थी। जैसे ही मामला सुनवाई पर आया, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में हर दिन डेवलपमेंट हो रहे हैं। केजरीवाल को अब सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। हाई कोर्ट ने 25 जून को फैसला सुना दिया, इसलिए कोर्ट उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे, वह नई याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के 25 जून के आदेश को समग्रता से चुनौती देंगे। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। ईडी ने आपत्ति नहीं जताई लेकिन ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी ने मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है और कोर्ट उसे रिकार्ड पर ले ले।

आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। वीडियोग्रैब/प्रेट्र

सीबीआइ की कार्रवाई अरविंद और आप को खत्म करने की साजिश

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

▶ सीबीआइ ने कोर्ट में जो बातें रखी हैं और जो दस्तावेज रखे, वे आपस में मेल नहीं खाते हैं : जस्मिन शाह

सीबीआइ द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप ने कहा है कि यह पूरा का पूरा मामला फर्जी है। सीबीआइ को इसकी दो साल की जांच में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला।

यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। आप ने सीबीआइ द्वारा केजरीवाल को लेकर कोर्ट में गलत दावा करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। आप ने कहा है कि सीबीआइ ने कोर्ट में झूठा दावा किया है।

आप के वरिष्ठ नेता जस्मिन शाह ने प्रेसवार्ता कर कहा कि भाजपा की सीबीआइ कोर्ट में झूठ बोलते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआइ ने कोर्ट में झूठा दावा किया कि सीएम केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डालकर केस से अपना पल्ला झाड़ लिया है। सीबीआइ के इस दावे का केजरीवाल ने तुरंत विरोध किया और जज से कहा कि सीबीआइ सरासर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ और ईडी ने भाजपा के इशारे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह फर्जी केस तैयार किया है।

पूरा तंत्र इस कोशिश में है केजरीवाल जेल से बाहर ना आएं : सुनीता केजरीवाल

सीबीआइ द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जिस पर तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआइ ने उन्हें आरोपित बना दिया और बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाएं। उन्होंने कहा कि ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।

रेड्डी का बयान विश्वास करने योग्य नहीं : सीएम

प्रथम पृष्ठ से आगे

केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सरकारी गवाह बने मगुंटा रेड्डी के बयानों पर भरोसा करना अनुचित है। उसका बेटा आरोपित था, वह सरकारी गवाह बन गया। चौधरी ने तर्क दिया कि मगुंटा रेड्डी 29 फरवरी 2024 को सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगियों में शामिल हो गए और उनके सभी पाप धुल गए। चौधरी ने जांच में सहयोग नहीं करने के सीबीआइ के दावे को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए एक अन्य अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि आबकारी नीति को हरी झंडी दिए जाने को लेकर वित्त, कानून व आबकारी विभाग से परामर्श किया गया था। कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसे उपराज्यपाल कार्यालय में भेजा गया। उन्होंने कुछ बदलाव सुझाए। बदलावों को कैबिनेट के सामने रखा गया, बदलावों को मंजूरी दी और फिर नीति बनाई गई।

सिसोदिया को नहीं ठहराया दोषी : केजरीवाल : सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया पर शराब की दुकानों के निजीकरण की सिफारिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कोर्ट को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हुए खंडन किया। कहा कि उन्होंने सिसोदिया को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। सीबीआइ सूत्रों द्वारा मीडिया में झूठी कहानी फैलाई जा रही है कि मैंने आबकारी नीति घोटाले का दोष सिसोदिया पर डाला है।

राजनीतिक नाटक को छोड़कर जल संकट दूर करे आप सरकार : भाजपा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर जल संकट से दिल्लीवासियों का ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट बना है, लेकिन सरकार के मंत्री झूठी बयानबाजी करने में व्यस्त हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल और जल संकट के लिए जिम्मेदार मंत्री आतिशी को योद्धा की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नरेला, बदरपुर, छतरपुर, नजफगढ़, कालकाजी, जंगपुरा, बब्बरपुर, बल्लीमारान सहित दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली के मंत्रियों का ध्यान इन क्षेत्रों में जल संकट दूर करने पर नहीं है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अनशन करने वाली जल मंत्री आतिशी अब अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सीपीआइ (एम) की नेता वृंदा करात के माध्यम से केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें दिल्ली सरकार से जल की उपलब्धता व वितरण से संबंधित आंकड़े मांगने चाहिए। आंकड़ों को देखकर उन्हें समझ आएगा कि जल वितरण के कुप्रबंधन, रिसाव और निजी टैंकरों से चोरी के कारण दिल्ली में जल संकट है।

वीरेंद्र सचदेवा। फाइल

देवेंद्र यादव। फाइल

नेतृत्वहीन आप सरकार की निष्क्रियता दिल्ली में जल संकट की बड़ी वजह : यादव : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में जल संकट की मुख्य वजह आप सरकार की निष्क्रियता, लापरवाही और भ्रष्टाचार है। पिछले 10 वर्षों के शासन में इस सरकार ने लगातार बढ़ती दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार पानी उत्पादन की क्षमता में एक एमजीडी पानी की बढ़ोतरी नही की। यादव ने बताया कि दिल्ली अपने पीने के पानी की 90 प्रतिशत जरूरत के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। इसके बावजूद जल बोर्ड ने गर्मियों से पानी की पर्याप्त जरूरत के लिए कोई योजना तैयार नही की।

यादव ने कहा कि जल बोर्ड दिल्ली के लिए उतना ही जल शोधन कर रहा है, जितना 10 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार के समय हो रहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में दो-तीन सप्ताह से बिल्कुल पानी नही आ रहा है, जबकि महरौली के असोला में पिछले तीन माह से जलापूर्ति नही हुई है। यादव ने कहा कि आप में व्याप्त भ्रष्टाचार के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, जबकि सांसद संजय सिंह और इनके कुछ सहयोगी जमानत पर हैं।

कांग्रेस की शिकायत पर हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी : सचदेवा

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा वर्ष 2022 में की गई शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी दिल्लीवासियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आबकारी घोटाले में उनके विरुद्ध जांच एजेंसियों को पास साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है।

सचदेवा ने कहा कि मनीष सिसोदिया को पहले ही सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है। केजरीवाल के विरुद्ध भी जांच चल रही है और पहले भी उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआइ कार्यालय बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मंगलवार से आप नेता कटाक्ष पूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका लोकतंत्र और न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। आप एवं विपक्ष के कुछ अन्य नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि केजरीवाल के विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। इन लोगों को यह समझना चाहिए कि आप सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

नई संहिता के तहत फोरेंसिक जांच की चुनौतियों से निपटने की तैयारी

विनीत त्रिपाठी • जागरण

▶ दिल्ली एफएसएल की कार्यप्रणाली का मुंबई सीआइडी आइजी व मुंबई एफएसएल ने लिया जायजा

नई दिल्ली: अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मौजूदा समय में फोरेंसिक साइंस लैब की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसे देखते हुए एक जुलाई से लागू होने वाली तीन नई आपराधिक संहिता में फोरेंसिक जांच को विशेष महत्व दिया गया है।

इसे लेकर दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैब न सिर्फ खुद को बल्कि अन्य राज्यों को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में मुंबई सीआइडी आइजी दिलीप पाटिल भुजबल व मुंबई एफएसएल की निदेशक डा. संगीता वी. घुमटकर ने दिल्ली एफएसएल की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे चलने वाले एफएसएल कंट्रोल रूम से लेकर साइबर व क्राइम सीन डिविजन के कार्य को करीब से जाना।

अपराध का बदलता पैटर्न व नई संहिता को देखते हुए अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आइसीजीएस) की शुरुआत की गई थी।

कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी देतीं दिल्ली एफएसएल निदेशक दीपा वर्मा (बाएं)। जागरण

दिल्ली एफएसएल पहुंचे मुंबई सीआइडी आइजी व एफएसएल अधिकारियों को दिल्ली एफएसएल निदेशक दीपा वर्मा ने प्रयोगशाला का दौरा कराया।

सपा अध्यक्ष अखिलेश ने अस्पताल पहुंच जाना आतिशी का हाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लोक नायक अस्पताल में दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी से मुलाकात की और कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्रियों की समस्याएं बढ़ गई हैं।

अखिलेश यादव ने कहा, मैं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आया था। वह न केवल बहादुर हैं, बल्कि लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यादव ने दावा किया कि सीबीआइ उन लोगों को फंसा रही है, जो भाजपा के लिए खतरा हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने भी आतिशी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की जनता के लिए बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। यह बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार और एलजी अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और दिल्ली की जनता के पानी के साथ भेदभाव की नीति अपना रहे हैं।

एम्स ने दुर्लभ ब्लड कैंसर से पीड़ित किसान की बचाई जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया से पीड़ित था मरीज, यह रक्त कैंसर का एक दुर्लभ और आक्रामक रूप है

दुर्लभ कैंसर की बीमारी से जूझ रहे अलीगढ़ के किसान की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जान बचाई है। 33 वर्षीय हरविंदर कुमार को एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया था। यह बीमारी रक्त कैंसर का एक दुर्लभ और आक्रामक रूप है। मरीज की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर एम्स प्रशासन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और उनका उपचार किया।

उपचार में शामिल एम्स के डाक्टरों ने बताया कि हरविंदर को 2019 में गंभीर हालत में एम्स में पहुंचाया गया था। वह पूरी तरह बेहोश थे और उनके हीमोग्लोबिन का स्तर चार ग्राम/डेसीलीटर था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनकी नाक से खून बह रहा था। हृदय गति रुक सकती थी। उनको फौरन खून चढ़ाए जाने की जरूरत थी। लेकिन, हरविंदर के पास उपचार के लिए न पैसे और न ही कोई ब्लड डोनर था। गंभीर वित्तीय बाधाओं के कारण स्वजन ने सारी आशा खो दी थी। तभी उनकी मुलाकात एम्स, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी विवेक कुमार सिंह से हुई। आपात स्थिति को भांपते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मेडिकल टीम और धर्मार्थ ट्रस्ट के समर्थन सहित एम्स में संयुक्त संसाधन जुटाए और हरविंदर के इलाज के लिए धन इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हरविंदर ने बताया कि वह अब सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। एम्स में किसी को नहीं जानते थे और फिर भी हर कोई मुझ जैसे गरीब मरीज की मदद के लिए आगे आया। इसके लिए एम्स का शुक्रिया। हेमेटोलाजी विभाग के डा. महापात्रा, डा. तुलिका सेठ, डा. मुकुल अग्रवाल, डा. तेजस्विनी और विवेक कुमार सिंह और अन्य ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया है। एम्स के निदेशक डा. एम श्रीनिवास ने कहा, हरविंदर कुमार की सफल रिकवरी मेडिकल स्टाफ की प्रतिबद्धता और क्षमता और एम्स में रोगी की देखभाल की ताकत का प्रमाण है।

बेटी के जन्म से नाखुश मां ने नहीं पिलाया दूध, मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : तीसरी बेटी होने से नाखुश एक महिला ने बेटी को अपना दूध नहीं पिलाया। तबीयत बिगड़ने पर भी उसे अस्पताल लेकर नहीं गई। इस कारण नवजात की मौत हो गई। नवजात के गर्दन पर भी निशान मिले हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में नवजात के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआइ भेजा गया है। इसमें मौत के कारण के बारे में पता चलेगा। पुलिस यह भी पता नहीं लगा पाई है कि महिला कौन है। बता दें कि आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।

थाने में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार मामला शिव दुर्गा विहार सेक्टर-39 की डिलीवरी हट का है। यहां 16 मई को महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। इससे महिला नाखुश थी। उसने नवजात को दूध नहीं पिलाया। यह देख वहां मौजूद नर्स ने उससे बार-बार दूध पिलाने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। दो दिन बाद बच्ची की मौत हो गई।

विलंबित ग्रीष्मकालीन कार्य योजना ने दिल्ली को प्रदूषण से जूझने पर किया मजबूर : सीआरईए

संजीव गुप्ता • जागरण

▶ कहा, मानसून की दस्तक से थोड़ा ही पहले यह प्लान लाने का कोई औचित्य नहीं, प्रविधानों पर की आपत्ति

नई दिल्ली : सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने दिल्ली सरकार के समर एक्शन प्लान पर सवाल उठाए हैं। सीआरईए के मुताबिक इस वर्ष दिल्ली की ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना के क्रियान्वयन में काफी देरी हुई, जो विशेष रूप से चिंताजनक है। कारण, वर्ष 2022 में यह कार्ययोजना 11 अप्रैल को जारी की गई थी जबकि वर्ष 2023 में एक मई से इस पर क्रियान्वयन शुरू हुआ था।

सीआरईए के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने देरी के लिए हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने को जिम्मेदार ठहराया है। गर्मियों के सीजन यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून के भी पूर्वार्द्ध में प्रदूषण के बढ़े स्तर से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा, अबकी बार दिल्ली वासियों को गर्मियों में भी खराब हवा में सांस लेने को बाध्य होना पड़ा। मई तो 2017 के बाद सात सालों का सर्वाधिक प्रदूषित माह बन गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) भी तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहे, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ गया। सीआरईए ने मौजूदा वर्ष के लिए दिल्ली की ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना की तुलना पिछले वर्ष की कार्य योजना से की है। इस तुलना के मुताबिक बिंदु पिछले साल वाले ही हैं। वहीं 2024 की ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना में रियल टाइम सोर्स अपार्शन्मेंट को छोड़ना प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले प्रयासों को कमजोर करता है, डेटा-संचालित नीति निर्णयों को बाधित करता है और प्रदूषण स्रोतों के लिए जवाबदेही कम करता है।

दिल्ली में सुबह प्रदूषण की स्थिति। फाइल

2024 की ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना आधी अधूरी है। यह वायु प्रदूषण के तात्कालिक कारणों का शमन करने के लिए, भविष्य के लिए नहीं। केवल धूल विरोधी अभियान सीधे वायु गुणवत्ता में सुधार को लक्षित करता है। बहुत से कार्य बिंदु जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित आवरण बढ़ाना और खुले में जलने से रोकना, पहले से ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अभिन्न अंग हैं और मौसमी क्रियान्वयन के लिए नई रणनीतियां नहीं, बल्कि चल रही प्रथाएं होनी चाहिए। पौधारोपण और नगर वनों के विकास जैसी पहल, पर्यावरण की दृष्टि से प्रभावी होते हुए भी तत्काल वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं लाती हैं। इसके चलते दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए।

– मनोज कुमार, विश्लेषक, सीआरईए

महत्वाकांक्षी लक्ष्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने को इस साल लगेंगे 4 .5 करोड़ पौधे

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थानों और विभिन्न विभागों को दिया लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस साल 4.5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। सीएक्यूएम ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थानों, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न निकायों को उनका लक्ष्य भी दे दिया है। इसमें दिल्ली के लिए 56,40,593, हरियाणा के लिए 1,32,50,000, राजस्थान के लिए 42,68,649 और उप्र के लिए 1,97,56,196 पौधारोपण का लक्ष्य शामिल है।

सीएक्यूएम ने बुधवार को एनसीआर में परिवहन विभाग की सभी एजेंसियों को सलाह दी है कि वे प्रमुख सड़कों के किनारे, सेंट्रल वर्ज के साथ-साथ, जहां तक संभव हो खुले क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने की कोशिश करें। इसके साथ शैक्षणिक संस्थानों, उच्च शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों से भी 2024-25 के दौरान 9,08,742 के संचयी पौधारोपण लक्ष्य के साथ अपने संबंधित परिसरों के भीतर और बाहर बड़े पैमाने पर हरियाली व पौधारोपण अभियान शुरू करने को कहा है।

हर साल बढ़ाया जा रहा लक्ष्य: इससे पहले साल 2021-22 के दौरान एनसीआर में केवल 28,81,145 नए पौधारोपण किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीआर में 3,11,97,899 नए पौधारोपण किए गए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूरे एनसीआर में राज्य सरकारों के लिए लगभग 3.85 करोड़ नए पौधारोपण का एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से लगभग 3.6 करोड़ पौधारोपण सफलतापूर्वक किया गया यानी 93.5 प्रतिशत सफलता हासिल की। इसमें उत्तर प्रदेश में 103.4 प्रतिशत सफलता हासिल की गई यानी लक्ष्य से अधिक पौधारोपण किया गया। दिल्ली में 84.6 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया, हरियाणा में यह 87.4 प्रतिशत रहा व राजस्थान ने 86 प्रतिशत तक लक्ष्य की पूर्ति की।

बड़े पैमाने पर पौधारोपण का लक्ष्य। फाइल

मियावाकी तकनीक पर फोकस

सीएक्यूएम ने बताया कि तमाम किस्म की विकास परियोजनाओं के चलते एनसीआर क्षेत्र में जगह की कमी रहती है। इसे देखते हुए शहरी वन क्षेत्र और सघन वन लगाने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस तरह से जितनी भी जगह मौजूद है, वहां पर अधिकाधिक हरियाली की जा सकेगी।

****

रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को लगाई फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों को काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में डीडीए द्वारा बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि छोटे अफसरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि डीडीए ने रिज क्षेत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दौरे को लेकर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस मामले में डीडीए द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। कोर्ट ने डीडीए से कहा आप एक सामान्य दस्तावेज को ढूंढ नहीं पाए। जिस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं, उस पर हमें संदेह है। हमने उस ईमेल के पहले भाग को देखा है, जिसमें उपराज्यपाल के दौरे की बात बताई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के निवासी बिंदु कपूरिया की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। यचिका में आरोप लगाए गए कि कोर्ट द्वारा अनुमति न मिलने के बाद भी पेड़ों को काटा गया। डीडीए की तरफ से वकील के रूप में पेश मनिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट को गलत जानकारी दी गई है।

मंत्री ने बिना अनुमति 1100 पेड़ काटने पर तलब किया रिकार्ड

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के आरक्षित वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट से बिना अनुमति लिए 1100 पेड़ों को काटने के मामले में आप सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। चोरी-छिपे काटे गए इन सैकड़ों पेड़ों की वजह से दिल्ली के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लिहाजा, पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे मामले में रिकार्ड तलब किया है।

उन्होंने अवैध रूप से पेड़ों को काटने के मामले में कार्रवाई की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। वन विभाग के अधिकारियों को यह जानकारी गुरुवार सुबह 11 बजे तक देने का निर्देश दिया है। एलजी ने कोर्ट को बताया कि दक्षिणी दिल्ली के आरक्षित वन क्षेत्र में 1100 पेड़ गैर कानूनी तरीके से काट दिए गए, जबकि पेड़ काटने से पहले अनुमति आवश्यक है।

18 वीं लोक सभा में तेलुगुदेसम पार्टी (तेदेपा) के 16 सांसद हैं, बुधवार को इन सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने कहा, उनकी सरकार भारत की प्रगति और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

विपक्ष ने पहली चर्चा में ही आक्रामक-मुखरता की खींच दी लकीर

राहुल गांधी ने स्पीकर को बधाई देने के दौरान कहा, विपक्ष भी देश के लोगों की आवाज

अखिलेश ने कहा, सदन उनके इशारे पर चले, किसी और के इशारे पर नहीं

संजय मिश्र ● जागरण

नई दिल्ली : प्रतिपक्ष के नए नेता राहुल गांधी के साथ विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं ने नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने के दौरान ही सदन में सरकार व प्रतिपक्ष के अधिकारों की सीमा रेखा खींचते हुए दो टूक संदेश दे दिया कि ताकतवर होकर उभरा विपक्ष नवगठित 18वीं लोकसभा में अपनी आवाज दबाने के किसी प्रयास को सहन नहीं करेगा। साथ ही मणिपुर हिंसा, किसानों की पीड़ा, नफरती हिंसा और पिछली लोकसभा में डेढ़ सौ सांसदों के निलंबन जैसे सत्ता को असहज करने वाले विषयों का जिक्र कर आइएनडीआइए ने साफ कर दिया कि गतिरोध के बहाने ज्वलंत सवालों को उठाने से रोकना संभव नहीं होगा।

लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में अपने पहले संबोधन में ही राहुल गांधी ने बिरला को बधाई देने के साथ कहा, यह सदन हिंदुस्तान के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के संरक्षक हैं। निस्संदेह सरकार के पास सत्ता की शक्ति है, पर विपक्ष भी देश के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस बार विपक्ष पिछली बार की तुलना में देश के लोगों की अधिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। विपक्ष आपके काम में मदद करना चाहेगा और हम चाहेंगे कि सदन अच्छी तरह से चले।

राहुल ने कहा,इसके लिए यह बहुत अहम है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो। विपक्ष को जनता की आवाज सदन में उठाने की अनुमति दी जाए और उन्हें विश्वास है कि स्पीकर हमें देश के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने देंगे। सदन कितनी कुशलता से चलता है, इससे ज्यादा अहम यह है कि सदन में देश की आवाज को सुनने की कितनी अनुमति दी जाती है। अतः सदन को कुशलतापूर्वक चलाने के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाना गैर-लोकतांत्रिक विचार है। राहुल ने कहा, इस चुनाव ने दिखाया है कि हिंदुस्तान के लोग विपक्ष से देश के संविधान की रक्षा की उम्मीद करते हैं। हमें यकीन है कि विपक्ष को बोलने का मौका देकर आप संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य निभाएंगे। काफी समय से पैंट-टी शर्ट में दिखने वाले राहुल लोकसभा में कुर्ता-पायजामे में नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिरला को बधाई देते हुए कहा, स्पीकर का आसन मुख्य न्यायाधीश की तरह है जिससे निष्पक्षता की उम्मीद है। कहा,उनका अंकुश विपक्ष पर तो रहा ही है, अब यह अंकुश सत्तापक्ष पर भी रहे। कहा, सदन स्पीकर के इशारे पर चलना चाहिए। इसका उलटा न हो। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी कहा, विपक्ष संख्या बल में इस बार ताकतवर है। द्रमुक के टीआर बालू ने आसन के निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा की। शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत ने पिछली लोस को संसदीय स्वर्णकाल बताने के सत्ता पक्ष के रुख पर पलटवार करते हुए कहा कि सांसदों को निलंबित-निष्कासित कर विधेयक पारित कराना कैसे गौरवपूर्ण है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, संसद की स्वतंत्रताव स्वायत्तता सुरक्षित रखना स्पीकर की जिम्मेदारी है न कि सत्तापक्ष का संरक्षण करना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा अब विपक्ष को कुचलकर आगे नहीं बढ़ सकती।

संसद में बुधवार को 18वीं लोस के पहले सत्र के दौरान बोलते राहुल गांधी। प्रेट्र

राष्ट्रपति आज संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को लोस व राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को बताने की उम्मीद है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मु का यह पहला संबोधन होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ था जबकि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद भवन के गजद्वार पर प्रधानमंत्री और लोकसभा व राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी राष्ट्रपति की अगुवानी करेंगे। यहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड सिंगोल के साथ लोकसभा में ले जाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना जरूरी है।

राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में मिली मान्यता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, कैबिनेट स्तर का प्रोटोकाल व सुविधाएं मिलेंगी
- राहुल ने खरगे का जताया आभार, कहा- संसद में उठाएंगे हर भारतीय की आवाज

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल की नई संवैधानिक भूमिका की अधिसूचना जारी कर दी। कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को विश्वास में लेने के बाद मंगलवार देर रात ही राहुल को नेता विपक्ष बनाए जाने की घोषणा की थी।

लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नौ जून से आधिकारिक रूप से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल को कैबिनेट स्तर के मंत्री का प्रोटोकाल व सुविधाएं मिलेंगी। गत 10 वर्षों में दो लोकसभा के कार्यकाल के दौरान सदन में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं था। उप्र के रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी को संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 की धारा-दो के तहत विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि इससे पहले ही लोस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सदन में राहुल ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का आगाज कर दिया जब वह ओम बिरला को पीएम मोदी के साथ आसन तक छोड़ने गए।

लोकसभा में नेता विपक्ष की अपनी नई भूमिका के लिए राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार जताया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'मैं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे व देशभर के सभी कांग्रेस नेताओं व 'बब्बर शेर' कार्यकर्ताओं को उनके भारी समर्थन व हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर संसद में हर भारतीय की आवाज उठाएंगे। अपने संविधान की रक्षा करेंगे और राजग सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे।'

पीएम की ओर से पेश प्रस्ताव पारित होने से बाकी अर्थहीन

प्रथम पृष्ठ से आगे

महताब ने एलान किया कि चूंकि स्पीकर के निर्वाचन का पीएम मोदी की ओर से पेश प्रस्ताव पारित हो गया है, इसलिए बाकी प्रस्ताव अर्थहीन हो गए हैं। भले ही वोटिंग की नौबत नहीं आई, मगर तकनीकी रूप से स्पीकर पद के लिए चुनावी मुकाबला हुआ। लोकसभा के अब तक के इतिहास में यह केवल चौथा मौका था, जब स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत आई। डिप्टी स्पीकर का पद देने का सरकार की ओर से भरोसा नहीं दिए जाने के मद्देनजर विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया।

बिरला के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले उन्हें बधाई दी और फिर परंपरा के अनुसार दोनों उन्हें साथ लेकर अध्यक्ष के आसन तक बिठाने ले गए। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू भी उनके साथ गए। लोस अध्यक्ष ने दूसरी बार उन्हें चुनने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा, सरकार व विपक्ष सबकी सहमति से सदन चले, गतिरोध न हो और परंपराएं कायम रहें, वह ये सुनिश्चित करेंगे। कहा, संसद के विरोध व सड़क के विरोध में अंतर है, जिसे समझा जाना चाहिए। बिरला ने कहा,स्पीकर जब बोलने के लिए खड़े हों, तो सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। बिरला के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का सदन से परिचय कराया।

अफजाल नहीं ले सके शपथ, बसपा ने अखिलेश को बताया जिम्मेदार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर

- गैंगस्टर एक्ट में मिली चार वर्ष की सजा मामले में तीन जुलाई को हाई कोर्ट में है सुनवाई

सपा सांसद अफजाल अंसारी मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। इसका कारण गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई है। हाई कोर्ट में मामले की तीन जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके बाद ही अफजाल के शपथ लेने की संभावना है। अफजाल गाजीपुर से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। वह मंगलवार को संसद भवन पहुंचे और अखिलेश यादव के पास बैठे थे। कुछ देर बाद वह संसद से बाहर चले गए।

अफजाल के शपथ नहीं लेने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने कारण स्पष्ट किया है। गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते वर्ष अफजाल को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। अफजाल ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट से फैसला आने तक अफजाल न तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और न ही किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई।

बसपा प्रत्याशी रहे डा. उमेश कुमार सिंह ने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले की जनता से धोखा किया है। वह जानते थे कि अफजाल को चार साल की सजा मिल चुकी है। इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया। संविधान बचाने के नाम पर संविधान से खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अफजाल ने संसद भवन में प्रवेश किया। इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

वहीं, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह ने कहा,अफजाल का शपथ न ले पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नवनिर्वाचित सांसद संसद भवन में बैठने के बाद भी शपथ नहीं ले सका। अफजाल को संसद में उपस्थित ही नहीं होना चाहिए था।

बिरला ने कांग्रेस को कठघरे में किया खड़ा

प्रथम पृष्ठ से आगे

आसन से स्पीकर के संबोधन में विपक्ष के उस रवैये का भी जवाब छुपा था, जिसमें लोकसभा चुनाव में संविधान के खतरे में होने के नारे लगाए जा रहे थे और सदन में भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने संविधान की प्रति के साथ लोकसभा सदस्य की शपथ लेते देखे गए थे।

विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद बिरला नहीं रुके। उन्होंने उस दौर में इंदिरा सरकार के कई निर्णयों को भी गलत ठहराया और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। बिरला के संबोधन में संविधान का उल्लेख भी कई बार आया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा ने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे संविधान की भावनाएं आहत हुईं। दावा किया कि संविधान में पांच-पांच संशोधन किए गए। मकसद एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियों को निहित करना था। इंदिरा गांधी नौकरशाही एवं न्यायपालिका को भी अपने प्रति उत्तरदायी बनाना चाहती थीं। मेंटेनेंस आफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) लगाकर इंदिरा गांधी ने सुनिश्चित किया कि मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को अदालतों से न्याय नहीं मिल पाए। एक्ट लाकर मीडिया को सच लिखने से रोका गया।

दरअसल बिरला का यह संबोधन एजेंडे में नहीं था। लिहाजा विपक्ष की ओर से कोई रणनीति तैयार नहीं थी। कांग्रेस की ओर से विरोध तो स्वाभाविक था लेकिन दूसरे सहयोगी दल असमंजस में दिखे। इसीलिए कभी-कभार दूसरे विपक्षी दलों के कुछ सदस्य भी खड़े हो जाते फिर बैठ जाते। संबोधन के अंत में स्पीकर ने सदस्यों से आपातकाल के दौरान जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखने का आग्रह किया। इस पर प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य खड़े हो गए। विपक्षी सहयोगी दल के कुछ सांसद भी खड़े दिखे हालांकि बाद में उनका कहना था कि वह तो सदन से बाहर जाने के लिए खड़े हुए थे।

आपातकाल की घटनाओं ने दिया तानाशाही का उदाहरण : मोदी

आपातकाल की बरसी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन में लाए गए निंदा प्रस्ताव की सराहना करते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास किया। बुधवार को अपने एक्स हैंडल से पीएम ने पोस्ट किया- 'मुझे खुशी है कि स्पीकर ने आपातकाल की कड़ी निंदा की। उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया, उसका भी उल्लेख किया। उस दौरान पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी अद्भुत भाव था।' पीएम ने कहा, आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, पर आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह इस बात का एक उपयुक्त उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनता की राय दबा दी जाती है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है।

लोकसभा उपाध्यक्ष पद की संवैधानिक व्यवस्था

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क : 18वीं लोकसभा के लिए बुधवार को अध्यक्ष (स्पीकर) का चुनाव विपक्ष की शुरुआती असहमति के बावजूद ध्वनिमत से हो गया। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। विपक्ष को इस पद के लिए सत्ता पक्ष के किसी उम्मीदवार के नाम पर विरोध नहीं था, पर वह आम सहमति के लिए यह आश्वस्ति जरूर चाहता था कि उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का पद उसे मिले। वैसे अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि उपाध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष अपने पास ही रखेगा या फिर विपक्ष को देगा।

विपक्ष का कहना है कि संसदीय परंपराओं के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता रहा है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कई बार उपाध्यक्ष का पद भी सत्ता पक्ष के पास रहा है। ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद किसे मिलना चाहिए। 16वीं लोकसभा (2014-19) में भाजपा नीत गठबंधन (राजग) के घटक दल अन्नाद्रमुक के एम थंबी दुरई उपाध्यक्ष थे, जबकि 17वीं लोकसभा (2019-24) में तो उपाध्यक्ष कोई था ही नहीं। संविधान का अनुच्छेद 95 (1) कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति या यह पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा अनुच्छेद 93 के मुताबिक, लोकसभा 'जल्द से जल्द' अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, पर इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। आमतौर पर अध्यक्ष का चुनाव नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण हो जाने के बाद अगले दिन हो जाता है। उपाध्यक्ष के लिए ऐसी कोई तय परंपरा या नियम नहीं है।

पुराना और नया संसद भवन। फाइल

अब तक के लोकसभा उपाध्यक्ष

लोकसभा उपाध्यक्ष	समय	पार्टी	लोकसभा में स्थिति
एम. अनंतशयनम अयंगर	1952-56	कांग्रेस	सत्ताधारी दल
हुकुम सिंह	1956-1957	कांग्रेस	सत्ताधारी दल
हुकुम सिंह	1957-1962	कांग्रेस	सत्ताधारी दल
एसवी कृष्णामूर्ति राव	1962-1967	कांग्रेस	सत्ताधारी दल
आरके खालिदकर	1967-69	कांग्रेस	सत्ताधारी दल
जीजी स्वैल	1969-1970	एपीएचएलसी	विपक्षी दल
जीजी स्वैल	1971-1977	एपीएचएलसी	विपक्षी दल
गोडे मुरहारी	1977-1979	कांग्रेस	विपक्षी दल
जी लक्ष्मणन	1980-1984	द्रमुक	सत्ताधारी दल
एम थंबी दुरई	1985-1989	अन्नाद्रमुक	सत्ताधारी दल
शिवराज वी पाटिल	1990-1991	कांग्रेस	विपक्षी दल
एस मल्लिकार्जुनैया	1991-1996	भाजपा	विपक्षी दल
सूरज भान	1996-1997	भाजपा	विपक्षी दल
पीएम सईद	1998-1999	कांग्रेस	विपक्षी दल
पीएम सईद	1999-2004	कांग्रेस	विपक्षी दल
चरणजीत सिंह अटवाल	2004-2009	शिअद	विपक्षी दल
करिया मुंडा	2009-2014	भाजपा	विपक्षी दल
एम थंबी दुरई	2014-2019	एआइएडीएमके	सत्ताधारी

एपीएचएलसी-आल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस

स्रोत-लोकसभा और भारतीय चुनाव आयोग

गांधी परिवार की सत्ता की भूख से सदन में डगमगाया आइएनडीआइए : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पात्रा ने आपातकाल पर स्पीकर के निंदा प्रस्ताव के दौरान विपक्षी दलों के रुख पर कसा तंज

आपातकाल को याद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव को लेकर जो माहौल बना, उसे आधार बनाकर भाजपा ने विपक्षी गठबंधन में दरारें देखने और दिखाने का प्रयास किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डा. संबित पात्रा ने दावा किया है कि निंदा प्रस्ताव और संवेदना के लिए रखे गए दो मिनट के मौन के दौरान कांग्रेस के सदस्य तो हंगामा कर रहे थे, जबकि आइएनडीआइए के घटक दल सपा, तृकां और द्रमुक सदस्य शांत थे। उन्होंने तंज कसा कि राहुल और गांधी परिवार की सत्ता की भूख से सदन में आइएनडीआइए डगमगा गया।

भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में डा. पात्रा ने कहा, 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट से सहमति लिए बगैर आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रपति से चुपचाप हस्ताक्षर कराने के बाद अगले दिन कैबिनेट को बताया था। उन्होंने कहा, इमरजेंसी के दौरान सिर्फ जनसंघ के नेता ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, देवीलाल, एम. करुणानिधि, एमके स्टालिन व शरद यादव सहित आज सदन में मौजूद रहे टीआर बालू भी जेल गए थे। डा. पात्रा ने कहा,' विडंबना देखिए कि निंदा प्रस्ताव जैसे ही बिरला ने रखा, वैसे ही कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। वेल की तरफ कांग्रेस के सांसद भागे पर सपा के लोग बैठे रहे। राहुल गांधी सोच रहे थे कि उठें या न उठें, शोर मचाएं या न मचाएं। वह अखिलेश यादव व टीआर बालू को देख रहे थे।' 'ऐसी परिस्थिति तभी होती है, जब आप अन्यायी होते हैं और न्यायवान दिखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ऐसा ही कर रही थी।' भाजपा सांसद ने कहा, जो कल संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ले रहे थे, वह आज असमंजस में थे। आपातकाल पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताने के लिए जब स्पीकर ने मौन के लिए कहा तो कांग्रेस के सदस्य वेल में हल्ला मचा रहे थे। सपा, टीएमसी और डीएमके सदस्य शांति से खड़े थे। उन्हें देखकर अंततोगत्वा राहुल गांधी को भी शांति से खड़ा होना पड़ा। उन्होंने कहा कि सत्ता की भूख में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और आज राहुल और गांधी परिवार की वही सत्ता की भूख आइएनडीआइए को डगमगा रही है।

डा. संबित पात्रा फाइल

जय फलस्तीन कहने पर खतरे में पड़ सकती है ओवैसी की संसद सदस्यता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- लोकसभा में शपथ ग्रहण के समय सांसद ने लगाया था नारा
- वरिष्ठ अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने की राष्ट्रपति से शिकायत

लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाने के कारण हैदराबाद के सांसद व आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रपति से करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

हरी शंकर जैन के पुत्र व अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, संविधान, संसद सदस्य को किसी अन्य देश के प्रति आस्था व्यक्त करने की इजाजत नहीं देता है। अनुच्छेद 102 के मुताबिक, अगर संसद सदस्य किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है, तो सदस्यता जा सकती है। ओवैसी ने फलस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की है। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति सुझाव के लिए चुनाव आयोग भेज सकती हैं। उनका जो निर्णय होगा, वह अंतिम होगा। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जब भारत के प्रति आस्था व्यक्त करने का वक्त आएगा तब ये सांसद भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। लेकिन फलस्तीन मामले में क्या इतना नहीं पता कि संसद का कोई निर्वाचित सदस्य किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा की घोषणा नहीं कर सकता। वैसे, संविधान विशेषज्ञों की अलग राय है। विशेषज्ञ एसके शर्मा के अनुसार, शपथ के दौरान वही बोलना होता है, जो लिखा होता है। आपातकाल के दौरान कुछ सदस्यों ने 42वें संशोधन को छोड़कर बाकी संविधान पर सच्ची निष्ठा व आस्था रखने की शपथ ली थी। मामला कोर्ट तक गया था, जिस पर कोर्ट ने तय शब्दों को ही संसद की कार्रवाई में रखने का आदेश दिया था। पीडीटी आचार्य कहते हैं कि यह मामला इस प्रकार का नहीं है, जिससे संसद सदस्यता गंवानी पड़े।

आपातकाल के दौरान पहचान छुपाकर संघर्ष करते रहे नरेन्द्र मोदी

- लोगों ने बताया, साधु, सरदार व आम आदमी के रूप में घूमते रहते थे मोदी
- आपातकाल के बाद 1978 में मोदी ने लिखी पुस्तक 'संघर्ष मा गुजरात'

नई दिल्ली, आइएएनएस : इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय नरेन्द्र मोदी महज 24 साल के थे। उन्होंने तब भी सरकार के इस दमनकारी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। वह लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों का हिस्सा रहे थे। उन्होंने आपातकाल की समाप्ति के बाद 1978 में अपनी पहली पुस्तक 'संघर्ष मा गुजरात' लिखी, जो गुजरात में आपातकाल के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में एक नेता के रूप में उनके अनुभवों का एक संस्मरण है। इस किताब को खूब सराहा गया।

गौरतलब है कि आपातकाल के दौरान नरेन्द्र मोदी तत्कालीन सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। स्वयंसेवकों और अन्य लोग आंदोलन के दौरान या तो जेल में डाल दिए गए थे या फिर सरकार से छुपते घूम रहे थे। मोदी ने उन सबको सहारा और ढाढस देने का भी काम किया था। वह उन परिवारों से मिलकर उनकी जरूरतें समझते, उनका कुशल क्षेम पूछते और हरसंभव मदद करते थे।

ऐसे ही कुछ लोगों ने उस आपातकाल के दौर को याद किया और बताया कि कैसे मोदी उस दौर में भी उनके साथ परिवार के एक सदस्य के रूप में तटस्थ होकर खड़े रहे। राजन दयाभाई भट्ट ने बताया, आपातकाल के दौरान मेरे पिताजी भूमिगत हो गए थे। मैं छोटा था और मेरी मां अकेली थी। इस दौरान नरेन्द्र मोदी हमारे घर आया करते थे। मां से मिलते और कहते थे कि किसी भी चीज को लेकर चिंता मत करो। अजीत सिंह भाई गढ़वी ने बताया कि इमरजेंसी के समय नरेन्द्र मोदी पूरे भारत में वेश बदलकर इधर-उधर जाया करते थे। नरेन्द्र मोदी पंजाब में सरदार बनकर गए थे।

देवगन भाई लखिया ने कहा कि आपातकाल के दौरान मोदी को एक आयोजक बनाया गया, जो सभी लोगों को नया फोन नंबर देते थे। उस समय गुजरात में पांच डिजिट का फोन नंबर होता था। ऐसे नरेन्द्र मोदी ने एक तरीका बताया कि आखिर के दो नंबर उसको उल्टा कर दो। जिसके जरिये सभी वर्कर एक दूसरे के संपर्क में आ गए। डा आर के शाह ने बताया कि इमरजेंसी के दौरान देश के सभी नेताओं के साथ चाहे विरोधी पार्टियों को नेता क्यों न हो, मोदी का उनके साथ लगातार संपर्क रहता था। यह सब वह अंडरग्राउंड होते हुए करते थे।

नाई की दुकान पर रखवाते थे साहित्य : हसमुख पटेल ने बताया कि आपातकाल के दौरान जो आंदोलन चल रहा था, उसमें नरेन्द्र भाई के पास जो साहित्य आता था उसको कहां रखना है किन लोगों को देना है इसके लिए मार्गदर्शन वही करते थे। वह बताते थे कि यह साहित्य नाई की दुकानों पर रखो जहां ज्यादातर सामान्य लोग आते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि भूमिगत होकर भी सभी तरह के साहित्य का प्रकाशन और वितरण नरेंद्र मोदी कराते थे और पूरे देश में उसे भेजने और उसका वितरण कराने की जिम्मेदारी भी उनके पास थी।

आपातकाल के दौरान नरेन्द्र मोदी को सरदार के सहित विभिन्न वेशभूषा अपनानी पड़ी थी। एक्स/@मोदीआर्काइव

आपातकाल में मोदी चला रहे थे आंदोलन

नागर भाई चावड़ा ने कहा कि जब आपातकाल लगा तो संघ को बैन कर दिया गया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। ऐसे में किसी को पता नहीं चल रहा था कि आंदोलन कौन चला रहा है। यह बाद में पता चला कि पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था वह एक ही व्यक्ति चला रहा था और वह थे नरेन्द्र भाई मोदी। प्रकाश मेहता ने कहा कि आंदोलन के दौरान नरेन्द्र मोदी उनके घर पर कई बार अलग-अलग वेश में आए। एक बार साधु बनकर आए, एक बार सामान्य नागरिक के वेश में आए, एक बार सरदार बनकर आए। उनका आइडिया था कि सरकार के खिलाफ गुजरात में जो साहित्य छपता था, उसे हम ट्रेन के जरिये अलग-अलग जगह भेजें। हम उसे ट्रेन में लोगों को दे आते थे और इस तरह हम देश के कोने-कोने में उसे पहुंचाते थे।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है राजस्थान में। बसपा यहां सभी सीटों चौरासी, खींवसर, दौसा, उनियारा-देवली और झुंझुनूं पर प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने यह जानकारी दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 27 जून, 2024

कर्नाटक में तीन और उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग पर हाईकमान करेगा फैसला : सिद्दरमैया

- सीएम सिद्दरमैया के करीबी नेताओं ने उठाया उपमुख्यमंत्री का मुद्दा
- उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार ने कहा, पार्टी इसका उचित जवाब देगी

सिद्दरमैया। फाइल

केएन राजन्ना। फाइल

बीजेड जमीर अहमद। फाइल

बेंगलुरु, प्रेट्र: कर्नाटक में तीन और उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक के कुछ मंत्री वीराशैवा-लिंगायत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। फिलहाल कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री के पद पर वोक्कालिगा समुदाय के डीके शिवकुमार हैं।

सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना, आवास मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली समेत कई अन्य नेताओं ने इस हफ्ते राज्य में तीन और उपमुख्यमंत्री बनाए जाने का मामला उठाया था। ये सभी नेता सिद्दरमैया के करीबी माने जाते हैं।

राज्य में कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि मंत्रियों का तीन नए उप मुख्यमंत्री की मांग करना सिद्दरमैया गुट की योजना का हिस्सा है, ताकि मौजूदा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को काबू में रखा जा सके और सरकार और पार्टी में उनके प्रभाव को कम किया जा सके। दरअसल पिछले साल मई में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के समय से ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। मई में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने दावेदारी पेश की थी। कांग्रेस ने सिद्दरमैया को मुख्यमंत्री पद देते हुए तय किया था कि डीके शिवकुमार राज्य के इकलौते उपमुख्यमंत्री रहेंगे। उधर, मंत्रियों की मांग पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए शिवकुमार ने कहा कि पार्टी उचित जवाब देगी। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में अधिक उपमुख्यमंत्री बनाने की कोई योजना है, उन्होंने कहा, ''आप मल्लिकार्जुन खरगे और हमारे प्रभारी महासचिव या मुख्यमंत्री से पूछें।''

लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा नेताओं की नाराजगी आ रही सामने

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद : लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री जवाहर चावड़ा का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, इसमें वह भाजपा के चुनाव निशान वाला पोस्टर हटाते नजर आ रहे हैं। उधर, कांग्रेस का एक खेमा पूर्व में साथ छोड़कर गए नेताओं की वापसी का विरोध करने लगा है। लोकसभा चुनाव के साथ गुजरात की पांच विधानसभा सीटों पर भी उप चुनाव हुए थे। माणावदर सीट पर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते अरविंद लाडाणी ने प्रदेश भाजपा आलाकमान को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री चावड़ा पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एवं पोरबंदर से सांसद मनसुख मांडविया ने कहा कि कुछ नेता अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। पार्टी ने उन्हें पहचान दी और पद दिया। इसी से उनकी पहचान है। इसी बयान से नाराज होकर जवाहर चावड़ा ने कहा कि उनकी पहचान स्वयं से है, भाजपा से नहीं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह भाजपा के चुनाव निशान वाला पोस्टर हटाते नजर आ रहे हैं।

ओडिशा में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की तैयारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

- मंत्री नित्यानंद गोंड ने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने के दिए संकेत

नित्यानंद गोंड। फाइल

ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की तरह शराबबंदी की चर्चा चल पड़ी है। हालांकि इस मुद्दे पर न तो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और न ही भाजपा सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) से ओडिशा में शराबबंदी लागू होगी। इसका राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने खंडन किया। अब राज्य के सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण मंत्री, नित्यानंद गोंड ने कहा है कि ओडिशा में शराब पर प्रतिबंध लगाने की राज्य की भाजपा सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि राजस्व नुकसान के डर से शराब की बिक्री को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

गोंड ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निषेध दिवस के अवसर पर बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शराब की लत के कारण समाज प्रदूषित हो रहा है। कई राज्यों में सरकारी स्तर पर शराब पर प्रतिबंध है। हमारी सरकार भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आबकारी व अन्य विभागों से इस संबंध में चर्चा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हम चरणबद्ध तरीके से ओडिशा को शराब मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वस्थ समाज बनाने के लिए आने वाले दिनों में नशे की खपत को कम करने के लिए भी कदम उठाएगी।

उल्लेखनीय है कि बिहार, गुजरात, मिजोरम और नगालैंड राज्य में शराब प्रतिबंधित है।

महाराष्ट्र में सीएम की चाय पार्टी का एमवीए ने किया बहिष्कार

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन ने विधानसभा के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। सरकार पर किसानों और आम जनता के मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। यह घोषणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार और गठबंधन सहयोगी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अंबादास दानवे ने की। मुंबई में 27 जून से 12 जुलाई तक आयोजित होने वाले सत्र के दौरान महायुति गठबंधन सरकार 28 जून को विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्य का बजट पेश करेगी। लोस चुनाव को देखते हुए अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था। वडेट्टीवार ने कहा कि विपक्षी दलों ने महायुति गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के विरोध में हाई-टी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया और परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के जरिये करदाताओं के पैसे की ठगी की है।

शिअद की लड़ाई हुई सार्वजनिक, बागियों को सुखबीर के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं

बागी नेता बोले, लोग मौजूदा लीडरशिप से नाराज हैं इसलिए एक खालीपन पैदा हो गया

इन्द्रप्रीत सिंह ● जागरण

- सरना बोले-चलती जंग में घोड़े नहीं बदले जाते हैं
- परमिंदर ढींडसा ने कहा- सुखबीर हमें अपनी केवल कर्मचारी ही मान रहे

परमजीत सिंह सरना। फाइल

परमिंदर सिंह ढींडसा। फाइल

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सुखबीर बादल की लीडरशिप से बगावत करने वाले नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि सुखबीर के प्रधान पद से इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा सहित कई नेताओं ने बुधवार को सुखबीर बादल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव और 2019 व 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल हार की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हैं।

परमिंदर ढींडसा ने जागरण से बातचीत में कहा कि हम तो एक जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर तनख्वाह लगवाएंगे ताकि मन से पिछली गलतियों को बोझ उतर जाए। उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों में हम शामिल नहीं थे लेकिन गलत फैसलों को लेकर खामोशी साधने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा लीडरशिप से नाराज हैं इसलिए एक खालीपन पैदा हो गया है जिसको रेडिकल फोर्स भर रही है। सुखबीर बादल को लग रहा है कि पार्टी केवल उनकी है और हम उनके कर्मचारी हैं।

दूसरी ओर सुखबीर बादल के समर्थकों ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने कहा है कि चलती जंग में कभी घोड़े नहीं बदले जाते, सुखबीर बादल ही हमारे जरनैल हैं और वह ही रहेंगे। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह ढींडसा, सिकंदर सिंह मलूका और प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा भाजपा के इशारे पर बगावती सुर अपनाए हुए हैं। भाजपा शिअद को तोड़ने का प्रयास कर रही है। चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन को लेकर जब बात हुई थी तभी भाजपा नेताओं साफ कर दिया था कि वे न तो बंदी सिखों के मामले में कोई फैसला लेंगे और न ही किसानों के बारे में। इस पर सुखबीर बादल ने इन्कार कर दिया। सरना ने कहा कि बात सीटों की नहीं है, पंथक मुद्दों की है। शिरोमणि अकाली दल ने अगर पंथक मुद्दों पर बात नहीं करनी है जिसके लिए शिअद का गठन हुआ है तो क्या करना है?

बगावत का असर : शिअद ने विस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी से भी खींचे हाथ : शिअद में चल रही बगावत का असर जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव पर भी पड़ने लगा है। पार्टी की ओर से सुरजीत कौर को प्रत्याशी बनाया गया था। अब नाम वापसी के अंतिम दिन देर शाम को शिअद ने उन्हें अपना पार्टी प्रत्याशी मानने से भी इनकार कर दिया है। जालंधर में पार्टी के शहरी प्रधान कुलवंत सिंह मन्नण ने कहा कि सुरजीत कौर को अकाली दल का कोई समर्थन नहीं है।

कैरों, मजीठिया की चुप्पी

अकाली दल में छिड़ी जंग के बीच सुखबीर बादल के दो नजदीकी रिश्तेदारों और सीनियर नेताओं आदेश प्रताप सिंह कैरों और बिक्रम सिंह मजीठिया की खामोशी भी दिलचस्पी पैदा कर रही है। ये दोनों नेता भी वैसे सुखबीर से नाराज माने जाते हैं। कैरों को तो संसदीय चुनाव के बीच ही पार्टी से निलंबित कर दिया था।

'भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में नहीं होगी सख्त कार्रवाई'

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार कहा कि नंदीग्राम थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 47 मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य से दर्ज एफआइआर की जांच की प्रगति पर रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी मंगलवार को होगी और राज्य को उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद नंदीग्राम थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुल 47 शिकायतें की गई जिसके आधार पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है, लेकिन भाजपा का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया गया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष व नंदीग्राम के भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने इस शिकायत के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुवेंदु के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि जानबूझकर इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज किए गए हैं। एक ही व्यक्ति ने 34 शिकायतें की है जिसके आधार पर एफआइआर भी दर्ज कर ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई साजिश है। उनकी गुजारिश है कि उन सभी एफआइआर की जांच सीबीआइ से कराई जाए।

मानहानि के मुकदमे में सांसद राहुल गांधी की सुलतानपुर में पेशी दो को

संवादसूत्र, जागरण, सुलतानपुर

राहुल गांधी।

रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे में पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र बुधवार को विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने निरस्त कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी तिथि दो जुलाई तय करते हुए सांसद को उपस्थित होने का आदेश दिया है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी बीती 20 फरवरी से जमानत पर हैं। कोर्ट ने अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इसमें कोतवाली नगर घरहाकलां डिहवा के रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र पिछली तारीख पर दिया था। इस पर उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बहस की। मजिस्ट्रेट ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। इसमें राहुल को जमानत मिल चुकी है। बुधवार को उनका बयान विशेष न्यायालय में दर्ज किए जाने के लिए तिथि नियत थी, लेकिन वह नहीं आए। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी प्रकरण में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज के भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को परिवाद दायर किया था। इससे पहले राहुल 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। तब उन्हें जमानत मिल गई थी।

कोरोना काल में कमल नाथ ने की थी 100 की अनुमति पर 2500 लोगों की चुनावी सभा

कमल नाथ।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन कर रोड शो और चुनावी सभाएं करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल नाथ के खिलाफ ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया है कि कमल नाथ ने ग्वालियर और दतिया सहित आसपास के कई क्षेत्रों में 100 लोगों की अनुमति पर दो से ढाई हजार लोगों के साथ चुनावी सभाएं की थीं।

प्रमोद कृष्णम का तंज-जो काम नेहरू, इंदिरा व राजीव नहीं कर पाए, वह राहुल ने किया

जागरण संवाददाता, अमरोहा

- कल्कि पीठाधीश्वर ने कहा- राहुल ने 15 वर्ष में कांग्रेस को किया बर्बाद
- संभल में आयोजित कल्कि धाम के कार्यक्रम में पीएम मोदी आए थे

प्रेस वार्ता करते कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। जागरण

कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 15 वर्ष में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। इस कार्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने पूरा नहीं किया, लेकिन अब राहुल ने पूरा कर दिया है। राहुल को विपक्ष का नेता चुने जाने की बधाई देता हूं। नई जिम्मेदारी मिली है, इसे बखूबी निभाएं, लेकिन संसद को सियासी अखाड़ा नहीं बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्रकारों से बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भाजपा अयोध्या नहीं, फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है। अयोध्या को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। मैंने अभी भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनकर आगे बढ़ रहा है।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के फिर अध्यक्ष बनाए गए पित्रोदा

सैम पित्रोदा। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को फिर से सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया है।पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के बाद कुछ सप्ताह पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। इन टिप्पणियों को भाजपा ने ''नस्लवादी'' करार दिया था। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले पित्रोदा ने आठ मई को पद से इस्तीफा दिया था।

'प्रतियोगी परीक्षाएं व सरकारी भर्ती बनी व्यवसाय'

जासं, प्रयागराज

राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ की बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। सौ.संगठन

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ की बैठक में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी भर्ती व्यवसाय बन चुकी है। यह हजारों करोड़ रुपये का कारोबार है। निरंतर गड़बड़ी चल रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है।

उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। नीट के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुप्पी साधकर बैठे हैं। 10 वर्ष में 41 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मोदी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कभी नहीं बोलते। उन्होंने बीते 10 वर्ष में सिर्फ झूठ बोला और नफरत फैलाई। प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अतीत को कुरेदते रहे। कांग्रेस को कोसने के सिवाए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस नेता ने एनडीए की केंद्र सरकार के भी शीघ्र गिर जाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि अब हालात कितने खराब है, इससे अनुमान लगाएं कि अयोध्या के राम मंदिर की छत भी लीक हो रही। आम जन को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को धरातल पर देखना होगा। जन आकांक्षाओं को समझना होगा। उसके अनुरूप ठोस कदम भी उठाने होंगे। आयोजन में शामिल पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एमएम पल्लम राजू ने कहा कि सीमा पर चीन हजारों वर्ग किलोमीटर देश की जमीन कब्जा कर चुका है, लेकिन सरकार को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है।

शपथ ग्रहण पर टकराव तेज, दो नवनिर्वाचित तृणमूल विधायकों ने विस परिसर में दिया धरना

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल में विवाद

- राज्यपाल के आमंत्रण के बावजूद शपथ लेने राजभवन नहीं पहुंचे दोनों विधायक
- विधानसभा में शपथ लेने पर अड़े, धरना देकर राज्यपाल का करते रहे इंतजार
- दिल्ली गए राज्यपाल, आज फिर धरने पर बैठेंगे दोनों विधायक

सीवी आनंद बोस। फाइल

रेयात हुसैन। फाइल

सायंतिका। फाइल

कई मुद्दों पर चल रहा है टकराव

ममता सरकार और राज्यपाल के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव चल रहा है। राजभवन की एक महिला कर्मी द्वारा राज्यपाल पर छेड़खानी का आरोप लगाने के बाद विवाद और बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्यपाल बैठक के लिए बुलाएंगे तब भी वह राजभवन नहीं जाएंगी।

बंगाल विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन और सत्तारूढ़ दल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। शपथ को लेकर गतिरोध के बीच तृणमूल के दोनों नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार ने बुधवार को बंगाल विधानसभा परिसर में चार घंटे तक धरना दिया। राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने दोनों को पहले ही पत्र व ईमेल भेजकर साफ कह दिया था कि उन्हें बुधवार दोपहर में राजभवन आकर ही शपथ ग्रहण करना होगा। पर विधानसभा में शपथ लेने को अडिग दोनों विधायक राज्यपाल के आमंत्रण के बावजूद राजभवन नहीं पहुंचे। दोनों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे विधानसभा में प्रतीक्षा करेंगे और शपथ के लिए राजभवन नहीं जाएंगे। दोनों ने राज्यपाल के विधानसभा आकर उन्हें पद की शपथ दिलाने या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी सौंपने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया। इसलिए दोनों दोपहर 12 बजे से विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए और राज्यपाल के इंतजार में शाम चार बजे तक धरना दिया। दोनों विधायक हाथों में तख्तियां भी लिए थे, जिसपर 'उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाए' जैसे नारे लिखे थे और राज्यपाल से शपथ का अनुरोध करते दिखे। सायंतिका कोलकाता के बरानगर और हुसैन मुर्शिदाबाद के भगवानगोला सीट से निर्वाचित हुए हैं। दूसरी ओर, दोपहर तक इंतजार के बाद दोनों विधायकों के राजभवन नहीं पहुंचने पर राज्यपाल बोस दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

विधायकों पर लगेगा जुर्माना : राजभवन सूत्रों ने कहा कि संविधान के तहत विधायकों के शपथ ग्रहण में अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है। राज्यपाल के निर्णय का अनुपालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है। संविधान के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति शपथ लिए बिना विधानसभा में आता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आज भी धरने पर बैठेंगे दोनों विधायक : इस बीच दोनों विधायकों ने कहा है कि जल्द शपथ दिलाने की मांग पर वे गुरुवार को फिर विधानसभा परिसर में आंबेडकर मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगे। सायंतिक ने कहा, 'जब तक हम शपथ नहीं ले लेते, हम विधायक के रूप में काम नहीं कर सकते।

विधानसभा अध्यक्ष बोले- यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति: वहीं, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह एक संवैधानिक शिष्टाचार है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल चाहें तो वह विस में आकर शपथ दिला सकते हैं।

यह है नियम : प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शपथ समारोह के प्रबंधन को लेकर संसदीय कार्य विभाग से राज्यपाल को लिखित पत्र भेजने की परंपरा है और उसके आधार पर राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार इस संबंध में निर्णय लेते हैं। परंतु इस मामले में संसदीय कार्य विभाग ने राजभवन को कोई पत्र नहीं भेजा । इसके बाद हालिया राजभवन और राज्य सचिवालय विवाद से नई जटिलताएं सामने आ गईं। संसदीय परंपरा के अनुसार, उपचुनाव के मामले में राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ममता सरकार से टकराव के कारण पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस व्यवस्था को बदल दिया था। स्पीकर के साथ मतभेद के कारण उन्होंने डिप्टी स्पीकर को यह जिम्मेदारी देकर एक असाधारण निर्णय लिया था। वहीं, राज्य सरकार ने इस बार अलग राह अपनाई। संसदीय कार्य विभाग की जगह विधानसभा सचिवालय ने शपथ के लिए राज्यपाल को पत्र भेजा, जिससे गतिरोध पैदा हुआ।

न्यायाधीश ने पूछा- राजभवन के सामने धरना पर पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई?

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजभवन के सामने तृणमूल कांग्रेस के धरने के मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। गुरुवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। दरअसल भाजपा ने राजभवन के सामने धरने की मंजूरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले साल पांच से 10 अक्टूबर तक तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी धारा 144 का उल्लंघन कर केंद्र के खिलाफ राजभवन के सामने धरने पर बैठे थे। पुलिस ने सत्ताधारी दल को इसकी मंजूरी दे दी थी लेकिन भाजपा मंजूरी नहीं मिली है। हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य के महाधिवक्ता (एजी) किशोर दत्ता से पूछा कि जब राजभवन के सामने तृणमूल का धरना हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि पुलिस कानून का पालन नहीं करेगी तो दूसरे कैसे मानेंगे?

जहां पिछड़ गई थी टीएमसी वहां अतिरिक्त ध्यान दें मंत्री : ममता

ममता बनर्जी। फाइल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : लोकसभा चुनाव के बाद बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों को उन क्षेत्रों में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया, जहां लोकसभा नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे या जहां सत्तारूढ़ पार्टी पिछड़ गई है। उन्होंने मंत्रियों को यह भी समझाया कि जिन क्षेत्रों में लोगों ने तृणमूल को वोट नहीं दिया, उन क्षेत्रों में क्या समस्या है देखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लोग जनसंपर्क पर ध्यान दें। बैठक में मुख्यमंत्री ने कूचबिहार में अच्छे नतीजे के लिए मंत्री उदयन गुहा की भी सराहना की। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि 517 नए पद सृजित किए जाएंगे। अन्य विभागों में भी रिक्तियां निकाली जाएंगी। इन पदों पर भर्ती की जाएगी।

****

15 करोड़ 93 लाख के नशीले पदार्थ भट्‌टी में जलाए पंचकूला और अंबाला पुलिस ने। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर पकड़े नशीले पदार्थों की खेप को किया नष्ट। चार जिलों की संयुक्त कमेटी की देखरेख में जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया।

नीट-यूजी पेपर लीक में दो आरोपितों को रिमांड पर लेगी सीबीआइ

चिंटू और मुकेश को तीन दिनों के रिमांड पर लेने की मिली अनुमति

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में बुधवार को सीबीआइ के आवेदन पर विशेष अदालत ने दो आरोपितों, बलदेव कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह और मुकेश कुमार को रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी। सीबीआइ अब रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपितों से पेपर लीक, साल्वर गैंग, अन्य आरोपितों और अभ्यर्थियों तक उनकी पहुंच के बारे में राज उगलवाएगी। सीबीआइ पेपर लीक के आरोपितों से बरामद मोबाइल फोन, लैपटाप समेत अन्य उपकरणों की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

तीन दिनों तक पूछताछ करेगी सीबीआइ : आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपितों चिंटू सिंह और मुकेश कुमार की रिमांड के लिए सीबीआइ ने मंगलवार को ही सीबीआइ की कोर्ट में आवेदन दिया था। जिस पर बुधवार को सुनवाई की गई। सीबीआइ के जज हर्षवर्द्धन सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चिंटू सिंह और मुकेश कुमार को तीन दिनों के लिए रिमांड पर देने का निर्णय सुनाया। चिंटू को झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। टैक्सी ड्राइवर मुकेश कुमार मुखिया संजीव सिंह का खास व्यक्ति है। मुकेश कुमार का काम उम्मीदवारों को लाने-ले जाने का था। ये दोनों आरोपित संजीव मुखिया के अहम लिंक हैं।

नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रेट्र

आरोपितों-अभ्यर्थियों के फोन लोकेशन का होगा मिलान : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईओयू के सुबूतों के आधार पर सीबीआइ नीट-यूजी के अभ्यर्थियों और आरोपितों के फोन लोकेशन की जांच कर रही है। आरोपितों और अभ्यर्थियों के बीच क्या बातचीत हुई, जांच एजेंसी इसकी तह में जाने की कोशिश में जुटी है। यह जानने की कोशिश भी की जा रही है कि पेपर लीक की घटना होने के छह महीने पहले तक आरोपितों की गतिविधियां क्या थीं। उनकी किनसे मुलाकात हुई और वे कहां-कहां गए, ये सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जो बिहार में गिरफ्तार किए गए हैं उनका राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तार आरोपितो से क्या संबंध है, इसकी भी जांच हो रही है। इस सारी कवायद का मकसद पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है।

सीबीआइ की तीन सदस्यीय टीम हजारीबाग पहुंची: दूसरी ओर नीट-यूजी पेपर लीक मामले में जांच के लिए सीबीआइ की तीन सदस्यीय टीम के बुधवार को हजारीबाग पहुंचने की सूचना है। सीबीआइ की टीम ने हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानउल हक से पूछताछ भी की है। सूत्रों ने बताया कि एहसानउल हक जांच एजेंसी के अधिकांश सवालों का जवाब न में दे रहे थे। इसके बाद जांच टीम उन्हें स्कूल परिसर में भी लेकर गई और वहीं उनसे देर शाम तक पूछताछ जारी थी।

कटा हुआ था प्रश्नपत्र का एक लिफाफा

प्रथम पृष्ठ से आगे

जांच में यह बात सामने आई है कि जिस लिफाफे से बुकलेट लीक होकर पटना पहुंचा था, वह नीचे से कट किया गया था और बाद में उसे चिपकाया गया था। बिहार से आई जांच टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। जांच में ट्रंक और बुकलेट के प्लास्टिक रैपर में छेड़छाड़ की बात सामने आने पर दो ट्रंक का पहले ही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई (ईओयू) जब्त कर पटना ले गई थी। टीम ने कुरियर कंपनी को भी रडार पर रखा है। हजारीबाग में कुरियर कंपनी का कार्यालय बंद है। टीम रांची जाकर पूछताछ करेगी।

शिवानी और नमन को गिरफ्तार करने भोपाल जाएगी एसटीएफ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले में दोनों वांछित
- गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगे गिरोह से जुड़े राज

उप्र लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक में शिवानी सिंह और नमन भ्रामरी सहित अन्य की भी तलाश तेज हो गई है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे में शिवानी व नमन को आरोपित बनाते हुए वांछित किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही भोपाल जाएगी। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर वांछित अभियुक्तों की घेरेबंदी करेगी। माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद राजीव नयन गिरोह से जुड़े अहम राज सामने आएंगे।

मेरठ जेल में बंद मेजा के राजीव नयन मिश्रा को एसटीएफ पेपर लीक का मास्टरमाइंड मानती है। उसकी खास मित्र शिवानी सिंह भोपाल के भरतनगर की है। एसटीएफ की गिरफ्त में आए प्रिंटिंग प्रेस कर्मी सुनील रघुवंशी और राजीव के सहयोगी सुभाष प्रकाश से पूछताछ में पता चला कि शिवानी सिंह परीक्षार्थियों से लिए गए पैसे का हिसाब-किताब रखती थी। शिवानी के विश्वासपात्र नमन भ्रामरी को विशाल दुबे वाट्सएप पर राजीव की तरह ही प्रश्नपत्र भेजता था। इसके बाद ज्यादा पैसा कमाने के लालच में राजीव ने अपने एजेंट मीरजापुर के डा. शरद पटेल, लखनऊ के अमित सिंह व सौरभ शुक्ला, प्रतापगढ़ के अरुण कुमार सिंह, मेजा के कामेश्वर मौर्या और करछना के पुष्कर को पेपर भेजकर परीक्षार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। भोपाल के आनंदनगर में होटल कोमल में आठ अभ्यर्थियों को बुलाकर प्रश्नपत्र के सवालों का जवाब रटवाया गया था। मास्टर माइंड व्हाट्सएप चैट पर लेन-देन की बातचीत के रिकार्ड भी मिले हैं।

केरल विस में परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र: केरल विधानसभा में बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं, नीट और नेट में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से प्रभावित उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की गई है। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ सहमत थे कि हाल में नीट, यूजीसी-नेट में अनियमितता की आई खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और उसकी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दोनों पक्षों का यह भी मानना था कि ऐसी घटनाएं इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। सदन में यह मुद्दा एलडीएफ विधायक एम विजिन ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया किया कि नीट में अनियमितता के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उधर, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली व तीन विधायकों सहित कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ कोटा पुलिस ने मंगलवार को राजकाज में बाधा डालने और शांति भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

बिहार में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या

जासं, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) : बिहार के मोतिहारी शहर में भाजपा नेता व जिला परिषद सदस्य 50 वर्षीय सुरेश यादव की बुधवार की शाम बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद करीब एक घंटे तक लोगों ने हंगामा कर सड़क जाम किया, पुलिस से धक्का-मुक्की की। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। सुरेश ईंट व्यवसाय से भी जुड़े थे। सुरेश भाजपा में किसी पद पर नहीं थे, किंतु पार्टी के सक्रिय नेता के रूप में जिले में उनकी खासी पहचान थी। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे का वीडियो फुटेज निकाला है। बताया गया कि सुरेश अपनी सोसाइटी के कार्यालय से निकलकर कहीं जाने के लिए मुख्य सड़क पारकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच हेलमेट पहने बाइक सवारों ने गोलियां मार दीं।

नीट परीक्षा में गड़बड़ी का असर...सीयूईटी यूजी का परिणाम आने में हो सकती है और देरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एनटीए ने 30 जून को परिणाम जारी करने की दी है समय सीमा
- लेकिन अब तक उत्तर कुंजी जारी नहीं किए जाने से बढ़ा संदेह

विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा सीयूईटी-यूजी का परिणाम आने में करीब दस से पंद्रह दिन का और समय लग सकता है। हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परिणाम को जारी करने की अनुमानित तारीख 30 जून दी है, लेकिन जिस तरह से अब तक परीक्षा कुंजी नहीं जारी की गई है, उससे साफ है कि इनका परिणाम आने में कम से कम दस दिन का और समय लगेगा। वैसे भी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद छात्रों को आपत्ति लेने और उसका निराकरण करने के लिए दस दिन का समय दिया जाता है।

एनटीए से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस बार सीयूईटी-यूजी की परीक्षा 29 मई को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि यह परिणाम 20 जून के आसपास आ जाएगा। एनटीए ने भी इसे 26 जून तक जारी करने के संकेत दिए थे। लेकिन, इस बीच चार जून को नीट-यूजी का परिणाम आने और उसमें मिली गड़बड़ियों व उसके बाद एक-एक कर कई परीक्षाओं के भी गड़बड़ी व पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद एनटीए की पूरी व्यवस्था ही पटरी से उतर गई है।

सूत्रों के मुताबिक, इस अव्यवस्था का असर सीयूईटी- यूजी के परिणाम को अंतिम रूप देने पर भी पड़ा है। जिसके चलते इसमें और भी जांच-परख बढ़ा दी गई है। इस बीच, यूजीसी का जोर इसके परिणाम को जल्द से जल्द जारी करने को लेकर है। यूजीसी का मानना है कि यदि इसका परिणाम आने में देरी होगी तो दाखिला भी देरी से होगा। इसके चलते विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाला नया सत्र प्रभावित होगा।

सीयूईटी के जरिये 261 विश्वविद्यालयों में इस बार मिलेगा प्रवेश

यूजीसी के अनुसार, सीयूईटी के जरिये इस बार देश के 261 विश्वविद्यालय अपने यहां स्नातक कोर्सों में प्रवेश देंगे। इन विश्वविद्यालयों ने इस बार अलग से कोई प्रवेश परीक्षा नहीं कराई है। इनमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। पिछली बार देश के करीब सौ विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी के जरिये अपने यहां स्नातक कोर्सों में दाखिला दिया था। छात्रों की सुविधा को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के सुझाव के बाद यूजीसी ने यह कदम उठाया है।

रामपुर में मदरसे के बच्चों ने क्षतिग्रस्त की कई देव मूर्तियां

जागरण संवाददाता, रामपुर : उत्तर प्रदेश में रामपुर के रामायण पार्क में स्थित हनुमानजी समेत कई देवों की मूर्तियों को मदरसे के बच्चों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर हिंदू-मुस्लिम आमने-सामने आ गए। पुलिस ने स्थिति संभाली। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर पार्क की सुरक्षा नहीं करने का आरोप लगाया है। रामायण पार्क में देवी-देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। आरोप है कि मदरसे के बच्चों ने पार्क में खेलते समय हनुमानजी और कई देवों की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ हिंदू युवा भी वहां खड़े थे। उन्होंने बच्चों को पार्क से भगा दिया। बच्चों ने घर जाकर पूरा मामला बताया तो उनके स्वजन एकत्र होकर पार्क में आ गए। उन्होंने हिंदू युवाओं से आपत्ति की। इसी बीच पुलिस और शहर विधायक आकाश सक्सेना भी आ गए। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया।

सरकारी मेडिकल कालेज में दाखिले के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- कोलकाता के एक कोचिंग सेंटर का मालिक है आरोपित
- आरोपित ने शिकायतकर्ता से 17 लाख रुपये की ठगी की

नीट अनियमितता के बीच सरकारी मेडिकल कालेज में दाखिले के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार रात कोलकाता के एक कोचिंग सेंटर के मालिक सौरीश घोष को गिरफ्तार किया है। आरोपित तथा उसके कुछ साथियों ने शिकायतकर्ता को उसकी बेटी को सरकारी मेडिकल कालेज में दाखिला दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे करीब 17 लाख रुपये की ठगी की थी। शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल करने के लिए आरोपित ने उन्हें कुछ फर्जी दस्तावेज भी भेजे थे।

दस्तावेज में दिखाया गया था कि शिकायतकर्ता की बेटी का नाम राज्य के एक सरकारी मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए सूचीबद्ध हो गया है। जांच करने पर शिकायतकर्ता को पता चला चला कि यह फर्जी दस्तावेज है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कोलकाता के शेक्सपियर सरणी थाने इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपित को पांच जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम आरोपित से पूछताछ कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वह किसी रैकेट में शामिल है या नहीं। मई में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) में अनियमितताओं के कई आरोप लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बंगाल पहले से ही शिक्षक भर्ती घोटाले जैसी कई तरह की गड़बड़ियों के लिए कुख्यात हो चुका है। ऐसे में अब मेडिकल कालेज में प्रवेश के नाम पर गड़बड़ी की बात सामने आ ने लगी है।

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का भी आयकर भर रही मध्य प्रदेश सरकार

धनंजय प्रताप सिंह ● नईदुनिया

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार पिछले तीस वर्षों से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भत्ते सहित परिलब्धियों पर जनता के पैसों से आयकर भर रही है। इस पर सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि मंत्रियों का कर सरकार नहीं भरेगी, लेकिन प्रदेश में अभी भी विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आयकर राज्य सरकार ही भर रही है। यही नहीं, इनको मिलने वाली अन्य सुविधाएं, जैसे उनको दिए गए आवास के किराए को भी आयकर छूट के दायरे में रखा गया है। इन्हें भी 1994 से ही आयकर नहीं देना पड़ रहा है। गौरतलब है कि डा. मोहन यादव सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर जमा नहीं करने की परंपरा को मंगलवार को समाप्त कर दिया लेकिन उस निर्णय में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं हैं क्योंकि इनके लिए अलग से मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया है।

मप्र विधानसभा। फाइल

इनके वेतन और भत्ते के लिए अलग से बना है अधिनियम

क्या है प्रविधान

मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन और भत्ते) अधिनियम 1972 की धारा 8 (क) में संशोधन करके प्रविधान किया गया कि मप्र विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाले भत्ते सहित परिलब्धियों पर आयकर नहीं लिया जाएगा।

विधेयक का नहीं किया विरोध : विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को यह छूट भी इन्हें 1997 में अध्यादेश के जरिए दी गई थी और बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन और भत्ते) अधिनियम 1972 की धारा 8 (क) में संशोधन करके इसे एक जनवरी 1994 की तिथि से लागू किया था। जब यह विधेयक विधानसभा में लाया गया था, तब भाजपा विपक्ष में थी, लेकिन किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया था। 2003 के बाद से सारे लाभ भाजपा सरकार के मंत्री, सीएम, विस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष पा रहे हैं।

श्रीनिवास तिवारी थे विधानसभा अध्यक्ष : विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को भत्ते व अन्य परिलब्धियों पर लगने वाला आयकर जब विधानसभा सचिवालय ने भरने का निर्णय लिया था, तब मप्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी थे व भेरूलाल पाटीदार उपाध्यक्ष थे। नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा थे। सभी ने इस पर सहमति जताई थी। यह बात भी चर्चा में आई थी कि विधायकों के लिए भी यह सुविधा लागू की जाए।

एसीबी की छापेमारी में डीएसपी के नाम करोड़ों की बेनामी संपत्ति निकली

जागरण संवाददाता, जम्मू : एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति बनाने वाले पुलिस के एक डीएसपी चंचल सिंह पर मामला दर्ज कर लिया है। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर एसीबी की विभिन्न टीमों ने एक साथ जम्मू संभाग के कठुआ, श्रीनगर व हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ठिकानों पर सात जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डीएसपी के पास जम्मू के विभिन्न जिलों में प्लाट, दुकानें व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। उसके हिमाचल के मनाली में दो होटल हैं। मनाली स्थित होटलों में छापेमारी के दौरान समझौता पत्र बरामद हुआ जो शिमला निवासी वेद प्रकाश और चंचल सिंह की पत्नी रेखा देवी के बीच हुआ था। चंचल की पत्नी ने मनाली के मोहल व फटी बुराऊ कोठी में 240 कनाल जमीन खरीदी थी। यह जमीन 2.85 करोड़ में खरीदी जिसमें से 25 लाख चेक से दिए।

संघ ने दिया सुझाव... बजट हो किसान, युवा, उद्योग और आमजन के लिए हितैषी

नेमिष हेमंत ● जागरण

- वित्त मंत्री के समक्ष आरएसएस के समवैचारिक संगठन रख रहे बजट संबंधित सुझाव व मांगपत्र
- जीएसटी व आयकर में राहत के साथ किसानों को सीधे आर्थिक लाभ व नौकरियां देने की मांग

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार राजग की सरकार बनने के बाद देशवासियों की निगाहें अगले माह पेश होने वाले आम बजट पर है। माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान विपक्षी दलों की ओर से जोरशोर से उठाए गए महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बजट में प्रमुखता से जगह मिल सकती है। साथ ही आधारभूत संरचनाओं पर जोर होने के साथ आयकर स्लैब के माध्यम से मध्यम वर्ग को राहत दी जा सकती है।

बजट को अंतिम रूप देने के क्रम में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण उद्योग, व्यापार व किसान संगठनों के साथ सामाजिक व आर्थिक सगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सुझाव ले रही हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सक्रिय है। उसका जोर है कि बजट में किसान, युवा, उद्योग व आम लोगों की जरूरतों और उम्मीदों को प्राथमिकता मिले। इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती व भारतीय किसान संघ समेत संघ के अन्य समवैचारिक संगठनों की ओर से वित्तमंत्री को पत्र के माध्यम से या मुलाकात में कई सुझाव दिए जा रहे हैं। लघु उद्योग भारती की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन में सरलीकरण और आयकर में सुधार की मांग प्रमुखता से की गई है, जो उद्योग जगत की प्रमुख चिंता है। संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, सभी राज्यों के उद्यमी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें जीएसटी के क्रियान्वयन के काफी कठिन होने का मुद्दा उठा था। इस कानून के प्रविधान ऐसे हैं, जिससे इंस्पेक्टरराज तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। आयकर स्लैब में राहत के साथ एक सुझाव आयकर को खत्म करने का भी गया है। कृषि शोध पर बढ़ावा देने, गो सेवा आधारित विश्वविद्यालय के लिए बजट आवंटन, सौर ऊर्जा में प्रोत्साहन समेत अन्य प्रविधान का सुझाव दिया गया है। स्वदेशी जागरण मंच ने रोबोट के आयात पर शुल्क लगाने तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पर जोर देने को कहा है। इसके पहले, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने वित्तमंत्री से मुलाकात कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने के साथ मनरेगा में 200 दिन रोजगार गारंटी की मांग की है।

बदलाव की कहानियां

पांच साल पहले दूध के लिए तरसते थे बच्चे, अब सबकुछ है

राधाकिशन शर्मा ● नईदुनिया

बिलासपुर: वर्ष 2018 में हुए विधानसभा और उसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के गांवों में ग्राउंड रिपोर्ट करने का अवसर मिला था। मल्हार में मां डिडिनेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यहां के ग्रामीणों से चुनावी चर्चा की। मल्हार से चिल्हाटी होते हुए लोहर्सी पहुंचा था। उस दौर में वहां के ग्रामीणों को दूध व दही लेने के लिए साढ़े तीन किलोमीटर दूर चिल्हाटी आना पड़ता था।

पांच साल बाद लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल के महीने में 30 तारीख को दोपहर करीब ढाई बजे पहुंचा। पांच साल पहले ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो कुछ देखा और अनुभव किया था, वही बातें मन में थी। गर्मी का दिन था लिहाजा पानी की बोतल भी रख ली थी। गांव के एंट्री पाइंट पर बड़ा सा गेट बन गया था। गांव में घुसते ही बस स्टैंड, स्टैंड के चारों तरफ पान व चाय की दुकान के अलावा होटल। होटल में लोगों की भीड़। भीड़ दिखी तो सोचा, यहीं से ग्राउंड रिपोर्ट का श्रीगणेश किया जाए। यह निर्णय काफी सार्थक रहा। बस स्टैंड में बिलासपुर के अलावा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण भी मिल गए। दो लोकसभा क्षेत्रों का चुनावी परिदृश्य सामने आ गया। आधे घंटे की चर्चा के बाद बस स्टैंड से गांव की ओर रुख किया। ग्रामीणों से चर्चा करते-करते गांव की गलियों की ओर निकल पड़ा। एक ऐसा बदलाव दिखा जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। सामने देखा और मन ही गिनती लगाई एक, दो और तीन। जी हां तीन मेडिकल स्टोर्स, डेली नीड्स की चार दुकानें। देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे मैं देख रहा था वह ज्वेलरी की दुकान थी। ग्लास का गेट, शो रूम की तरह सजी दुकानें। दुकान के भीतर एसी और दीवार पर बड़ा स्क्रीन वाला टीवी।

ग्राम लोहर्सी में संचालित केनरा बैंक की शाखा। नईदुनिया

तब मैंने लाल चाय पी थी... इस बार उसी गांव में काफी पीकर लौटा हूं

गांव की गलियों में मुझे रवि श्रीवास मिल गए। गांव का पढ़ा लिखा युवक। पेशे से एलआइसी एजेंट। दो घंटे साथ रहने से उनके साथ आत्मीय संबंध जो बन गया। उन्होंने घर चलने और चाय पीने की जिद पकड़ ली। उनके प्रस्ताव को मैं ठुकरा नहीं पाया और घर चलने की बात कह दी। जब रवि के घर के लिए हम लोग मुड़े सामने सरस्वती शिशु मंदिर का भवन और दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम दिखाई दिया। मेरी नजरों को पढ़ते हुए रवि बोले, तीन साल हो गया है सरस्वती शिशु मंदिर को चलते। बच्चों की अच्छी दर्ज संख्या है। रवि ने बताया अब तो गांव में कालेज भी खुल गया है। बात करते-करते घर पहुंच गए। 10 मिनट के भीतर दो कप काफी आ गया। काफी के कप को उत्सुकता के साथ देखा, रवि को समझते देर नहीं लगी। वे बोले आपका सोचना सही है, पांच साल पहले जब दूध की जरुरत पड़ती थी, तब साढ़े तीन किलोमीटर दूर चिल्हाटी जाना पड़ता था। उस समय तो ऐसी भी स्थिति बन जाती थी कि मेहमानों को लाल चाय पिलानी पड़ जाती थी। अब डेयरी में दूध मिल जाता है। उनकी बात सुनकर पांच साल पहले का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। तब मैं इसी गांव में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आया था और जगदीश के यहां लाल चाय पीकर आया था। काफी पीने के बाद उनसे विदा लिया और बिलासपुर के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते भर गांव में आए इस बदलाव को सोचते रहा। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी तो गांव में बैंक खुल गया। कपड़ा से लेकर डेयरी और ज्वेलर्स की दुकानें खुल गईं।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

गलत दावे के साथ नेहरू का वीडियो प्रसारित

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली : इंटरनेट मीडिया पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के इंटरव्यू का एक पुराना वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि वे आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे और उन्होंने इसका विरोध किया था।

पड़ताल: प्रसारित वीडियो क्लिप के की-फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें आरिजिनल वीडियो इंटरव्यू प्रसार भारती आर्काइव के यूट्यूब चैनल पर मिला, जो मई, 1964 में रिकार्ड किया गया इंटरव्यू है। नेहरू का यह इंटरव्यू अमेरिकी टीवी पत्रकार आर्नल्ड माइक ने लिया था। इस इंटरव्यू को सुनने पर पूरा संदर्भ स्पष्ट हो जाता है। माइक पूछते हैं, 'आप, गांधी और मिस्टर जिन्ना सभी ब्रिटिश राज से आजादी और विभाजन के पहले से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल थे?', जिसका जवाब देते हुए नेहरू कहते हैं, 'जिन्ना आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। वास्तव में उन्होंने इसका विरोध किया था।'

निष्कर्ष: आजादी की लड़ाई में भाग न लेने के दावे के साथ प्रसारित हो रहा नेहरू के इंटरव्यू का क्लिप एडिटेड और आल्टर्ड है। इंटरव्यू के दौरान नेहरू ने जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि, प्रसारित क्लिप में जिन्ना शब्द की जगह आइ यानी मैं को जोड़ दिया गया है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि नेहरू ने ऐसा अपने लिए कहा था।

क्या हो रहा है प्रसारित

इंटरनेट मीडिया यूजर साध्वी पूजा ठाकुर ने प्रसारित वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, दुर्लभ वीडियो, 'मैं आजादी की लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। बल्कि मैंने इसका विरोध किया था।' नेहरू जी। अन्य यूजर्स इस वीडियो को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर कर रहे हैं।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

****

18 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया छत्तीसगढ़ में, जिनमें पांच लाख का इनामी नक्सली हेमला बुधरा भी शामिल है। सुकमा जिले में बीते 23 जून को पुलिस वाहन को आइईडी विस्फोट से उड़ाने की घटना में शामिल छह नक्सलियों को बुधवार को गिरफ्तार भी किया गया।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 27 जून, 2024

उप्र के कई जिलों में तेज वर्षा, वज्रपात से 13 लोगों की मौत

उत्तराखंड व हरियाणा में रविवार को प्रवेश कर सकता है मानसून

हिमाचल में भी वर्षा का अलर्ट, हल्की हिमपात की भी संभावना

पंजाब में 28 से 30 जून तक तेज वर्षा के आसार, आरेंज अलर्ट

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। बुधवार को उप्र के कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सुलतानपुर, गोरखपुर, देवरिया व अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में झमाझम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार से शनिवार तक 18 जिलों में तेज वर्षा और 44 जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा व तेज हवा की चेतावनी जारी की है। इस बीच प्रदेश में वज्रपात से 13 लोगों की मौत हो गई। संभल में तीन, मीरजापुर, लखीमपुर व पीलीभीत में दो-दो, वाराणसी, चंदौली, मुरादाबाद व बहराइच में एक-एक व्यक्ति की मौत की सूचना है।

उधर, उत्तराखंड में देहरादून समेत चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व टिहरी के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा से तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार व शुक्रवार को राज्य में तेज वर्षा के आसार हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां रविवार को मानसून दस्तक दे सकता है। हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर के लिए 29 व 30 जून को भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने तीन जिलों हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा में भी 28 से 30 जून तक वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हिमपात होने की भी संभावना है। पंजाब में 28 से 30 जून तक तेज वर्षा के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में बुधवार को प्री-मानसून की वर्षा शुरू हुई। यहां रोहतक, हिसार जिलों में वर्षा हुई, बाकी हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ मौसम का मिजाज बदला। यहां 30 जून को मानसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

अयोध्या में बुधवार को वर्षा से जलमग्न हुई गली से गुजरते लोग। प्रेट्र

बिना पहचान वाले मानव सैंपल के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों पर परीक्षण या सर्जिकल प्रक्रिया के चलते बचे हुए और बिना पहचान वाले सैंपल का व्यावसायिक उद्देश्यों में इस्तेमाल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन सैंपल में मानव अंग, अंगों के हिस्से, कोशिकाएं, ऊतक, कोशिका उत्पाद जैसे कि रक्त, मूत्र, लार, डीएनए, आरएनए, बाल या अन्य कोशिकाएं आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में कहा है कि ये सैंपल किसी मरीज, पोस्टमार्टम, वेस्टेज, टिशू बैंक, आइवीएफ क्लीनिक और अंग दान केंद्र समेत अन्य के हो सकते हैं।

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बचे-खुचे, बिना पहचान वाले दिशानिर्देश के अनुसार, अस्पतालों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध सैंपल अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए कीमती संसाधन बन सकते हैं, जिनका बीमारी का निदान विकसित करने, इनोवेशन करने या किट का विकास करने, बीमारी के कारण का पता लगाने व अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सैंपल बिना पहचान वाले या बचे हुए जैविक नमूने हैं जो अनुसंधान उद्देश्यों के लिए नहीं रखे गए हैं और उपचार या देखभाल के बाद उन्हें नष्ट किया जाना होता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सतत खोज अब परिणाम की ओर...

भोजशाला ने दी 1700 से ज्यादा धरोहरों की अमूल्य पुरासंपदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार

- 22 मार्च से शुरू हुआ था एएसआइ सर्वे
- पहले छह सप्ताह की समय सीमा थी निर्धारित
- 29 अप्रैल को समय सीमा आठ सप्ताह बढ़ाई गई
- 27 जून को यह समय सीमा होगी पूर्ण
- दो जुलाई को हाई कोर्ट में प्रस्तुत होगी सर्वे रिपोर्ट
- चार जुलाई को कोर्ट में होनी है सुनवाई

देवी-देवताओं की मूर्तियां कह रहीं भोजशाला की कहानी

धार स्थित भोजशाला। नईदुनिया आर्काइव

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश से 22 मार्च से धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हो रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सर्वे का गुरुवार 27 जून अंतिम दिन है। एएसआइ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रो. आलोक त्रिपाठी की अगुआई में तीन माह से अनवरत चल रहे सर्वे में खोदाई के दौरान अब तक 1700 से ज्यादा धरोहरें मिली हैं। इनमें देवी-देवताओं की 37 मूर्तियां भी शामिल हैं। मां वाग्देवी की खंडित मूर्ति खास है, जो भोजशाला से लंदन ले जाई गई मूर्ति के समान ही बताई जा रही है। हालांकि, आकार में यह छोटी है। सर्वे के तहत की गई सफाई में भित्तिचित्र भी दिखाई दिए हैं।

भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि सर्वे में अब तक जो पुरावशेष मिले हैं, वे भोजशाला को मंदिर साबित कर रहे हैं। अब तक 37 मूर्तियां मिल चुकी हैं। इनमें भगवान श्रीकृष्ण, जटाधारी भोलेनाथ, हनुमान, शिव, ब्रह्मा, वाग्देवी, भगवान गणेश, माता पार्वती, भैरवनाथ आदि देवी-देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। भगवान गणेश की दो मूर्तियां हैं। भगवान भैरवनाथ सहित मयूर पंख वाले कृष्ण, हनुमानजी, ब्रह्माजी की परिवार सहित मूर्तियों के अलावा जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी हैं। द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति से लेकर अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। 1700 पुरा अवशेषों में स्तंभों व दीवार के 575 टुकड़े बड़े आकार के हैं।

सर्वे के 97वें दिन देवी की मूर्ति सहित आठ पुरावशेष मिले : भोजशाला में सर्वे के 97वें दिन बुधवार को एएसआइ की टीम को उत्तरी भाग में खोदाई के दौरान आठ पुरावशेष मिले। इनमें देवी की काले पाषाण की एक खंडित मूर्ति भी है। दो पुरावशेषों में भगवान नृसिंह की आकृति दिखाई दे रही है, जबकि शेष पांच पुरावशेष अस्पष्ट हैं। उनकी सफाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गोपाल शर्मा ने कहा कि भोजशाला को समय-समय पर तोड़फोड़ करके भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यह सर्वे से भी स्पष्ट हो गया है।

न्यूज गैलरी

भाग रहा दुष्कर्म का आरोपित पुलिस गोलीबारी में घायल

गुवाहाटी: असम के उदलगुरी जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मुख्य आरोपित उस समय पुलिस गोलीबारी में घायल हो गया जब वह मंगलवार को हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 22 जून को नाबालिग लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। (प्रेट्र)

पुणे में जीका वायरस के दो मामले मिले

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे में जीका संक्रमण के दो मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुणे के डाक्टर और उनकी बेटी की रिपोर्ट में जीका संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हाल ही में बुखार और जीका के अन्य लक्षण दिखने के बाद डाक्टर और उनके परिवार के सदस्यों के खून के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव है। (एएनआइ)

कामाख्या मंदिर के पट चार दिन के बाद फिर खुले

गुवाहाटी : कामाख्या मंदिर के दरवाजे बुधवार सुबह भक्तों के लिए फिर खोले गए। अंबुबाची मेले के अवसर पर मंदिर के दरवाजे प्रतीकात्मक तौर पर चार दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि के दौरान मां कामाख्या अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। अंबुबाची मेला 22 जून को शुरू हुआ था। (प्रेट्र)

शादी से मुकरने पर मंगेतर के घर पर की फायरिंग, गिरफ्तार

मलप्पुरम : केरल में एक व्यक्ति ने मंगेतर के कथित तौर पर शादी से इन्कार करने पर उसके घर पर एयर गन से गोलियां चला दीं। घटना मंगलवार रात कोट्टक्कल में हुई। आरोपित अबू ताहिर को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। (प्रेट्र)

असम पुलिस के छह कर्मियों को उम्रकैद की सजा

तिनसुकिया : असम के तिनसुकिया जिले की स्थानीय अदालत ने छह पुलिसकर्मियों को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में यह सजा सुनाई है। सात अक्टूबर 2013 को अंबिकापुर बाजार में अजीत सोनोवाल नाम के शख्स की पिटाई से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। (प्रेट्र)

नक्सल प्रभावित बीजापुर के पांच और स्कूलों में बजी घंटी

बीजापुर जिले के गांव कावड़गांव में जवानों की सुरक्षा में खुला प्राथमिक स्कूल। नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के भय से बंद किए गए स्कूलों को फिर खोलने की पिछले तीन वर्षों से चल रही प्रक्रिया के तहत चालू शिक्षा सत्र के पहले दिन बुधवार को जवानों की सुरक्षा में पांच और स्कूलों को खोला गया। जिले में 24 स्कूल को दोबारा खोलने की तैयारी है। अगले चार-पांच दिनों में अन्य स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। जिले में नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडूम के समय 2005 से 2011 के दौरान नक्सली हिंसा, तोड़फोड़ व भय से 300 सौ से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा था। पिछले तीन वर्षों में 220 स्कूल दोबारा खोले जा चुके हैं। इस साल 24 स्कूल खोलने के बाद भी लगभग 55 स्कूल जो बच जाएंगे, उन्हें आगामी शिक्षा सत्र में खोला जा सकता है। बता दें कि बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बल के नए कैंप खोलने और कैंप की पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों को नियद नेल्ला नार योजना (आपका अच्छा गांव) में शामिल कर विकास को गति देने के अंतर्गत इन स्कूलों को दोबारा खोलना संभव हो पाया है। स्कूल के लिए ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के सहयोग से अस्थायी शेड तो कहीं झोपड़ियां बनाई हैं। स्कूलों के संचालन के लिए गांव अथवा आसपास के क्षेत्र के 12वीं पास युवाओं को शिक्षा दूत नियुक्त किया गया है।

डोडा में मुठभेड़ में जैश के तीन पाकिस्तानी आतंकी ढेर

जागरण टीम, जम्मू

- 11 और 12 जून को छत्तरगला आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली
- मारे गए आतंकियों से दो एम-4 राइफलें, एक असाल्ट राइफल व गोला-बारूद बरामद

जम्मू संभाग के डोडा जिले में सुरक्षाबलों ने बुधवार को घने जंगल के बीच छह घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में तीन पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इनके पास से अमेरिका निर्मित दो एम-4 राइफलें, एक असाल्ट राइफल व भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला है। माना जा रहा है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुठभेड़ एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। मारे गए आतंकियों के साथियों के जंगल में छिपे होने की आशंका के मद्देनजर सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान सघन अभियान चला रहे हैं।

डोडा जिले में ही आतंकियों ने 11 और 12 जून को दो हमले किए थे। उन्होंने पहले छत्तरगला में सुरक्षाबलों की संयुक्त जांच चौकी और इसके अगले दिन गंदोह क्षेत्र के कोटा टाप में हमला किया। दोनों जगह हुई मुठभेड़ों में सुरक्षाबलों के पांच जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। दोनों मुठभेड़ों के बाद आतंकी भाग निकले थे। डोडा के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबल उसी दिन से अभियान चला रहे हैं। बुधवार सुबह गंदोह के सीनू गांव के पास छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान भद्रवाह स्थित सेना मुख्यालय से दो हेलीकाप्टरों से तीन-तीन बार जवानों को लाया गया। ड्रोन भी उड़ाए गए। कुछ ही देर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी मार गिराया। दोपहर बाद दो और आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ शाम को खत्म हो गई पर तलाशी अभियान जारी था।

ढलान पर ढोक में छिपे थे आतंकी : आतंकी ढलान पर एक ढोक (मिट्टी के घर) में छिपे थे। मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और पाकिस्तान से आए हैं।

जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपरेशन की निगरानी के लिए मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पठानकोट के गांव में दिखे दो संदिग्ध

पठानकोट जिले के गांव कोट भटिया में फार्म हाउस पर संदिग्ध देखे जाने के बाद जांच करते सेना, बीएसएफ के जवान व स्वैट कमांडो। जागरण

संवाद सहयोगी, जागरण • बमियाल (पठानकोट)

भारत-पाकिस्तान की अतंरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित पठानकोट जिले के गांव कोट भटिया में एक फार्म हाउस पर मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे दो संदिग्ध व्यक्ति देखे गए। हाई अलर्ट के बाद पुलिस लगभग 20 घंटे से संदिग्धों की तलाश में जुटी है। पुलिस, सेना व बीएसएफ के जवान बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी भी सीमावर्ती इलाके से ही आए थे। गांव कोट भटिया से एयरबेस की दूरी लगभग 50 किमी है। इससे सटे गुरदासपुर जिले के दीनानगर थाने पर भी 2015 में आतंकी हमला हुआ था। फार्म हाउस पर रहने वाले मजदूर महेश कुमार ने बताया कि मुंह पर कपड़ा बांधे व काले कपड़े पहने दो संदिग्ध व्यक्ति रात्रि लगभग 9:30 बजे पहुंचे और उससे खाना मांगा। उसके पास रात का बचा हुआ खाना था, जिसे संदिग्धों ने खाया और वहां से चले गए। जाते-जाते धमकी दी कि यदि उनके बारे में किसी को बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोनों संदिग्धों की आयु 25-26 वर्ष के आसपास थी। बुधवार शाम सात बजे तक सर्च अभियान जारी था। एसएसपी सोहेल मीर ने बताया कि सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है। भटिया के जिस फार्म हाउस पर मंगलवार रात्रि संदिग्ध देखे गए हैं, यह पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ कठुआ की सीमा से भी सटा हुआ है। 2010 में भी इसी फार्म हाउस पर संदिग्ध व्यक्ति देखे गए थे। इसके दो दिन बाद पुलिस से मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थे।

राजस्थान में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों से रैगिंग, सात छात्र निलंबित

संवाद सूत्र, जागरण, उदयपुर

- पहाड़ी पर बुलाकर जूनियर छात्रों से कराई गई उठक-बैठक
- एक छात्र की किडनी व लिवर प्रभावित
- प्रिंसिपल ने छात्रों पर दर्ज कराया केस

राजस्थान में डूंगरपुर जिला मेडिकल कालेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 50 से ज्यादा छात्रों के साथ रैगिंग की घटना सामने आई है। इस दौरान कई छात्रों की हालत बिगड़ गई। पहाड़ी पर बुलाकर उठक-बैठक कराने के दौरान एक छात्र की किडनी और लिवर दोनों प्रभावित हो गए। उसे गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती होकर डायलिसिस भी करानी पड़ी।

मामला सामने आने पर कालेज प्रशासन ने द्वितीय वर्ष के सात छात्रों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। रैगिंग की घटना डेढ़ महीने पहले की बताई जा रही है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भरी दोपहर कालेज के पास पहाड़ी पर बुलाया गया, जहां द्वितीय वर्ष के छात्रों ने उनकी रैगिंग की। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में उनसे उठक-बैठक कराई गई।

बताया जाता है कि जिस छात्र की किडनी और लिवर प्रभावित हुए, उससे तीन सौ से अधिक उठक-बैठक कराई गई थी। मामला सामने आने के बाद मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल एस. बाला मरगुनवेलू ने द्वितीय वर्ष के आरोपित छात्रों को निलंबित करने के साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

डर से सामने नहीं आ रहे हैं छात्र : रैगिंग की घटना के बाद डर के चलते जूनियर छात्रों ने कालेज आना बंद कर दिया। बताया गया कि 50 से अधिक छात्र होते हुए भी किसी ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई। घटना की जानकारी 20 जून को एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से प्रिंसिपल को मेल से दी गई। जांच के लिए प्रिंसिपल ने एक कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई। अब पुलिस छात्रों से पूछताछ में जुटी है।

अरुणाचल प्रदेश में स्कूल हास्टल में जूनियर छात्रों को लाठियों से पीटा, पांच निलंबित

ईटानगर, प्रेट्र: अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के एक हास्टल में आठवीं कक्षा के 15 छात्रों पर 11वीं कक्षा के कई छात्रों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्कूल के प्राचार्य राजीव रंजन ने बताया कि मंगलवार को हुई घटना में शामिल पांच छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है है। आरोप है कि बोरदुमसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के आठवीं कक्षा के छात्रों को छात्रावास में 11वीं कक्षा के कई छात्रों ने लाठियों से पीटा। घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

फाक्सकान प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरी देने से इन्कार पर रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के श्रम विभाग से फाक्सकान इंडिया एपल आइफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दिए जाने के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भर्ती करते समय पुरुष और महिला श्रमिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि इस अधिनियम के प्रविधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है।

समाचार एजेंसी रायटर ने मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि फाक्सकान ने चेन्नई के पास अपने आइफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरियों से व्यवस्थित रूप से बाहर रख रहा है। जबकि इस मामले को लेकर कंपनी का कहना है कि विवाहित महिलाओं के पास अविवाहित समकक्षों की तुलना में अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं।

महोबा में बैंक कर्मी काम करते समय अचेत, कुछ ही क्षण में मृत्यु

जागरण संवाददाता, महोबा

- काम करने के दौरान हार्टअटैक से हुई मौत का वीडियो आया सामने

राजेश कुमार शिंदे (फाइल फोटो)। स्वजन

19 जून को ड्यूटी के दौरान काम करते वक्त पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे प्रबंधक

ड्यूटी के दौरान बैंक कर्मी की हार्ट अटैक से मृत्यु होने का वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो गया। घटना 19 जून की है। किस तरह स्वस्थ व्यक्ति को पलक झपकते मौत ने अपनी आगोश में ले लिया, उसका वीडियो देख हर कोई स्तब्ध है।

उत्तर प्रदेश के महोबा में एचडीएफसी बैंक के कबरई शाखा में हमीरपुर के बिंवार गांव के राजेश कुमार शिंदे एग्री रीजनल मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। वह अपने लैपटाप पर काम कर रहे थे, उसी दौरान सुबह 11.45 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा। वह कुर्सी पर बैठे-बैठे बेसुध हो गए। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पांच मिनट, 25 सेकेंड के वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह बैंक में सब सामान्य तरीके से चल रहा था, अचानक राजेश की हालत बिगड़ने से माहौल बदल गया। राजेश के साथ बैठे अन्य कर्मचारियों ने उनकी हालत बिगड़ती देख पानी के छींटें मारे, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका शरीर धीरे-धीरे शिथिल पड़ गया। बैंक में उनके साथी उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजेश कुमार शिंदे ने दम तोड़ दिया।

हाइपरटोपिक कार्डियोमायोपैथी पीड़ितों की अचानक हो रही मृत्यु : लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डा. संतोष कुमार सिन्हा के मुताबिक मधुमेह, हाईपरटेंशन और धूमपान पहले से ही हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर थे। इसके अलावा हाइपरटोपिक कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें दिल की दीवार मोटी हो जाती है और पंपिंग कम होने से रक्त की आपूर्ति प्रभावित होती है और लोगों की जान चली जाती है।

बढ़ेगी सुरक्षा

ओईएफ ने बनाई देश की सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट

जैकेट भाभा कवच का उन्नत संस्करण, छह गोलियां लगने के बाद भी जवान को रखेगी सुरक्षित, केरल पुलिस को 170 बुलेटप्रूफ जैकेट सप्लाई की, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला पुलिस ने की मांग

जागरण संवाददाता, कानपुर

ओईएफ, फूलबाग में बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट की खासियत बताते (बीच में) जीएम डा. अनिल रंगा, (बाएं) अपर महाप्रबंधक आरके वर्मा और (दाएं) चंद्रशेखर। जागरण

देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को दुश्मनों की गोली से सुरक्षित रखने के लिए आयुध उपस्कर निर्माणी (ओईएफ), फूलबाग कानपुर में बनी लेवल पांच श्रेणी की बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट (बीआरजे) तैयार है। इसमें छह गोलियां लगने पर भी जान का खतरा नहीं सताएगा। केरल पुलिस के बाद महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला पुलिस व डीआरडीओ की शाखा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) ने बीआरजे की मांग की है। ओईएफ के जीएम डा. अनिल रंगा ने मंगलवार को निर्माणी के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में बीआरजे को देश की पहली सबसे हल्की जैकेट बनाने का दावा किया है।

जीएम ने बताया कि जैकेट को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गुजरात के विशेषज्ञों ने लेवल पांच के मानकों की कसौटी पर बेहतर पाया। केरल पुलिस के भी परीक्षण में पास होने पर 170 जैकेट की सप्लाई कर दी गई है। अब महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला पुलिस से 150 जैकेट और एचईएमआरएल से भी 25 जैकेट का आर्डर मिला है।

भाभा कवच से कम कीमत पर मिलेगी जैकेज : ओईएफ की ओर से पूर्व में बनाए गए भाभा कवच का वजन करीब 10 किग्रा था और कीमत भी 1.40 लाख रुपये थी। केरल पुलिस ने ओईएफ से बुलेटप्रूफ जैकेट की मांग की, जिस पर उन्हें भाभा कवच को दिखाया गया। केरल पुलिस के दिए डिजाइन के अनुसार दो माह में उन्नत संस्करण तैयार किया गया। महज 6.5 किग्रा वजन और 84 हजार रुपये की कीमत की बीआरजे को तैयार कर लिया। बीआरजे में नरम और कठोर आर्मर प्लेट लगी है, जो पुलिसकर्मी को एके 47 और नाइन एमएम पिस्टल से 10 मीटर की दूरी से चली गोली को बेअसर कर देगी।

निचली बर्थ पर सफर कर रहे शख्स पर गिरी सीट, मौत

- चेन ठीक से न लगे होने के कारण यात्रा के दौरान शख्स पर गिरी सीट
- गर्दन में गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था

हैदराबाद, प्रेट्र : ट्रेन में अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं तो मिडल बर्थ की चेन लगाने के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मामूली से लगने वाली यह बात जानलेवा तक साबित हो सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। केरल के 60 वर्षीय व्यक्ति पर यात्रा के दौरान ऊपर वाली सीट गिर गई, जिससे वह घायल हो गए। दरअसल, जिस कोच में वह यात्रा कर रहे थे उसकी ऊपरी बर्थ की सीट की चेन ठीक से नहीं लगाई गई थी। घटना 16 जून की है। उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

केरल के अली खान अपने दोस्त के साथ एर्नाकुलम-हजरत निजामुद्दीन मिलेनियम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच की निचली बर्थ पर आगरा की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन तेलंगाना के वारंगल से गुजर रही थी, तभी ऊपर वाली सीट अचानक गिर गई। इससे उनकी गर्दन में गंभीर चोट लग गई। उन्हें रामागुंडम के अस्पताल ले जाया गया। वहां से हैदराबाद के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 24 जून को उनकी मौत हो गई। मामला दर्ज किया कर लिया गया है।

रेल मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक्स पोस्ट में कहा है कि सीट क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं थी। सीट की जांच निजामुद्दीन स्टेशन पर की गई और वह ठीक पाई गई।

सेक्स स्कैंडल के आरोपित प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज

बेंगलुरु, प्रेट्र: बेंगलुरु की एक अदालत ने सेक्स स्कैंडल मामले के आरोपित जदएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश पारित किया। प्रज्वल फिलहाल एसआइटी की हिरासत में हैं। एसआइटी प्रज्वल पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। रेवन्ना को सोमवार को आठ जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था लेकिन एक दिन बाद ही कोर्ट ने उन्हें 29 जून तक एसआइटी की हिरासत में भेज दिया है। रेवन्ना ने होलेनरसिपुरा टाउन थाने में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में जमानत का अनुरोध किया था। इस मुकदमे में रेवन्ना पर 47 वर्षीय पूर्व घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

****

61 हो गई है तमिलनाडु के कल्लाकुरची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या। इस कारण राज्य में विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं।

जल स्रोतों की देशव्यापी दूसरी गणना में झरनों को भी किया जाएगा शामिल

जलशक्ति मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू की गणना प्रक्रिया, दो साल में आएगी रिपोर्ट

पिछली गणना में 40 हजार जलाशयों में मिला था अतिक्रमण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी तरह के जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले साल पहली गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिसके आधार पर यह पता चला था कि देश में नदियों, नहरों के साथ ही कितने तालाब, पोखर, झील आदि हैं।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार सभी जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट दो साल के भीतर आने की उम्मीद है। पिछली बार इसमें चार साल से अधिक का समय लगा था। इस बार की गणना में जल स्रोतों के रूप में झरनों को भी शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में राज्यों के साथ पहला मसौदा साझा किया गया है, जिसमें जल स्रोतों की गणना के तौर-तरीकों का विस्तृत लेखा-जोखा है। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, इस बार की गणना से जल संपदा की पूरी तस्वीर से वाकिफ हो सकेंगे। पिछली गणना का एक बड़ा निष्कर्ष अवैध कब्जे और अतिक्रमण के शिकार जल स्रोतों की संख्या सामने आना था।

जल स्रोतों की मिलेगी व्यापक तस्वीर।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 24,24,540 जलाशयों में से लगभग 40 हजार अतिक्रमण के शिकार हैं। शहरों में लगभग ढाई प्रतिशत जल स्रोतों अतिक्रमण से ग्रस्त हैं। तब केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया था कि वे जलाशयों पर अवैध कब्जे हटाने की पहल करें। अधिक चिंताजनक यह कि जो जल स्रोत अतिक्रमण के शिकार हैं, उनमें दो तिहाई से ज्यादा ऐसे हैं, जहां पूरी तरह अवैध कब्जा कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, जल स्रोतों की गणना का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डाटा बेस बनाना है, जिसमें जल स्रोतों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, इस्तेमाल, स्टोरेज की क्षमता, पानी की स्थिति जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके।

पुराने जल स्रोत फिर हो रहे जीवित : सीएसई

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सामने आया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित जलाशयों में बदलाव आ रहा है। प्रदूषित, अतिक्रमणग्रस्त या सूख चुके जलाशय सरकारी योजनाओं, निजी और सामुदायिक पहल की बदौलत पुनर्जीवित हो रहे हैं।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों को 'बैक फ्राम द ब्रिंक : रिजुवेनेटिंग इंडियाज लेक्स, पोंड्स एंड टैंक्स - ए कम्पेंडियम आफ सक्सेस स्टोरीज' नामक पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसे बुधवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में राष्ट्रीय संगोष्ठी में जारी किया गया। इस दौरान सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, 'हमें जल निकायों, झीलों, टैंकों और पोखरों की कला को फिर से सीखने की जरूरत है। हमें स्थानीय जल प्रणालियों में निवेश करने के लिए अपने काम को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वर्षा की हर बूंद को एकत्र किया जा सके।' मालूम हो कि सीएसई की टीम ने एक वर्ष की अवधि में भारत के चार अलग-अलग पारिस्थितिक क्षेत्रों में 22 राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और पांच केंद्रीय योजनाओं के तहत बनाए गए या बहाल किए गए 250 जलाशयों की समीक्षा की है।

बंगाल में शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर सीबीआइ का छापा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ ने बुधवार को कोलकाता से सटे साल्टलेक स्थित शिक्षा विभाग के मुख्यालय बिकास भवन में छापेमारी की। जांच अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के सील किए गए गोदाम में तलाशी अभियान चलाया।

▸ **जांचकर्ताओं ने सील गोदाम की तलाशी ली**

सीबीआइ का अभियान शुरू होने पर पुलिस भी बिकास भवन पहुंची। उन्होंने सीबीआइ अधिकारियों से बात की। शिक्षा विभाग के विभिन्न दस्तावेज को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदाम को 23 दिसंबर, 2022 को सीबीआइ ने सील कर दिया था। इससे पहले गत चार जनवरी को सीबीआइ के जांचकर्ताओं ने बिकास भवन में राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन से पूछताछ की थी और कुछ जरूरी दस्तावेज भी जुटाए थे।

सीबीआइ ने नवंबर 2023 में भी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में बिकास भवन में तलाशी अभियान चलाया था। जांचकर्ताओं ने कंप्यूटर और विभिन्न दस्तावेज की जांच की थी। विदित हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती को रद कर दिया था।

नकली करेंसी के साथ नेशनल खिलाड़ी समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

▸ एटीएस-एसओजी ने मुजफ्फरनगर में पकड़ा, दो साथी फरार
▸ एक आरोपित सहारनपुर निवासी, 77 हजार के नकली नोट बरामद

एटीएस और एसओजी की टीम ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके दो साथी फरार हैं। पकड़े गए आरोपितों में एक नेशनल एथलीट रह चुका है और दूसरा सहारनपुर का है।

मुजफ्फरनगर के एसपी (सिटी) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मंगलवार को फुलेंद्र उर्फ कोच और सद्दाम निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपित बाइक पर सवार थे। इनके कब्जे से पांच-पांच सौ रुपये के 155 जाली नोट (77,500 रुपये), दो मोबाइल फोन, एक पैनकार्ड, एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और तीन एटीएम कार्ड बरामद हुए। इनके दो साथी सलीम और मुजम्मिल फरार हैं। आठ सौ मीटर दौड़ में फुलेंद्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वह चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को निश्शुल्क कोचिंग भी देता था, लेकिन स्टेडियम में उसका रिकार्ड नहीं है। ये लोगों को रुपये दोगुना करने का लालच देते थे। उसको पहले पचास और एक सौ के असली नोट पर बड़ी सफाई से ओवर राइटिंग कर देते थे। अगर किसी नोट पर लिखे नंबर के अंत में तीन होता था तो उसे आठ कर देते थे और उसे मार्केट में चलाने के लिए भेज देते थे। विश्वास जमने पर उसे नकली करेंसी देकर भाग जाते थे और मोबाइल से उसका नंबर भी डिलीट कर देते थे, ताकि पकड़े न जाएं। आरोपितों के मोबाइल से ज्यादा डिटेल नहीं मिली है। जिला क्रीड़ा अधिकारी लक्ष्यराज त्यागी का कहना है कि फुलेंद्र उर्फ कोच चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में अधिकृत कोच नहीं है और न कभी इस पद पर रहा है।

नकली नोटो के साथ पकड़े गए आरोपितो के बारे में मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में जानकारी देते एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत। जागरण

न्यूज गैलरी

मणिपुर में मादक पदार्थों की तस्करी में आई है कमी : मुख्यमंत्री

इंफाल : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि लोगों के सहयोग से मणिपुर में मादक पदार्थों की तस्करी में कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में पोस्ते की खेती में भी 50-60 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने ड्रग्स के खतरे को खत्म करने का आह्वान किया। (प्रेट्र)

असम में 4.5 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, एक गिरफ्तार

गुवाहाटी : असम के कछार जिले में बुधवार को 4.5 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की गई। एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, स्पेशल टास्क फोर्स असम और कछार पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत सिलचर में एक वाहन को रोककर 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की 900 ग्राम हेरोइन बरामद की। विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने पड़ोसी राज्य मिजोरम से आ रहे वाहन को सिलचर में रोका। तलाशी के दौरान हेरोइन मिली, जिसे जब्त किया गया इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। (प्रेट्र)

छत्रपति संभाजीनगर में तेंदुए के हमले में किशोर की मौत

छत्रपति संभाजीनगर : महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में तेंदुए के हमले में एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार रात कन्नड़ पुलिस थाना क्षेत्र के भंबरवाड़ी गांव में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, किशोर गांव के आश्रम में रहता था और किसी को छोड़ने के लिए बाहर गया था। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला किया और उसे 150 फीट तक घसीटा। बुधवार सुबह लड़के की तलाश शुरू की गई और बाद में शव मिला। (प्रेट्र)

पालतू कुत्ते के काटने से एक सप्ताह में पिता-पुत्र की मौत

विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में एक सप्ताह के अंदर पिता- पुत्र की रेबीज से मौत हो गई। दोनों को पालतू कुत्ते ने करीब एक सप्ताह पहले काटा था। भार्गव की मंगलवार को रेबीज से मौत हुई, जबकि चार दिन पहले उनके पिता नरसिंग राव की भी अस्पताल में रेबीज से मौत हुई थी। कुत्ते की मृत्यु हो गई। राव और उनके बेटे के रेबीजरोधी टीका लेने तक रेबीज के लक्षण विकसित हो गए थे। (आइएएनएस)

दुश्मन की पकड़ में आसानी से न आने वाला राकेट नौसेना को मिला

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी के माइक्रोवेव आब्स्क्यूरेंट चैफ राकेट (एमआर-एमओसीआर) सौंपा है। यह आसानी से दुश्मन की रडार में नहीं आता। इसमें उपयोग की गई विशेष तकनीक इसके चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को अस्पष्ट कर देती है। इसे डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस मध्यम दूरी के चैफ राकेट में कुछ माइक्रोन व्यास वाले विशेष प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। जब इसे दागा जाता है तो पर्याप्त समय और क्षेत्र में यह माइक्रोवेव आब्सक्योर क्लाउड का निर्माण करता है। इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले उपकरणों से बचने के लिए एक कवच का काम करता है।

एमआर-एमओसीआर के पहले चरण के परीक्षणों को भारतीय नौसेना के जहाजों से सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। दूसरे चरण के परीक्षणों के बाद नौसेना की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई। योग्यता को पूरा करने वाले सभी एमआर-एमओसीआर को सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमआर-एमओसीआर के सफल विकास पर डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की सराहना की है। उन्होंने इस तकनीक को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बताया।

▸ **यह माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को अस्पष्ट कर देता है**
▸ **इसे डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया है**

नई दिल्ली में बुधवार को नौसेना को एमआर-एमओसी राकेट सौंपे जाने के निमित्त आयोजित कार्यक्रम। एएनआइ

प्रयागराज में मालगाड़ी डिरेल, दिल्ली-हावड़ा रूट सवा चार घंटे बाधित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▸ **गाजियाबाद से पीडीडीयू जा रही मालगाड़ी के तीन वैगन हुए बेपटरी**
▸ **सवा तीन घंटे तक डाउन और सवा चार घंटे तक ठप रही अप रेल लाइन**

देश के सबसे व्यस्ततम दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार को अपराह्न 3.07 बजे बड़ा हादसा हो गया। गाजियाबाद से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर जा रही खाली मालगाड़ी प्रयागराज जंक्शन से आगे बढ़ते ही निरंजन पुल पर डिरेल हो गई। मालगाड़ी के तीन वैगन (कुल 16 पहिए) पटरी से नीचे उतर गए। दिल्ली-हावड़ा डाउन लाइन पर हुई इस दुर्घटना के बाद अप लाइन पर भी वैगन के चले जाने से दिल्ली-हावड़ा रूट पर संचालन पूरी तरह ठप हो गया। गैस कटर से कोचों को काटकर अलग किया गया और लगभग सवा तीन घंटे बाद डाउन लाइन व सवा चार घंटे बाद अप लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। डाउन लाइन पर सबसे पहले 12308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस को दुर्घटना स्थल से सुरक्षित गुजारा गया। रेलवे की ओर से एक जांच टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की जांच करेगी।

एक खाली मालगाड़ी गाजियाबाद से पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर जा रही थी। प्रयागराज जंक्शन के यार्ड में ही ट्रेन के मध्य में रहे तीन वैगन तेज आवाज के साथ पटरी से नीचे उतर गए। स्पीड बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन तेज झटके के कारण वैगन अप लाइन तक तिरछे होकर पहुंच गए। इस दौरान किसी अन्य ट्रेन का अप लाइन पर संचालन नहीं हो रहा था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारित होने के बाद जहां-तहां ट्रेनों को रोक दिया गया। घटनास्थल पर छह लाइनें गुजरती हैं। इसमें दिल्ली-हावड़ा रूट अप-डाउन पूरी तरह से बाधित रहा, जबकि प्रयागराज-वाराणसी रेल मार्ग, प्रयागराज से वाया प्रयाग लखनऊ व प्रतापगढ़ मार्ग पर भी डेढ़ घंटे तक ट्रेनों का संचालन रुका रहा। मौके पर तकनीकी टीम व रेलवे अधिकारी पहुंचे तो री-रेलमेंट शुरू हुआ। शाम पौने पांच बजे गैस कटर से पटरी से उतरे वैगनों को काटकर अलग किया गया। एक हिस्से को छिवकी की ओर व दूसरे हिस्से को प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ाया गया। वहीं, शाम लगभग पांच बजे गोरखपुर वंदे भारत को मध्य लाइन को खाली कराकर जंक्शन पर भेजा गया। जबकि घटनास्थल से पहले आउटर पर रुकी ट्रेनों से उतरकर लोग पैदल ही घर जाने लगे। शाम सवा 6.20 बजे 12308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस को डाउन लाइन से गुजराने के बाद इस ट्रैक को चालू कर दिया गया। जबकि इसके साथ ही वाराणसी, लखनऊ व प्रतापगढ़ रूट पर भी ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है। शाम 7:20 बजे बाद अप लाइन भी शुरू हुई।

निरंजन डाट पुल के समीप रेलवे ट्रैक से उतरी मालगाड़ी। जागरण

> अभी सुपरवाइजर लेवल का ज्वाइंट नोट बनाया जा रहा है। एक जांच टीम पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल द्रुत गति से रेलवे ट्रैक को बहाल किया गया। **-हिमांशु शेखर उपाध्याय, सीपीआरओ, उमरे**

तेजस से टकराया गोवंशी, तीन घंटे प्रभावित रहा रेल यातायात

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और हिरनगांव रेलवे स्टेशन के बीच बुधवार सुबह तेजस एक्सप्रेस से गोवंशी टकराने के बाद रेल यातायात तीन घंटे तक प्रभावित रहा। घटना में ओवर हेड इलेक्ट्रिक वायर (ओएचई) टूटने से वंदे भारत समेत एक दर्जन ट्रेनें पीछे रोकी गईं। इसी दौरान सिग्नल फेल होने से भी कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ओएचई को एक घंटे में ठीक करा यातायात शुरू करा दिया गया था।

बिहार में पकड़े गए साइबर अपराधी पाकिस्तान के लिए कर रहे थे काम

जागरण संवाददाता, कटिहार

▸ **पटना से हुई थी दोनों की गिरफ्तारी, भोले-भाले लोगों को झांसे में ले उनके बैंक खातों का करते थे उपयोग**

बिहार साइबर पुलिस ने पटना के एक होटल से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम नेस्ताक आलम व उसकी महिला मित्र ईशा कुमारी है। ये दोनों पाकिस्तान में बैठे साइबर अपराधियों के लिए काम करते थे और भोले-भाले लोगों से बैंक खाते खुलवाकर अपने पास रख लेते थे। इस एवज में उन्हें 15 से 20 हजार रुपये देते थे। इन बैंक खातों के नंबर पाकिस्तान में बैठे अपने आका को वाट्सएप से भेज देते थे। पाकिस्तान से आडियो-वीडियो चैटिंग के माध्यम से साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी करते थे और रुपये अपने एजेंट के दिए बैंक खातों में मंगा लेते थे। इन दोनों का काम खातों से रुपये निकालकर पाकिस्तान भेजना होता था। बदले में इन्हें 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था।

आरोपित नेस्ताक छठी कक्षा तक पढ़ा है, जबकि उसकी महिला मित्र बीकाम पास है। इन दोनों ने अब तक बैंक खातों के माध्यम से पांच करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन पाकिस्तान के विभिन्न बैंकों में किया है। साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी सद्दाम हुसैन का कहना है कि गिरफ्तार दोनों साइबर अपराधियों के तार पाकिस्तान के साइबर अपराधियों से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब तक की जांच में आतंकी फंडिंग से संबंधित किसी तरह का साक्ष्य नहीं मिला है। आशंका को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

सिंचाई विभाग के इंजीनियर से 8.24 लाख ठगे : साइबर अपराधियों ने एक इंजीनियर संदीप कुमार को पार्ट टाइम काम कर रुपये कमाने का झांसा देकर आठ लाख 24 हजार दो सौ रुपये की ठगी कर ली है। मामले में इंजीनियर ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

शिक्षक से 15 लाख की ठगी : साइबर अपराधियों ने बेतिया शहर निवासी प्रशांत कुमार से आनलाइन 15 लाख रुपये की ठगी कर ली है। प्रशांत कुमार पेशे से शिक्षक हैं। प्रशांत को रुपये दोगुना करने का झांसा देकर ठगी की गई। ठगों को रुपये देने के लिए प्रशांत ने बैंक से 10 लाख का पर्सनल लोन और दोस्तों से कर्ज भी लिया। उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनके फोन नंबर को एक वाट्सएप ग्रुप पर एक नामी कंपनी के प्रोडक्ट को लाइक करके स्क्रीनशाट को टेलीग्राम के एक आइडी पर भेजने के बदले 150 रुपये देने को कहा गया। ऐसा करते ही शिक्षक के खाते में 150 रुपये आ गए। शिक्षक को झांसा देकर ठगों ने कई बार में 15 लाख 30 हजार 33 रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

शराब त्रासदी पर चर्चा की मांग कर रहे विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित

चेन्नई, प्रेट्र : कल्लाकुरची शराब त्रासदी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे तमिलनाडु में विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी सहित अन्नाद्रमुक विधायकों को बुधवार को विधानसभा के पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया।

काली शर्ट पहनकर विधानसभा आए विपक्षी दल के सदस्यों ने कल्लाकुरची शराब त्रासदी मामले पर चर्चा के लिए स्थगन की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने कहा कि वह इस मामले पर फैसला करेंगे, हालांकि अन्नाद्रमुक विधायकों ने इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने पर जोर दिया और विरोध करते रहे। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष ने अन्नाद्रमुक विधायकों को निलंबित कर दिया। कल्लाकुरची जिले में पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने के बाद से 59 लोगों की मौत हो चुकी है। कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने शराब त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन से मुलाकात की।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वाद दायर, नहीं हो सकी सुनवाई

जागरण संवाददाता, मथुरा

▸ **ईदगाह कमेटी और जन्मस्थान के समझौते को अवैध बताते हुए दायर किया वाद**
▸ **मैनपुरी के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के वाद पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई**

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच पुराने समझौते को लेकर मैनपुरी के अधिवक्ता के एक वाद पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की गई है।

मैनपुरी निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पिछले दिनों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डा. गौरव उत्सव राज के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच 10 बिंदुओं पर हुआ समझौता अवैध है। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है। इसलिए समझौता राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन इसे स्थानीय स्तर पर किया गया।

उनकी मांग है कि समझौते में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजेएम उपस्थित नहीं थे। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी।

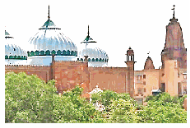
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह। फाइल

हालांकि, समझौता करने वाले ईदगाह पक्ष के चार और सेवा संघ के दो लोगों में सभी की मृत्यु हो चुकी है। उधर, जन्मस्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए 20 वाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें से भी एक वाद अजय प्रताप ने दायर किया था।

जागरण विशेष

उद्यम-उपक्रम को वरदान, बीएयू के हौसले से स्टार्टअप भरेंगे उड़ान

स्टार्टअप को तराश कर उन्हें छोटे-बड़े उद्योग का रूप देगा बीएयू, बनाया पूर्वी जोन का प्रामिनेंट एग्रीकल्चर इनक्यूबेशन सेंटर

ललन तिवारी • जागरण

भागलपुर: अंग्रेजों के जमाने से ही किसानों को सबल बना रहा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर (तब बिहार कृषि महाविद्यालय, स्थापित वर्ष 1928) ने नवाचारों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। उद्यम-उपक्रम के लिए वरदान बनते हुए यह अब चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के स्टार्टअप को तराश कर उन्हें छोटे-बड़े उद्योग का रूप देगा। केंद्र सरकार ने बीएयू में कार्य कर रहे सब एग्रीस को पूर्वी जोन का प्रामिनेंट एग्रीकल्चर इनक्यूबेशन सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फलक पर इसकी खास पहचान होगी। यहां उद्यम सोच के विद्यार्थियों के लिए नई स्कीम भी लांच की गई है। इसके तहत जिन छात्र-छात्राओं में स्टार्टअप की सोच उभरी है, उनके स्टार्टअप को इनक्यूबेट कर चार लाख रुपये शुरुआती अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले यहां ट्रेंड नवाचारों को पांच से 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देकर नए-नए उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं।

पूर्वी जोन पर खास फोकस: केंद्र की योजना के तहत यहां चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के ऐसे व्यक्ति या संगठन, जिनके पास नवाचार का गुणवत्तापूर्ण स्टार्टअप हो, उनका चयन किया जाएगा। इसके बाद बेहतर प्रशिक्षण देकर उनमें उद्यमी बनने का सर्वांगीण गुण विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उनके स्टार्टअप में विशेषज्ञों की राय को समाहित कर छोटे-बड़े उद्योग का रूप दिया जाएगा। मानक पर खरे उतरने वाले ऐसे स्टार्टअप को केंद्र सरकार से बतौर अनुदान 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। जब तक उद्योग सही तरीके से विकसित नहीं हो जाए, तब तक इनक्यूबेशन सेंटर के विशेषज्ञ इसकी निगरानी करेंगे।

देश-राज्य की समृद्धि में दे रहा योगदान: इस केंद्र में अलग-अलग कार्य क्षेत्र में अब तक 97 स्टार्टअप इनक्यूबेट (ट्रेंड) किए गए हैं। इनमें 51 को 6.3 करोड़ रुपिये का अनुदान मिला है। इससे इनका उद्यम रफ्तार पकड़ चुका है। सभी 51 स्टार्टअप ने इस जोन में तकरीबन 15 हजार से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया है। इनमें तकनीक, यांत्रिकी, केमिकल फर्टिलाइजर, लेबर कास्ट रिड्यूस, वेस्ट यूज करके खेती की लागत में कमी, किसानों के उत्पाद को वैल्यू एडिशन किया गया, जिससे किसानों को अपने उत्पाद का अधिक आय प्राप्त हुआ है।

पांच विजन पर काम करता है इनक्यूबेशन सेंटर: संस्थान के अनुसंधान निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का इनक्यूबेशन सेंटर बनाने की पहल आरंभ कर दी गई है। कई संस्थाओं से एमओयू के लिए बात चल रही है। संस्थाओं के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेक्निकल लैब की स्थापना की जा रही है। सब एग्रीस के प्रबंधक अशोक जायसवाल ने बताया कि केंद्र के पांच स्तंभ हैं, जो पांच एफ से जुड़े हैं। फूड, कैटल फीड, फैब्रिक (कपड़ा), फ्यूल (ऊर्जा), फैकेड (घर)। यूं कहें कि रोटी, कपड़ा, मकान, ऊर्जा व पशु चारा इनक्यूबेटर सेंटर के पांच विजन है।

बिहार सरकार भी दे रही 10 लाख का ब्याजमुक्त कर्ज

पीआरओ डा. राजेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार से चार अक्टूबर, 2023 को बीएयू का एक एमओयू हुआ है। इसमें बिहार में रहने वालों के लिए एग्रीकल्चर के अतिरिक्त विभिन्न कार्य क्षेत्र में स्टार्टअप को ट्रेंड किया जाएगा। अब तक इसमें 34 स्टार्टअप इंडोर्स हुए हैं। इस स्कीम में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक स्टार्टअप को 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। इसके लिए 3.4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। केंद्र को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हाल ही में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, पटना के साथ भी एमओयू किया गया है। दोनों मिलकर बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एंपावर करने के प्रयास में लगे हैं।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर का भवन • जागरण

> बीएयू का सब एग्रीस लगातार बेहतर परिणाम की बदौलत चार राज्यों का लीड इनक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है। यह पूर्वी भारत के स्टार्टअप को तरास कर छात्र-छात्राओं को उद्यमी बनाने का मुख्य केंद्र होगा।

डा. डीआर सिंह, कुलपति, बीएयू सबौर, भागलपुर

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

नेपाल के रास्ते भारत आ रही चीन की महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, महराजगंज : सोनौली बार्डर से नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही चीन की एक महिला को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास न तो पासपोर्ट मिला और न ही वीजा। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

एसएसबी-66वीं बटालियन के जवान मंगलवार की देर रात गश्त पर थे। उनको निर्माणाधीन चेकपोस्ट के पास बार्डर डेवलपमेंट मार्ग पर एक महिला दिखी। जवानों ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम शी जियोहोंग बताया। उसके बैग की तलाशी में पासपोर्ट की छायाप्रति मिली। पता वाले कालम में शीहे रोड 87421 एरिया शीमिंग सिटी, शीमेन प्रांत फुजैन, चीन दर्ज था। इसके बाद उसको आव्रजन कार्यालय लाया गया, जहां उसने खुद को शोधार्थी बताया और कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल से ही नेपाल में थी।

****

दैनिक जागरण
उद्देश्य के अभाव में जीवन निरर्थक हो जाता है

आपातकाल और कांग्रेस

यह समझना कठिन है कि लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हंगामा करना आवश्यक क्यों समझा? क्या कांग्रेस आपातकाल को सही मानती है या फिर यह चाहती है कि लोकतंत्र को कलंकित करने और संविधान का निरादर करने वाले इस तानाशाही भरे कदम का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसे स्पष्ट करना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के संदर्भ में जो कुछ कहा, उससे उसे शिकायत क्यों है? यदि कांग्रेस को आपातकाल के दौरान मारे और प्रताड़ित किए गए लोगों की याद में दो मिनट के मौन का प्रस्ताव रास नहीं आया तो हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो यह होता कि वह यह कहने की हिम्मत जुटाती कि 49 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश पर आपातकाल थोपने और राजनीतिक विरोधियों, मीडिया एवं जनता के खिलाफ दमन का चक्र चलाना एक भूल थी। यदि आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों की भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो कम से कम उसके नेताओं को चुप रहना चाहिए था या फिर सदन से बाहर चले जाना चाहिए था।

कांग्रेस के नेताओं और उसके समर्थकों की ओर से आपातकाल के संदर्भ में यह जो कहने की कोशिश की जा रही है कि पांच दशक पुराने इस काले दौर का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए, वह इसलिए किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं, क्योंकि अतीत की भूलों को विस्मृत करने से उनके दोहराए जाने का खतरा बढ़ जाता है। कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह संविधान के खतरे में होने का फर्जी हौवा खड़ा कर उसके प्रति प्रतिबद्धता जताने में लगी हुई है। यदि वह संविधान के प्रति इतनी ही अधिक प्रतिबद्ध है तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती कि इंदिरा गांधी ने अपनी संसद सदस्यता खारिज किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए आपातकाल का सहारा लिया और इस क्रम में इसी संविधान को कुचला और उसकी प्रस्तावना को मनमाने तरीके से बदल दिया। यह ठीक है कि हाल के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का संख्या बल बढ़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दबे-छिपे स्वर में आपातकाल को सही ठहराने की कोशिश करती दिखने लगे। उसकी यह कोशिश तो आपातकाल के स्मरण को और अधिक आवश्यक ठहराती है। आपातकाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर असहमति और असंतोष जताने से बेहतर होता कि कांग्रेस इस पर गौर करती कि उसके कुछ सहयोगी दलों ने भी इस मामले में उसका साथ देना आवश्यक नहीं समझा। आखिर वे समझते ही क्यों, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनके नेताओं को भी जेल में ठूंस दिया गया था। इनमें मुलायम सिंह यादव भी थे।

कड़े कदम आवश्यक

पंजाब में प्रतिदिन नशे से युवकों की जान जा रही है, लेकिन नशीले पदार्थ बेचने वाले बेखौफ हैं। यदि लंबे समय से पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान का असर नहीं हो रहा है तो सरकार को कड़े कदम उठाने के बारे में सोचना होगा। बठिंडा में जहां मंगलवार को नशे से दो युवकों की मौत हो गई वहीं तरनतारन में नशे ने पांच दिन में चार युवकों की जान ले ली। पटियाला के राजपुरा में भी नशा करने के कारण युवक की जान चली गई। जान गंवाने वाले ज्यादातर युवकों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी। स्वजनों ने जो आरोप लगाए हैं उससे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर कई सवाल पैदा होते हैं। तरनतारन में नशे से जान गंवाने वाले मनप्रीत की मां का कहना है कि गांव में दिन में ही युवा कतार में लग जाते हैं और उन्हें नशीले पदार्थ पैसे लेकर दिए जाते हैं।

जिला पुलिस अधिकारियों के साथ ही थाना एवं चौकी प्रभारियों को भी जवाबदेह बनाना होगा। क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री होने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

बेचने वाले भी गांव के ही हैं। बठिंडा निवासी लखविंदर के पिता के भी इस आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि तलवंडी साबो के हर गांव में सरेआम नशा बेचा जा रहा है। सरकार को जिला पुलिस अधिकारियों के साथ ही थाना एवं चौकी प्रभारियों को भी जवाबदेह बनाना होगा। जिस भी पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है उसको सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब किसी सख्त पुलिस अधिकारी की तैनाती होती है तो क्षेत्र में अपराध के ग्राफ में कमी आ जाती है। इसका मतलब है कि यदि पुलिस इच्छाशक्ति दिखाए तो नशा बेचने वालों पर नकेल कसी जा सकती है।

द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर

हर्ष वी. पंत

पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार की आदर्श साझेदारी होनी चाहिए, उसे नरेन्द्र मोदी और शेख हसीना ने पुन: परिभाषित किया

इस दौर को यदि भारत-बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णिम काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आईं। नई सरकार के कार्यकाल में यह किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का पहला भारत दौरा है। यह दर्शाता है कि बीते दस वर्षों के दौरान दिल्ली और ढाका के रिश्ते कितने मधुर एवं सहज हुए हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों की आंच भी उन पर नहीं पड़ी। तीस्ता जल समझौते की ही मिसाल लें तो जहां मोदी को बंगाल सरकार के विरोध से जूझना पड़ा, वहीं बांग्लादेश में हसीना को भारत-विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो न केवल द्विपक्षीय, बल्कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष जनवरी में जब शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना। तब उन्होंने कहा था, 'भारत हमारा एक प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद साथी और क्षेत्रीय साझेदार है। भारत-बांग्लादेश रिश्ते बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं।' उनके हालिया दौरे की महत्ता को प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह कहकर बखूबी रेखांकित किया कि 'वह हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेशी मेहमान हैं।' इस दौरे पर दोनों नेताओं के बीच दस सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। ये एमओयू डिजिटल एवं हरित साझेदारी से लेकर सामुद्रिक सहयोग और सबसे उल्लेखनीय भारत-बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी का साझा दृष्टिकोण जैसे विविधतापूर्ण विषयों पर केंद्रित रहे। साझा बयान भी कनेक्टिविटी, व्यापार और सहयोग भाव पर केंद्रित शांति, समृद्धि एवं विकास को समर्पित रहा। द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम प्रदान करने के लिए कुछ नई पहल भी की गई हैं। जैसे बांग्लादेश से इलाज के लिए भारत आने वाले मरीजों को ई-वीजा, नई रेल एवं बस सेवा, गंगा जल समझौते के लिए संयुक्त तकनीकी समिति, तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी एक बड़ी परियोजना के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम को बांग्लादेश भेजना, नेपाल से भारतीय ग्रिड के जरिये 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को पहुंचाने के साथ ही बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसी पहल शामिल हैं। बांग्लादेश की सामरिक क्षमताओं में बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाशना भी एक मुद्दा रहा। इसमें बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के साथ ही रक्षा औद्योगिक उत्पादन में सहयोग पर चर्चा हुई।

अवधेश राजपूत

शेख हसीना जुलाई में चीन का दौरा करेंगी। उससे पहले उनका हालिया भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों में आ रही परिपक्वता का भी परिचायक रहा कि दोनों देश अन्य राष्ट्रों के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के साथ ही एक-दूसरे के साथ बहुत निकटता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली ने कभी ढाका को बीजिंग के साथ सक्रियता बढ़ाने से नहीं रोका, लेकिन चीन को लेकर भारत की कुछ चिंताएं जरूर रही हैं, जिनका हसीना ने हमेशा ख्याल रखा है। वर्ष 2020 से ही चीन तीस्ता नदी से जुड़ी विकास परियोजना में एक अरब डालर के निवेश की इच्छा जता रहा है और गत वर्ष उसने एक औपचारिक प्रस्ताव भी दिया। बांग्लादेश के लिए यह लंबे समय से चली आ रही प्राथमिकता है और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में इस संदर्भ में एक समझौता भी किया था, लेकिन वह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के चलते सिरे नहीं चढ़ पाया था। उधर चीन बार-बार प्रस्ताव दे रहा था और भारत की ओर से हीलाहवाली के चलते हसीना राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर थीं। ऐसे में चीन जाने से पहले उनके भारत दौरे से नई दिल्ली को इस मोर्चे पर नए सिरे से पहल करने का अवसर मिला। तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारतीय तकनीकी टीम को बांग्लादेश भेजने का निर्णय यही संकेत करता है कि कुछ घरेलू चुनौतियों के बावजूद वह पड़ोसी देशों में अपने रणनीतिक हितों को तिलांजलि नहीं देगा। इसी प्रकार, 1996 में हुए गंगा जल समझौते के नवीनीकरण के लिए तकनीकी वार्ता का निर्णय भी बांग्लादेश को समय पर आश्वस्त करने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा हसीना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है।

भारत के लिए बांग्लादेश की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होना चाहता है और बंगाल की खाड़ी की भूमिका उसके एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में होगी। वहीं, बांग्लादेश के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक एवं सामरिक केंद्र के रूप में अपनी संभावनाओं को भुनाना है तो उसके लिए भारत से साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। चूंकि दोनों ही देश अपने रणनीतिक नजरियों को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं तो उनके व्यवहार को आकार देने में द्विपक्षीय साझेदारी निरंतर रूप से अहम बनी रहेगी। निःसंदेह, चीन इसमें एक अहम किरदार बना रहेगा, लेकिन उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए। भारत-बांग्लादेश के संबंध अपने हितों एवं समझ के आधार पर सशक्त हो रहे हैं। उनकी अपनी उपयोगिता एवं अहमियत है। इसी महत्ता को समझते हुए मोदी और हसीना ने अपने-अपने देशों की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाना सुनिश्चित किया है। पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार की आदर्श साझेदारी होनी चाहिए, उसे इन दोनों नेताओं ने पुनः परिभाषित किया है। परस्पर सम्मान, परस्पर हित और परस्पर संवेदनशीलता ने इस साझेदारी को अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

परीक्षाओं पर गंभीर चर्चा का समय

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

प्रतियोगी परीक्षाएं रद होने के सिलसिले से युवाओं के सपने तो मरते ही हैं, सरकारों की साख भी गिरती है

पिछले दिनों पेपर लीक होने की शिकायत मिलने के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल करने के लिए होने वाली यूजीसी-नेट परीक्षा भी रद कर दी गई। यह परीक्षा देश भर के 317 शहरों में आयोजित की गई थी और इसके लिए 11.21 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इससे पहले मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आई थी। इन दोनों मामलों की जांच सीबीआइ कर रही है। नीट-यूजी के पेपर लीक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। इस साल नीट-यूजी के लिए रिकार्ड 23 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पेपर लीक के इन मामलों के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट-पीजी समेत कुछ और परीक्षाओं को टाल दिया। देखा जाए तो पेपर लीक होने की बीमारी सिर्फ प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच स्कूलों-कालेजों की परीक्षाओं तक भी हो गई है। सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में पेपर लीक कांड स्वीकार्य नहीं हैं। इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अगुआई में गठित समिति इसका कोई उपाय करेगी। अभी की स्थिति ऐसी है कि जब तक जांच होती है तब तक कोई दूसरा पेपर लीक हो जाता है।

देश में पेपर लीक की बीमारी कोई नई नहीं है। पेपर लीक एक ऐसा नासूर है, जो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता गया है। पिछले सात वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इससे पहले वर्ष 1997 में आइआइटी-जेईई और 2011 में आल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके हैं। इससे करीब दो करोड़ युवाओं का करियर प्रभावित हुआ है। प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा रद होने से युवाओं के सपने मरते हैं। उनके अभिभावकों द्वारा पेट काट कर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। पेपर लीक रोकने के सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। पेपर लीक माफिया कभी परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के सर्वर को हैक कर लेते हैं। कभी परीक्षा सेंटर से साठगांठ कर पेपर लीक कर देते हैं। कुछ समय पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर ट्रांसपोर्ट कंपनी की मिलीभगत से लीक किया गया था।

नासूर बनी प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या। प्रेट्र

हालांकि पेपर लीक और नकल के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इनके बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा के कड़े प्रविधान हैं? जाहिर है सिर्फ कड़ी सजा भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आती। साफ-सुथरी परीक्षाएं कैसे कराई जाती हैं, यह एनटीए को यूपीएससी से सीखना चाहिए। इन दिनों कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी-आधारित यानी कंप्यूटर आधारित आनलाइन परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, लेकिन इसमें भी सेंध लगने का खतरा है। न भूलें यह एआइ का दौर है। अगर किसी मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो सकती है तो परीक्षाएं क्यों नहीं? वास्तव में, भर्ती आयोगों में राजनीतिक संपर्क वाली नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। परीक्षा आयोग की अपनी प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए। साफ्ट कापी को सीधे कोड लाक के माध्यम से 20 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए। इसे छपवाकर वहां मौजूद अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस पद्धति से प्रश्नपत्र प्रेस में छपाई की तुलना में थोड़े महंगे जरूर होंगे, लेकिन सुरक्षित और लीकप्रूफ होंगे। केंद्राध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होना चाहिए। पेपर सेट तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक वितरण में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। याद रहे कि सार्वजनिक परीक्षा के पेपर लीक का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है। इससे आम जन के संसाधनों के साथ ही राज्य के खजाने पर भी भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में भी कई खामियां हैं, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि तीन साल है, जिसे दस साल करना चाहिए। वहीं निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसमें समयबद्ध जांच का भी कोई प्रविधान नहीं है। अधिनियम में किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ अपराधी की संपत्ति जब्त करने का प्रविधान भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवार को भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पेपर सेटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।

हमें पेपर लीक के मामले को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सच तो यह है कि इसने देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। यह किसी 'राज्य विशेष' और 'पार्टी विशेष' का मामला नहीं है, यह देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है। ऐसे में गंभीरता से 'परीक्षा पे चर्चा' करने की आवश्यकता है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिस्थितियों के अनुकूल जीवन

दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। समय, गति यहां तक कि ग्रह-नक्षत्र भी निरंतर गति करते रहते हैं। इस जगत में परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। भले ही कुछ चीजें स्थायी लगती हों, लेकिन ऐसा है नहीं। निरंतरता परिवर्तन के साथ जुड़ी है। परिवर्तन से ही विकास, और विकास से ही लोगों के जीवन में प्रकाश होता है। हम एक निरंतर बदलती हुई दुनिया में रहते हैं। मनुष्य का जीवन भी इसी परिवर्तन का हिस्सा है।

हर नदी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है। फिर चलते-चलते उसमें दूसरी नदियों का मिलन होता जाता है। इस प्रकार एक स्रोत से निकली छोटी-सी धारा बड़ी नदी बन जाती है। इस तरह उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। पहाड़ों, जंगलों और सभ्यताओं के बीच से नदियां अपना रास्ता बनाती हुई आगे निकल जाती हैं और लगातार अपने अंतिम गंतव्य यानी महासागर की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक यही स्थिति मानव जीवन की यात्रा की है। मनुष्य भी कभी रुका नहीं है। शुरुआत से लेकर अब तक मानव ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। आग से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर किया है। यह निरंतर परिवर्तन का सूचक है। इसलिए मनुष्य को दुख में न ज्यादा दुखी और न सुख में ज्यादा प्रफुल्लित होना चाहिए, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए।

समय प्रत्येक का उचित मूल्यांकन कर देता है। इसलिए मनुष्य को धैर्य रखना सीखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बेहद खुश है, लेकिन बहुत संभव है कि दुख की किसी धारा का भी उसके भीतर प्रवाह बना हुआ हो। एक सुखी जीवन का रहस्य इसी में छिपा हुआ है कि हम दुख को भी उसी रूप में स्वीकारें और आगे बढ़ते रहें। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलेंगे तो सामने परेशानियों का पहाड़ नजर आने लगेगा। इसलिए जीवन जीने की सही तरीका यही है कि मनुष्य नदी के प्रवाह जैसा आचरण करे और परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाए।

समराज चौहान

मातृत्व अवकाश का बढ़ता दायरा

सुनीता मिश्रा

सरकार ने सरोगेसी के जरिये बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता को अवकाश देने का फैसला किया है

केंद्र सरकार ने सरोगेसी के जरिये बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता के लिए बड़ा फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक, सरोगेसी की दशा में, सरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता मां (सरोगेसी के जरिये जन्मे बच्चे को पालने वाली मां) को, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की स्थिति में 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। सरोगेसी के माध्यम से बच्चा होने के मामले में अधिष्ठाता पिता, जो सरकारी सेवक है, उसको भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। अभी तक इसका कोई प्रविधान नहीं था, लेकिन सरकार ने 50 साल पुराने नियम में संशोधन कर सरोगेट के साथ अधिष्ठाता माता को भी बच्चे की देखभाल के लिए छह महीने का अवकाश और वेतन देने का फैसला लिया है। हालांकि इसका फायदा अभी सरकारी महिला कर्मचारियों को ही मिलेगा।

सरोगेट मदर बनने का फैसला एक महिला के तौर पर उसके जीवन को बदलने वाले सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। सरोगेट मदर को छह माह का अवकाश और वेतन, दोनों मिलने से वह अपनी देखभाल करने में सक्षम होगी। अगर वह बच्चा छह महीने तक उसके पास और रहेगा तो वह उसे अपना दूध पिला सकती है, क्योंकि वह बच्चे से भावनात्मक रूप से काफी जुड़ी होती है। यह उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत में लगातार सरोगेसी नियमों में ढील दी जा रही है। इसी वर्ष फरवरी में मोदी सरकार ने माता-पिता बनने में असमर्थ लाखों दंपतियों को संतान सुख मिल सके इसके लिए सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया था। इस नियम के तहत बच्चे की चाह रखने वाले माता-पिता अगर किसी चिकित्सकीय परिस्थितियों के चलते खुद के अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग करने में अक्षम हैं तो वे डोनर की मदद ले सकते हैं। सरोगसी अर्थात 'किराए की कोख'। इस प्रक्रिया में बच्चा पैदा करने के लिए दूसरी महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है। यानी अगर कोई महिला किसी चिकित्सीय परिस्थिति के कारण गर्भधारण करने में असमर्थ है या फिर वह गर्भधारण ही नहीं करना चाहती तो वह किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर खरीदते हैं। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के दो तरीके होते हैं- ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु को सरोगेट मां के अंडाणु से मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे की जैविक माता सरोगेट मदर होती है। वहीं जेस्टेशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु और मां के अंडाणु को सरोगेट मदर की कोख में रखा जाता है। इसमें वह बच्चे की जैविक माता नहीं होती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सत्ता पक्ष और विपक्ष में बढ़ती दूरी

'शत्रुता के भाव से भरी संसद' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी के माहौल पर आपत्ति व्यक्त की है। चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं। लिहाजा किसी की चुनावी जीत-हार सबके लिए सहजतापूर्वक स्वीकार्य होने चाहिए, लेकिन 2014 के बाद से देखा जा रहा है कि यह दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक दलों को मालूम होना चाहिए कि चुनावी जीत-हार उल्लास, प्रमाद, शोक के विषय नहीं हैं। अगर ये भाव दोनों पक्षों में आते हैं तो यह माना जाना चाहिए कि लोकतंत्र के यात्री इसकी सवारी सेवा भाव से नहीं कर रहे हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के विरुद्ध अपना उम्मीदवार दिया। यह जानते हुए कि उसके उम्मीदवार की हार होगी तो यह कतई गैर-लोकतांत्रिक कदम नहीं है। कई बार दलों में अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव हुए हैं। स्वाधीनता के बाद राज्यों में सत्ताधारी दल में नेता पद के लिए भी चुनाव हुए हैं। फिर दोनों ने मंत्रिमंडल में साथ-साथ काम भी किए हैं। यद्यपि उनके समर्थकों में इसको लेकर संघर्ष जरूर हुआ। इसे जातीय रंग भी दिया गया, लेकिन वह सरकार पांच साल तक निर्बाध तरीके से चली। हालांकि इन दिनों भारतीय राजनीति में एक-दूसरे के प्रति कटुता कुछ ज्यादा देखी जाने लगी है। संसद तक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनावपूर्ण माहौल या शत्रुता भाव साफ तौर पर दिखाई देता है। आखिर यह बीमारी लोकतंत्र को क्यों और कैसे लग गई? इसकी जांच की जानी चाहिए और समय रहते इसका निदान किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारा लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा।

मुकेश कुमार मनन, पटना

आपातकाल की सच्चाई

पिछले दस साल से केंद्र में वापसी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भी सत्ता से दूर रही तो स्वाभाविक है कि वह सत्तापक्ष से चिढ़ी सी रहेगी, लेकिन इस बार विपक्ष के संख्या बल में वृद्धि होने से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संसद सत्र के प्रथम दिन से ही नई सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। संविधान खतरे में होने का डर पूरे चुनावी परिदृश्य में दिखाया गया और अभी भी इसी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। जवाबी हमले में सरकार ने आपातकाल की पूरी सच्चाई देश की युवा पीढ़ी के सामने लाई तो कांग्रेस को बैकफुट पर आकर कहना पड़ा कि मोदी सरकार अतीत की घटनाओं को कुरेद रही है। मोदी सरकार ने पिछले दस साल से लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित करने का काम ही किया है। कांग्रेस के शासन काल में हर क्षण संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती थीं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

शादी-विवाह बड़ा उद्योग

भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ शादियां होती हैं। औसतन हर विवाह में 12 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। विवाहों पर कुल जितना व्यय किया जाता है, उस हिसाब से इसका बाजार फूड और ग्रोसरी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यह अमेरिका के वैवाहिक बजट से दोगुना है। केवल चीन ही इस मामले में हमसे आगे है। वर्ष 2024 में इस उद्योग में 50 खरब रुपये से अधिक व्यय किए गए। वर-वधु की शिक्षा में विवाह पूर्व सम्मलित रूप से कुल जितना धन खर्च किया जाता है, उससे दोगुना विवाह में खर्च कर दिया जाता है। यह राशि सामान्यतः तीन वर्ष की कुल आय के बराबर होती है। शादियां अनेक क्षेत्रों के व्यवसायों को तीव्र गति से बढ़ा रही हैं। ज्वेलरी, परिधान, इलेक्ट्रानिक्स, वाहन, होटल, बैंड-बाजा, घोड़ी, शराब, फूल, आतिशबाजी, टेंट, यात्रा, फोटो ग्राफी, डीजे, इलेक्ट्रिशियंस आदि पर विवाह में पैसा खर्च होता है। इससे धन समाज के अनेक वर्गों में पहुंचता है, अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। पर अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने के नाम पर अनेक समारोह विदेश में होने लगे हैं, जिससे आर्थिक संसाधनों का बड़ा भाग वहां चला जाता है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

10 हजार से अधिक छात्र और ढाई हजार से अधिक शिक्षक अध्ययन-अध्यापन करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, जहां भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे।

आजकल

प्रो. महेश चंद गुप्ता
पूर्व प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय

नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान का अर्थ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया है। लगभग आठ सदी के बाद यह विश्वविद्यालय समूचे विश्व में ज्ञान के प्रसार के लिए एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। 455 एकड़ में बना नालंदा का नया परिसर केवल कंक्रीट की एक इमारत भर नहीं है, बल्कि इसके निर्माण से हमारे देश का गौरवशाली इतिहास पुनर्जीवित हुआ है। यह भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ाया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिये समूची दुनिया में ज्ञान की अलख जगाने के साथ-साथ एक नया इतिहास रचा जाना तय हो गया है। यह हमारे शैक्षिक उत्थान की प्रेरणा बनेगा। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि नालंदा की प्रेरणा तभी काम आएगी, जब हम शैक्षिक उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे

इतिहास में समूचे विश्व में चर्चित रहा नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलाने में सक्षम हो सकता है। फाइल

सदियों पहले समूचे विश्व के लिए ज्ञान का सागर बने जिस नालंदा को आक्रांताओं ने तहस-नहस कर दिया था, उसका पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा और युगांतकारी कदम है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की स्थापना के उपरांत नालंदा हमारे राष्ट्र के पुनरुत्थान का एक और उदाहरण बना है।

आक्रांताओं ने नालंदा के वैभव को तीन बार नष्ट किया। नालंदा में लगाई गई आग किसी इमारत, पुस्तकालय को नष्ट करने का नहीं, बल्कि भारत के गौरव को आहत करने का प्रयास था, क्योंकि प्राचीन मगध साम्राज्य (आधुनिक बिहार) में पांचवीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का नाम समूची दुनिया में था। इसमें दुनिया भर के दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव ही ऐसा था, जिसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा में चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। भारतीय गणित के प्रणेता और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान नालंदा के प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक रहे। इतिहासकारों के अनुसार सदियों पहले नालंदा में दाखिला आसान नहीं था। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को कठिन साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

आक्रांताओं ने हमारे नालंदा जैसे विशाल भवन नष्ट कर दिए। हमारे अस्तित्व के खात्मे की कोशिशें की गईं, परंतु वह ज्ञान को भला किस प्रकार मिटा पाते। उस ज्ञान को कैसे मिटाते, जो हमारे सहज स्वभाव में है। वक्ती तौर पर भवनों को ढहा देने वाले आक्रांता खुश हो कर चले गए, लेकिन जिस प्रकार काले बादलों का अंधेरा छंटने पर सूर्य की सप्त रश्मियां वातावरण को फिर से जगमग कर देती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और उत्कृष्टता के रूप में नामित नालंदा विश्वविद्यालय से पुनः शिक्षा का उजियारा फूटना शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नालंदा वैश्विक हित का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मोदी का मिशन है कि भारत, दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने और फिर से विश्व के समक्ष सर्वप्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में पहचाना जाए, लेकिन यह मिशन कैसे पूरा होगा, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है। नालंदा का फिर से उठ खड़ा होना निश्चय की खुशी का मौका है। शैक्षिक उत्थान ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है।

शिक्षा के लिए बजट में पर्याप्त प्रविधान : आजादी के बाद सत्तर वर्षों में शिक्षा को नजरअंदाज ही किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रविधान नहीं किए गए। इसी कारण हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर संस्थान पिछड़ गए। हमारे देश में प्राइवेट विश्वविद्यालय निरंतर विस्तार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत यूजीसी की फंडिंग वाले विश्वविद्यालय पिछड़ रहे हैं। हमारे ज्यादातर विश्वविद्यालयों का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है। उनमें विश्वस्तरीय स्मार्ट क्लास रूम का अभाव है। अच्छे आडिटोरियम, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लाक्स और बेहतरीन लैब की कमी खलती है। जो भारत प्राचीन काल में समूचे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिस भारत में उच्च शिक्षा के दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में शामिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस भारत में विश्वविद्यालयों की मौजूदा स्थिति विचारणीय है। देश में उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिहाज से पिछड़ रही है। धनवान लोगों के बच्चे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं और वहीं करियर बनाकर बस भी जाते हैं। प्राइवेट विवि की फीस इतनी है कि सभी बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। यूजीसी फंडिंग वाले विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारी जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है, जब हम अपने विश्वविद्यालयों को विश्व रैंकिंग में लाएंगे। उन्हें बड़ा ब्रांड बनाने की दिशा में काम करेंगे।

हालांकि मोदी सरकार ने शैक्षिक उत्थान के प्रयास शुरू किए हैं। नई शिक्षा नीति इसका प्रमाण है। जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती हैं। हम विकसित देशों को देखें तो पाएंगे कि वे सांस्कृतिक लीडर तब बने, जब वे एजुकेशनल लीडर हुए। आज दुनिया भर के छात्र उन देशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थानों में हुआ करती थी। देखा जाए तो पीएम मोदी के पास विजन है, वह व्यापक काम कर रहे हैं और देश का गौरव लौटा रहे हैं। अभी हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, वह भारत के लिए गौरवशाली और बड़े सकारात्मक बदलावों का कालखंड है। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को मान रही है। भारत की गौरवशाली और प्राचीन संस्कृति की तरफ लोगों का रुझान है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर खिंचे रहने वाले युवा भी हमारी संस्कृति को पुनः अंगीकार कर रहे हैं। मोदी का सपना भारत को विश्वगुरु बनाने का है। यह सपना शिक्षा की बदौलत सच हो सकता है। आज नालंदा फिर उठ खड़ा हुआ है। इसी तर्ज पर समूचे देश के विवि को प्रगति पथ पर बढ़ाया जाए। यह काम केवल सरकार या संबंधित विवि प्रशासन के जिम्मे छोड़ने से नहीं होगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा।

दोबारा प्राप्त होगी खोई हुई प्रतिष्ठा

मुनीष त्रिपाठी
इतिहासकार

एक कहावत है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। लगभग आठ सदी बाद नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया जाना इस कहावत को चरितार्थ करता प्रतीत हो रहा है। साथ ही लंबे इंतजार के बाद नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में अपने पुराने स्वरूप में लौटता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से शिक्षा, ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनने वाला है। वस्तुतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र सम्राट कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान सरकार इस विश्वविद्यालय को वैसा ही वैभव दिलाना चाहती है, जैसा इसका वैभव 800 साल पहले हुआ करता था। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है।

कभी प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट यहां प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान से नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया था तथा छात्र के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 637-642 ईसवी (लगभग छह वर्ष) तक छात्र के रूप में अध्ययन किया था। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने यहां अध्ययन था और सम्राट बनने पर शिक्षा के इस वैश्विक केंद्र को संरक्षण भी दिया था। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए 100 गांवों से होने वाली आय को विश्वविद्यालय के खर्चे हेतु दान में दे दिया था। आज एक बार फिर आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के साथ साथ समाज के जिम्मेदार लोग भी इस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए आगे आएं तो इसे आधुनिक आर्यभट्ट जैसे विद्वान और हर्षवर्धन जैसे शासक फिर से प्राप्त हो सकेंगे। विश्वविद्यालय की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा से प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। निश्चित तौर पर भारत को फिर से विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। भारत विश्वगुरु की पदवी पर अपनी ज्ञान संपदा और संस्कृति के चलते स्थापित हुआ था, क्योंकि ज्ञान संपदा ही भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। हां, इतना ध्यान अवश्य देना होगा कि जो नींव और संरचना प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन और नूतन ज्ञान के समन्वय की थी, उसे बनाए रखना होगा, क्योंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान से ही शोध को बढ़ावा मिलता है। नवाचार, प्रायोगिक शिक्षा जैसे नूतन आयाम भी विश्वविद्यालय शिक्षा के जरूरी अंग होने चाहिए। सूचना विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, समुद्री विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, एआइ जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान में उच्च चरित्र वाले शिक्षकों का अभाव है जो समाज की रीढ़ होते हैं। विश्वविद्यालय में उनके निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए।

आधुनिक विज्ञान ने विश्व के देशों की दूरी को समेट दिया है और आज अनेक कारणों से देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कूटनीतिक ज्ञान की उपयोगिता की आवश्यकता बढ़ी गई है। ऐसे में विदेश नीति की शिक्षा की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय में होनी ही चाहिए। उद्योगीकरण और उद्यमशीलता के अभाव में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। उद्योग-धंधों की स्थापना का प्रशिक्षण विश्वविद्यालयी शिक्षा का अंग होना चाहिए। ईमानदार नौकरशाहों के सृजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट नहीं हुए होते तो भारत को सैकड़ों वर्षों तक गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। यदि किन्हीं कारणों से दासता आती भी तो वह शक, हूणों जैसी होती, क्योंकि तब इन्हीं विश्वविद्यालयों से चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, मिहिरभोज, पुष्यमित्र शुंग, पेशवा बाजीराव जैसे योद्धा, विद्वान पैदा होते जो दासता की बेड़ियों को शीघ्र ही तोड़ डालते।

खरी-खरी

पुल का गुल हो जाना

विनोद कुमार विक्की

प्रचंड गर्मी के बीच एक राज्य से एक ऐसी खबर आई कि जनता से अभियंता तक सभी चिंतित हैं, चिंता स्वाभाविक है, एक बार फिर से विकास पानी में जो बह गया था। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार होने वाला पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। पुल के गुल होने से निर्माण एजेंसी बचाव और सरकार बयान की तैयारी में है। रही बात जनता की, तो क्षेत्रीय जनता ने विकास न सही, लेकिन पुल के सुपर स्ट्रक्चर के रूप में विकास का ट्रेलर तो देख ही लिया था। मीडिया और विपक्ष का दबाव देख माथा महतो और पच्ची सिंह की दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच आयोग घटनास्थल पर पहुंचती उससे पहले ही संतरी से मंत्री तक निर्माण एजेंसी की तात्कालिक सेवा पहुंच गई। साथ ही पुल का पाया जल में एवं माया माननीयों के महल में।

घंटों स्थल एवं निर्माण मैटेरियल का निरीक्षण कर माथा-पच्ची ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, फिर प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

'सर, अरबों रुपये का पुल स्ट्रक्चर आखिर कैसे गिर गया?' पहला प्रश्न बाल की खाल न्यूज चैनल के पत्रकार ने किया।

'देखिए, सृष्टि और संहार तो प्रकृति का नियम है, इंसानी जीवन का कोई भरोसा नहीं, यह तो पुल है...' माथा महतो ने जवाब दिया।

'तो इसमें सरकार दोषी है या निर्माण एजेंसी...?'

अगला प्रश्न कह के लूंगा मीडिया के रिपोर्टर का था।

पच्ची सिंह ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, 'अपलोग भी न कमाल करते हैं। जब सरकार को पुल गिराना ही होता तो वह बनवाती ही क्यों? और कभी सुना है कि जन्म देने वाली मां बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार डालना चाहती हो, तो फिर निर्माण करने वाले मासूम इंजीनियर भला क्यों बनने से पहले ही पुल गिराना चाहेंगे।'

'पुल गिरा कैसे?' सभी पूछ बैठे।

'हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुल न तो घटिया सामग्री और न ही निर्माण एजेंसी की गलती से गिरा है। घटना वाले दिन वातावरण का तापमान 46 डिग्री से ज्यादा था। प्रचंड गर्मी के कारण पुल का पाया पिघल गया और उद्घाटन से पहले ही पुल भरभराकर गिर गया।'

पोस्ट

जब वोटिंग ही नहीं करवानी थी तो फिर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा ही क्यों किया था?
अरविंद चोटिया@arvindchotia

ओवैसी हों या छत्रपाल, ऐसे सभी सांसदों की शपथ दोबारा कराई जानी चाहिए। इससे एक गलत परंपरा का निर्माण हो रहा है। कल को संसद में 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे भी लग सकते हैं।
विकास सारस्वत@VikasSaraswat

नेता विपक्ष को सदन की कार्यवाही के दौरान सतर्क रहकर नियमों के हवाले से सत्तारूढ़ नेताओं की हर बात की समीक्षा करनी होती है। उसकी भाषा भी धारदार होनी चाहिए। राहुल गांधी के लिए यह पद बहुत बड़ी परीक्षा का होगा। यदि वह इसमें पास हुए तो निश्चित ही उनका कद बढ़ जाएगा। जगदीश भाटिया@jagdish

लोकसभा में आपातकाल पर आए प्रस्ताव का सपा और तृणमूल ने समर्थन किया। स्पीकर के चुनाव पर मतदान को लेकर भी विपक्षी खेमे में विभाजन दिखा। स्पीकर के लिए प्रत्याशी उतारने के मुद्दे पर तृणमूल ने अपना विरोध भी जताया कि उससे चर्चा नहीं की गई। यानी विपक्षी एकता की बात जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं।
अमन शर्मा@AmanKayamHai_

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार उतारने से सत्तापक्ष-विपक्ष में टकराव बढ़ेगा?

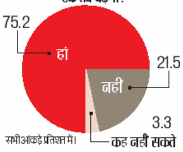

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या राहुल गांधी के नेता-प्रतिपक्ष बनने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

असमंजस में लोग हैं कैसे दें वे साथ,
उनका, जिसने था मढ़ा भारत पर आपात।
भारत पर आपात सुबह उठ भारत चौंका,
संविधान की पीठ गया था छुरा भोंका।
गए पिताजी जेल फैमिली घर में बेबस,
पर पुत्तर जी आज दिखाते हैं असमंजस!!
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

वीआइपी संस्कृति से मुक्त हो रहा प्रदेश

मध्य प्रदेश में 20 वर्ष बाद भाजपा ने सरकार का चेहरा बदला तो अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं। डा. मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान मिलने के बाद सुशासन की दिशा में प्रदेश ने एक कदम तो बढ़ाया ही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की सक्रियता से प्रदेश वीआइपी संस्कृति से भी मुक्त हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण मोहन सरकार द्वारा लिया गया वह निर्णय है, जिसके तहत अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन-भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों पर सरकारी खजाने से आयकर नहीं भरा जाएगा। सीएम और मंत्रियों की परिलब्धियों पर आयकर जमा करने का सिलसिला पिछले 30 वर्षों से अनवरत जारी है। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा सरकार के भी सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इसके लाभार्थी रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि यह मामला सरकार के संज्ञान में पहले नहीं आया हो, 'नईदुनिया' ने 29 जून 2021 को 'राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द चुकाते हैं अपना आयकर पर मध्य प्रदेश में सीएम और मंत्रियों का टैक्स जमा करती है सरकार' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, लेकिन तब सरकार ने सुध नहीं ली। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने कैबिनेट में यह निर्णय लिया कि हर मंत्री अपना आयकर स्वयं जमा करने का निर्णय कर राजनीतिक शुचिता का संदेश दे। दरअसल, इस मामले की शुरूआत 1997 में तब हुई थी, जब कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्रियों द्वारा आयकर जमा नहीं करने के कारण आयकर विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिया था। उन मंत्रियों को बचाने के लिए आनन-फानन उस समय सरकार ने बड़ी चतुराई का परिचय दिया और अध्यादेश के जरिए इसे भूतलक्षी प्रभाव से एक अप्रैल 1994 की तिथि से लागू

डा. मोहन यादव : बदली टैक्स प्रणाली। फाइल

दिग्विजय सिंह : आयकर छूट नीति बनाई। फाइल

कर दिया। बाद में 'मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972' में संशोधन कर कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने सीएम और मंत्रियों का आयकर जमा करने की परंपरा आरंभ की थी। इसमें भी ऐसा खेल खेला कि मंत्रियों को दोहरा लाभ दिलाया। लाभ ऐसा कि आयकर छूट का दायरा अधिकतम दर पर लागू कर दिया गया यानी मंत्रियों की निजी कमाई का आकलन पहले किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आयकर मुक्त आमदनी में छूट की पात्रता होती है, उसकी गणना पहले की जाती है। मंत्री की निजी आमदनी के बाद जो उन्हें सरकारी भत्ते और अन्य परिलब्धियां मिलती हैं, उन पर उच्चतम दर पर आयकर का भुगतान सरकार करती है। इससे उन्हें दोहरा लाभ मिलता रहा है। स्वयं की आमदनी पर आयकर छूट भी ले रहे और सरकारी आमदनी से बढ़ने वाली आय पर उच्च स्लैब का टैक्स सरकार जमा कर रही है।

एक पूर्व मुख्य सचिव कहते हैं कि कोई भी नियम पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। फिर भी दिग्विजय सरकार ने इसे दो वर्ष पूर्व की तिथि से लागू कर दिया था। प्रदेश के वित्तीय सलाहकार रहे एक कर सलाहकार तो इस प्रथा का अपराध मानते हैं। वे कहते हैं कि आयकर प्रत्यक्ष कर है यानी जिसकी आमदनी है, वही कर जमा करेगा। इसका सीधा मतलब है कि सरकार मंत्रियों का टैक्स भरकर अनैतिक कृत्य कर रही थी। बात सही भी है, जब राजनेताओं को स्वयं कोई लाभ लेना होता है तो सभी एक हो जाते हैं। यह 1997 में तब भी हुआ था, जब यह संशोधन विधेयक विधानसभा में रखा गया था। उस समय भाजपा विपक्ष में थी, विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन किसी भी विपक्षी सदस्य ने यह नहीं कहा कि सरकार गलत परंपरा की नींव रख रही है।

मोहन सरकार ने इस वीआइपी संस्कृति को समाप्त कर आम और खास आदमी के बीच के अंतर को खत्म किया है। पहले भी यादव ने सुशासन की दिशा में कुछ अच्छे काम किए हैं। वीआइपी मूवमेंट के समय यातायात रोकने के कारण जाम की स्थिति बन जाती थी। मुख्यमंत्री ने पहल की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वीआइपी मूवमेंट के लिए उतने समय के लिए ही यातायात रोका जाए जितने में वाहन निकल जाएं, काफी समय पहले से यातायात रोकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को एक काम और करना पड़ेगा कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आयकर भी राज्य सरकार ही भर रही है, इस कानून में भी संशोधन की पहल करवानी होगी। चूंकि इसका नियम 'मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन और भत्ते) अधिनियम 1972' अलग है, इसलिए इसमें संशोधन कर सरकार को अन्य गलती को भी सुधार लेना चाहिए। तय किया जाना चाहिए कि जनता के पैसों से इनका आयकर क्यों भरा जाए।

चुनावी चिंतन

लालू की छाया से बाहर निकलने की चुनौती

इस शृंखला के तहत आज पढ़िए लोकसभा चुनाव में राजद की सफलता और उसके सामने भविष्य की चुनौतियों के बारे में...

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

लोकसभा चुनाव में राजद और उसके सहयोगियों को भले ही अपेक्षा के अनुरूप सीटें न मिली हों, मगर परिणाम ने महागठबंधन में शामिल दलों को उत्साह से जरूर भर दिया है। राजद यह मान बैठा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वह बाजी मार ही लेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो राजद शून्य से सीधे चार सांसद पर पहुंच गया। उसके अपने वोट में 6.46 प्रतिशत की रिकार्ड बढ़ोतरी हुई। बेशक यह वोट राजग के खाते से राजद में स्थानांतरित हुआ। राजद को इसका सटीक आकलन करना होगा कि विपक्षी गठबंधन अपनी मजबूती के कारण से कितना जीता व राजग अपनी गलतियों की वजह से कितना हारा।

शाहाबाद और मगध में राजग को भारी नुकसान हुआ। सासाराम, औरंगाबाद, काराकाट, जहानाबाद, बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र संसदीय सीटें राजग के हाथ से निकल गईं। 2009 के परिसीमन के बाद से इन सीटों पर राजग का दबदबा था। वैश्य और निषाद वोटरों की बेरुखी का बड़ा असर उत्तर बिहार की सीटों पर देखा गया, जहां राजग की जीत तो हुई, लेकिन वोटों का अंतर खतरनाक ढंग से कम हो गया। शिवहर में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की रमा देवी तीन लाख 30 हजार वोटों के अंतर से जीती थीं, इस बार इसी सीट पर जदयू की लवली आंनद 30 हजार से कम वोटों के अंतर से जीतीं। सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जैसी परंपरागत कही जाने वाली लोकसभा सीटों पर भी राजग के उम्मीदवारों की जीत का अंतर कम हुआ। हालांकि, नौ सीटों पर राजग उम्मीदवारों की हार का कारण सिर्फ यह नहीं है कि महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा और वह आगे भी मजबूत रहेगा। इनमें से कुछ सीटों के परिणाम तात्कालिक कारणों से प्रभावित हुए। पहला कारण यह बना कि दो-तीन या चार बार से चुनाव जीत रहे सांसदों के विरुद्ध विक्षोभ संगठित हो रहा था। राजग के दलों के आंतरिक सर्वे में यह सलाह दी गई थी कि कुछ उम्मीदवारों को अगर नहीं बदला गया तो चुनाव में उन्हें जनता ही बदल देगी। इस तरह की सलाह-चेतावनी की अनदेखी की गई।

इसके अलावा सहयोगी दलों के बीच सीटों की अदला-बदली में भी स्थानीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। मसलन, शिवहर और सीतामढ़ी में पिछले चुनाव में राजग के जीते सांसद वैश्य बिरादरी के थे। इस बार दोनों सीटों पर सवर्ण उम्मीदवार उतारे गए। इसका नकारात्मक असर पड़ा। इस तरह राजद या महागठबंधन के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी को उपलब्धि मानकर राजद विधानसभा चुनाव में फिर इसी तरह की गोलबंदी का आकलन कर रहा है तो भारी भूल होगी, क्योंकि दोनों चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के समय जब राज्य में सरकार बनाने का मुद्दा आएगा, राजद के लिए सामाजिक समीकरण लोकसभा चुनाव की तरह नहीं रह पाएंगे। हां, अगर राजद इसे आगे भी जारी रखना चाहता है तो उसे माय समीकरण के दायरे से बाहर निकलना होगा। सीटों के बंटवारे के समय बड़ा दिल दिखाना होगा।

असल में राजद उन कमजोरियों से उबरने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण राजग ने उसकी छवि को आक्रामक बनाकर जनता के बीच वर्षों पहले परोस दिया था। यह अकारण नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभाओं में राजद शासनकाल के अपराध की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। लोकसभा चुनाव में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां तक बोल गए कि 1990 से 2005 तक राजद का शासन देख चुके लोग अपनी संतानों को बताएं कि उस दौर में जीना कितना मुश्किल था। इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव शासन के उस दौर के खराब प्रतीकों को ढोने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन, तमाम कोशिशों के बावजूद राजद के लोग उस शैली और प्रतीकों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते सत्ता राजद के दरवाजे से लौट कर वापस राजग के पास चली जाती है। लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी के मंच के आसपास के लोग कुछ इसी तरह का अराजक माहौल बना रहे थे, जिससे कमजोर लोगों में डर पैदा हो रहा था। चिराग पासवान को गाली इसी तरह के एक चुनावी मंच से दी गई थी। अच्छी बात यह है कि तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा में इस तथ्य को नोट किया। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि 15 अगस्त के बाद से शुरू होने वाली उनकी पदयात्रा में खास तरह के लोग उन्हें घेर कर नहीं रखें।

तेजस्वी यादव। फाइल

कुल मिला कर राजद के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वह लालू प्रसाद की छाया से निकल कर तेजस्वी के आभामंडल में पहुंच पाता है कि नहीं। क्योंकि लालू प्रसाद के राजद की सीमा थी। वह हासिल हो चुकी है। तेजस्वी के राजद में संभावना है, जिसने उसे 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की दहलीज तक पहुंचा दिया था। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव में वह चार साल पुरानी उपलब्धियों को कायम नहीं रख पाया।

****

एसबीआइ ने बांड से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने बुधवार को अपने पांचवें बुनियादी ढांचा बांड के जरिये 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने यह राशि 7.36 प्रतिशत की कूपन दर पर जुटाई है। एसबीआइ ने शेयर बाजार को बताया कि इस निर्गम को निवेशकों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली और 19,884 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं। इसे 5,000 करोड़ रुपये के आधार निर्गम आकार के मुकाबले लगभग चार गुना अधिक अभिदान मिला। (प्रेट्र)

बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ पेंशन के जरिये बुजुर्गों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की जरूरत है।
— दीपक मोहंती, चेयरमैन, पीएफआरडीए

संसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रतिकिलोग्राम	डालर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
78,674.25 ▲ 620.73	23,868.80 ▲ 147.50	₹72,300 ▼ ₹250	₹90,600 ▼ ₹900	₹83.57 ▲ ₹0.14	$85.69

एक नजर में

छह शहरों में कार्यालय स्थल की मांग आठ प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली : छह प्रमुख शहरों में बेहतर मांग से अप्रैल-जून तिमाही में पट्टे पर कार्यालय स्थल की कुल मांग आठ प्रतिशत बढ़ी है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कोलियर्स के अनुसार, अप्रैल-जून में कार्यालय स्थल की पट्टे पर कुल मांग 158 लाख वर्ग फुट रही, जो एक साल पहले 146 लाख वर्ग फुट थी। वैश्विक स्तर पर वित्तीय चुनौतियां कम होने कार्यालय बाजार बढ़ रहा है।' (प्रेट्र)

एलएंडटी में 45,000 श्रमिकों और इंजीनियरों की कमी

मुंबई : लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) समूह इस समय 45,000 श्रमिकों, इंजीनियरों की कमी से जूझ रहा है। निर्माण कारोबार 25,000 श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है, जबकि आइटी कारोबार में 20,000 इंजीनियरों की कमी है। इसके लिए कुशल पेशेवरों की कमी, प्रोजेक्ट को तेजी से निष्पादित करने का दबाव, चुनाव और मौसम में अस्थिरता आदि जिम्मेदार हैं। (प्रेट्र)

पी-नोट के जरिये निवेश 1.49 लाख करोड़ हुआ

मुंबई : मार्च के अंत में पी-नोट्स के जरिये निवेश बढ़कर 1.49 लाख करोड़ हो गया, जो मार्च 2023 के अंत में 88,600 करोड़ से काफी अधिक है। मार्च 2024 तक इस मार्ग से निवेश किए गए कुल 1.49 लाख करोड़ रुपये में से 1.28 लाख करोड़ रुपये इक्विटी में, 20,806 करोड़ रुपये डेट में और 346 करोड़ रुपये हाइब्रिड सिक्योरिटीज में निवेश किए गए। (प्रेट्र)

सात प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ेगी आर्थिकी

नई दिल्ली : आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकोनमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ेगी। एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता ने कहा खाद्य कीमतों पर काबू पाना एक चुनौती है। उन्होंने कहा, 'इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक नीति बनानी होगी।' (प्रेट्र)

प्रोजेक्ट फाइनेंस के नए नियम से बैंक परेशान

बैंकों के कर्ज देने की बढ़ेगी लागत और मुनाफे पर पड़ेगा असर, वित्त मंत्रालय से लगाई गुहार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : परियोजनाओं को कर्ज देने के आरबीआइ के नए नियम को लेकर बैंकों ने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है। एक दिन पहले ही वित्त मंत्रालय में बैंकों और वित्तीय एजेंसियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की गई है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़े तमाम मुद्दों पर विमर्श किया गया। इस बैठक में बैंकों की तरफ से प्रोजेक्ट फाइनेंस के नए नियम का मुद्दा उठाया गया।

बैंकों का कहना है कि आरबीआइ का नया नियम उनके लिए कर्ज की लागत बढ़ा देगा। इसका असर उनके मुनाफे के स्तर पर भी होने वाला है। बैंकों से पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से भी आरबीआइ के नए नियम को लेकर अपनी परेशानी से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया है। आरबीआइ के नए नियम के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से परियोजनाओं को जितना कर्ज दिया जाएगा उसकी पांच प्रतिशत राशि का समायोजन अपने मुनाफे से करना होगा।

बैंकिंग उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि आरबीआइ की तरफ से दो महीने पहले यह प्रस्ताव किया गया था लेकिन अभी तक इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। इस वजह से काफी दुविधा है। कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने बड़ी परियोजनाओं को कर्ज देने के फैसले को फिलहाल टाल रखा है। इनका मानना है कि इस बारे में नीतिगत स्पष्टता आने के बाद ही कर्ज देने का फैसला होना चाहिए। आरबीआइ का नया प्रस्तावित नियम कहता है कि परियोजनाओं को कर्ज देते समय कुल कर्ज का पांच प्रतिशत का समायोजन बैंक के खाते में होना चाहिए। बाद में जब परियोजना की शुरुआत हो जाएगी तो समायोजन के अनुपात को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। इस नियम के आने के साथ ही शेयर बाजार में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। खासतौर पर पीएफसी, आरईसी और इरेडा जैसी सरकारी क्षेत्र के एनबीएफसी में काफी गिरावट देखी गई थी। सरकारी बैंक भी इस प्रस्तावित नियम को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं है और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। पूर्व में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा था कि वित्त मंत्रालय आरबीआइ के प्रस्तावित नियम का अध्ययन कर रहा है।

क्या है नियम : प्रस्तावित नियम के तहत आवंटित कर्ज की पांच प्रतिशत राशि का समायोजन बैंकों को अपने मुनाफे से करना होगा।

ये पड़ा असर

- कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने बड़ी परियोजनाओं को कर्ज देने के फैसले को फिलहाल टाल दिया।
- शेयर बाजार में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- पीएफसी, आरईसी और इरेडा जैसी सरकारी क्षेत्र की एनबीएफसी में काफी गिरावट दर्ज की गई।

भविष्य में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए लाया गया नियम

इस नए नियम को लाने का एक मकसद यह भी था कि जिस रफ्तार से अभी देश में कर्ज की रफ्तार बढ़ रही है उससे आगे चलकर फिर से एनपीए की समस्या हो सकती है। पांच वर्ष पहले सकल एनपीए का स्तर (कुल अग्रिम के मुकाबले) 11 प्रतिशत था जो अब घटकर तीन प्रतिशत से नीचे आ गया है। दूसरी तरफ कर्ज की रफ्तार लगातार 15-16 प्रतिशत बनी हुई है। ज्यादा कर्ज वितरण की वजह से एनपीए के फिर से बढ़ने का खतरा रहता है।

शेयर बाजार में जोरदार उछाल संसेक्स-निफ्टी नए शिखर पर

- बीएसई का मानक सूचकांक 620.73 अंक चढ़कर 78,674.25 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ
- नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 147.50 अंक बढ़कर 23,868.80 के नए उच्च स्तर पर पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र : एशियाई बाजारों में तेजी के रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली से स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गए। दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 620.73 अंक चढ़कर 78,674.25 के नए रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 705.88 अंक बढ़कर 78,759.40 के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था। एनएसई का सूचकांक निफ्टी 147.50 अंक बढ़कर 23,868.80 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 168.6 अंक चढ़कर 23,889.90 के नए उच्चस्तर पर पहुंचा था।

रिलायंस का एमकैप 20 लाख करोड़ के पार : रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में चार प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। इससे उसका बाजार मूल्यांकन 80,359.48 करोड़ रुपये बढ़कर 20,48,282.28 करोड़ हो गया।

लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी से घरेलू बाजार को बल मिला और बुधवार को वह नई ऊंचाई पर पहुंच गए। इसके विपरीत, वैल्यूएशन संबंधी चिंताओं के चलते मिड और स्मालकैप शेयरों में मुनाफावसूली देखी गई।
-विनोद नायर, रिसर्च हेड, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज

बजट में मानक कटौती दोगुनी करने पर किया जाए विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार को आगामी बजट में नई रियायती कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को दोगुना करके एक लाख रुपये करना चाहिए या मूल कर छूट की सीमा को बढ़ा 3.5 लाख रुपये करना चाहिए।

बजट में कराधान सुधारों की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कर और सलाहकार कंपनी ईवाई ने सुझाव दिया कि कारपोरेट कर की दरों में स्थिरता रखी जाए। कंपनी ने कहा कि व्यक्तिगत कर के मोर्चे पर छूट/कटौती के बिना रियायती कर व्यवस्था जारी रहे। वर्तमान कर प्रणाली के तहत करदाता पुरानी व्यवस्था और नई रियायती व्यवस्था के बीच चयन कर सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में विभिन्न छूट मिलती है तो नई व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती दी जाती है लेकिन कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है।

होटल और सम्मेलन केंद्रों के लिए इन्फ्रा का दर्जा मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएचआरएआइ) ने सरकार से सभी श्रेणियों के होटल और 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक की परियोजना लागत पर निर्मित सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने का अनुरोध किया है।

सोना-चांदी बार पर आयात शुल्क घटाने की मांग

रत्न और आभूषण निर्यातकों ने बजट में सोने, चांदी और प्लेटिनम बार पर आयात शुल्क घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की। वित्त मंत्री के साथ यहां बजट पूर्व बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग कुल वस्तु निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देता है।

सड़कें अच्छी नहीं हों तो टोल न वसूलें : गडकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर सड़कें अच्छी हालत में नहीं है तो टोल नहीं वसूला जाना चाहिए। गडकरी सेटेलाइट आधारित टोल प्रणाली पर आयोजित एक वैश्विक कार्यशाला में बोल रहे थे। इस प्रणाली को चालू वित्त वर्ष में पांच हजार किलोमीटर से अधिक पर लागू किया जाना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, 'अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो आपको टोल नहीं वसूलना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'आपको यूजर शुल्क वहीं वसूलना चाहिए जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क प्रदान करते हैं। अगर आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर टोल वसूलते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया होगी।' राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मौजूदा फास्टैग व्यवस्था के भीतर ही वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है। इसमें शुरुआत में हाइब्रिड माडल का इस्तेमाल किया जाएगा।

बैटरी ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का एलान

- बैटरी भंडारण और बैटरी निर्माण से जुड़े रसायन बनाने में एक साथ पांच फैक्ट्री लगाने की घोषणा
- इन कंपनियों की तरफ से शुरुआत में दो हजार करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की संभावना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में बैटरी बनाने का उद्योग देसी-विदेशी कंपनियों को तेजी से आकर्षित करने लगा है। इस क्रम में बुधवार को एक साथ पांच कंपनियों ने बैटरी भंडारण और बैटरी निर्माण से जुड़े रसायन के निर्माण के क्षेत्र में निवेश करने का एलान किया है। जिन कंपनियों ने घोषणा की है उनके नाम है नैश एनर्जी, सिंगापुर की वीफ्लोटेक, बैटएक्स एनर्जीज, खुसमंदा पावर और लोहुम क्लीनटेक। ये सारी कंपनियां भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (आइईएसए) की तरफ से अगले हफ्ते आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह के 10वें संस्करण में अपनी योजनाओं का विस्तार से एलान करेंगी। मोटे तौर पर इन कंपनियों की तरफ से शुरुआत में दो हजार करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की संभावना है।

भारत में अभी बैटरी भंडारण बनाने की क्षमता सिर्फ 200 मेगावाट है जो वर्ष 2024 के अंत तक बढ़कर 500 मेगावाट हो जाने की संभावना है। हालांकि आइईएसए का कहना है कि वर्ष 2025 में भारत में 2,000 मेगावाट क्षमता की बैटरी का निर्माण होने लगेगा। हालांकि यह चीन के मुकाबले बहुत ही कम है। चीन में वर्ष 2024 की पहली तिमाही में ही 35 हजार मेगावाट की बैटरी निर्माण क्षमता लगाई गई है। अभी भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन (तिपहिया, दोपहिया से लेकर कारों तक में) बनाए जा रहे हैं, उनमें 90 प्रतिशत में चीन निर्मित बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है।

नैश एनर्जी ने कर्नाटक में स्थापित किया है संयंत्र

नैश एनर्जी की तरफ से स्वदेशी तकनीक से तैयार लिथियम-आयन बैटरी सेल है। इसका पूरी तरह से निर्माण भारत में शुरू किया जा चुका है। नैश ने कर्नाटक में एक लिथियम आयन सेल मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 600 मेगावाट घंटा है, जिसे 1.5 गीगावाट घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। वीफ्लोटेक हरियाणा के पलवल में अपनी गैर लिथियम बैटरी निर्माण इकाई स्थापित कर चुकी है। हाई-टेक सुविधाओं से लैस इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता 100 मेगावाट प्रति घंटा है। बैटएक्स एनर्जीज अत्याधुनिक बैटरी रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में निर्माण इकाई स्थापित कर रही है। कंपनी शुरुआत में 2.5 हजार मीट्रिक टन बैटरी की रिसाइकलिंग करेगी।

नीलामी में 60 प्रतिशत से अधिक स्पेक्ट्रम एयरटेल ने खरीदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : मोबाइल फोन के लिए आवाज तथा डेटा सिग्नल ले जाने वाली रेडियो तरंगों की नीलामी दो दिन के भीतर बुधवार को समाप्त हो गई। इसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित स्पेक्ट्रम के लिए अनुमानित न्यूनतम मूल्य 96,238 करोड़ रुपये से 12 प्रतिशत से भी कम (11,340 करोड़ रुपये) राशि प्राप्त हुई।

एयरटेल ने 6,857 करोड़ में 97 मेगाहट्र्ज रेडियो तरंगों को खरीदा है। यह कुल बेचे गए स्पेक्ट्रम का 60 प्रतिशत है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने बंगाल और बिहार के लिए 973 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा। वहीं कर्ज में डूबी वोडफोन आइडिया ने 4जी नेटवर्क कवरेज और सेवा में सुधार के लिए 3,510 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम खरीदा है। पिछली नीलामी 2022 में हुई थी जो सात दिन तक चली थी। उसमें 5जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकार्ड 1.5 लाख करोड़ से अधिक की बिक्री हुई थी।

राष्ट्रीय फलक

नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आठ हजार और फ्लैट बनाएगा एनबीसीसी

मनीष तिवारी, नई दिल्ली

- डिजाइन व बिल्डिंग प्लान तैयार कर रहा एनबीसीसी
- आम्रपाली परियोजनाओं का काम अगले साल मार्च तक होगा पूरा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की रुकी-फंसी परियोजनाओं में घर खरीदारों को राहत देने के बाद एनबीसीसी 10 हजार करोड़ रुपये के नए आवासीय प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं की मदद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आठ हजार तक लोगों को अपना घर हासिल करने का सपना पूरा हो सकता है। एनबीसीसी नई आवासीय परियोजनाओं की अंतिम डिजाइन और बिल्डिंग प्लान तैयार कर रहा है, जिसे अनुमति के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। एनबीसीसी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 3.5 का अतिरिक्त एफएआर देने की सैद्धांतिक सहमति दी है और इसके सहारे यह सरकारी कंपनी अपना पूरा कर्ज चुकाने के साथ ही दूसरे प्रोजेक्टों के लिए भी धन का इंतजाम करना चाहती है। इसके साथ ही वह अथारिटी का आम्रपाली पर बकाया भी चुकाने की स्थिति में आ जाएगी। ग्रेटर नोएडा में एनबीसीसी को जो अतिरिक्त एफएआर मिला है, उससे उसे पांच परियोजनाओं में अप्रयुक्त जमीन पर घर बनाने का मौका मिल गया है। एनबीसीसी के सीएमडी केपी महादेव स्वामी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 में पांच नई परियोजनाओं में निर्माण की तैयारी है। इनमें सेंचुरियन पार्क, गोल्फ होम्स, लीजर पार्क, लीजर वैली और ड्रीम वैली प्रोजेक्ट शामिल हैं।

स्वामी के अनुसार एनबीसीसी नोएडा में प्रिंसली एस्टेट में अप्रयुक्त जमीन पहले ही बेच चुका है। सिलिकान सिटी में खाली प्लाट को नए प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित कर लिया गया है। हालांकि अभी प्राधिकरण की अनुमति नहीं मिली है। आम्रपाली की फंसी परियोजनाओं में भी काम हर हाल में अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। अभी तक 30 से अधिक परियोजनाओं में 20,500 से ज्यादा फ्लैट पूरे किए जा चुके हैं। स्वामी ने कहा कि अब तक 6,300 यूनिट बेची जा चुकी हैं।

एनबीसीसी। फाइल

लालू के सहयोगी अमित कात्याल को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि कात्याल की आहार संबंधी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें जेल परिसर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद कात्याल को पर्याप्त शारीरिक, मानसिक देखभाल और स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार की आवश्यकता है।

अदालत ने कात्याल को 2.5 लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और 84 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर पहले भी रिहा किया गया था, लेकिन जांच को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है।

सुपरटेक और सन वर्ल्ड बिल्डर के सौ-सौ एकड़ के आवंटन निरस्त

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें न मानने पर यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में लिया फैसला
- फ्लैट खरीदारों पर नहीं पड़ेगा इसका कोई प्रभाव, किस्तों में कर सकेंगे लीज रेंट का भुगतान

यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने सुपरटेक बिल्डर व सन वर्ल्ड बिल्डर का सौ-सौ एकड़ भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें नहीं मानने पर प्राधिकरण बोर्ड ने यह फैसला लिया है।

बुधवार को चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में 81वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। परियोजना में खरीदारों के हित को सुरक्षित रखते हुए उनके हिस्से को छोड़कर शेष भूखंड का आवंटन रद किया गया है। एटीएस बिल्डर को 25 प्रतिशत राशि भुगतान के लिए बोर्ड ने 31 अगस्त तक का समय दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 वर्ग मीटर भूखंड योजना पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में कुल 45 प्रस्ताव रखे गए थे। सबसे अहम प्रस्ताव बिल्डर परियोजना और सुरक्षा रियल्टी से संबंधित था। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि शासन ने अधूरी परियोजना को पूरा कराने एवं खरीदारों को घरों पर कब्जा देने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया है। नौ में से चार बिल्डरों ने समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। एटीएस पर बकाया राशि की गणना गलत होने के कारण उसे 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिए 60 दिन का समय दिया है। दो बिल्डर का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुपरटेक बिल्डर और सन वर्ल्ड बिल्डर के 100-100 एकड़ के आवंटन को निरस्त करने का फैसला हुआ है। दोनों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें नहीं मानीं हैं। सुपरटेक बिल्डर व सन वर्ल्ड बिल्डर बार-बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे।

परियोजना में फ्लैट खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखते हुए उनसे जुड़े भूखंड का आवंटन रद नहीं किया गया है। फ्लैट खरीदारों को परियोजना जुड़े से लीज रेंट का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। सभी छह सबलेसी (किसी किराये के अपार्टमेंट, घर या अन्य इमारत का पूरा या आंशिक भाग किसी अन्य को किराये पर देना) भी समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

खराब वाहन देने वाली एजेंसी वापस लेगी, ब्याज सहित लौटाएगी रकम

राज्य ब्यूरो ● जागरण

- बिहार में रेडक्रास सोसायटी की शिकायत पर आयोग ने दिया निर्देश

पटना : बिहार में रेडक्रास सोसायटी ने टाटा मोटर्स से एक वाहन खरीदा था, उसमें कुछ खराबी थी। शिकायत के बावजूद कंपनी ने गाड़ी की संतोषजनक मरम्मत नहीं हुई। अंततः रेडक्रास सोसायटी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। मामले की सुनवाई के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक मामले का हवाला देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग को वाहन बिक्री एजेंसी को बीमित मूल्य के बराबर राशि वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को हर्जाने के रूप में 25 हजार रुपये भी देने होंगे। साथ ही रेडक्रास वह खराब वाहन एजेंसी को वापस कर देगी।

28 अगस्त, 2014 को शंकर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से 7,39,963 रुपये में रेडक्रास ने वाहन खरीदा था। शिकायत यह कि अधिकृत एजेंसी द्वारा सेवा की बाध्यता होने के बावजूद वाहन में नियमित रूप से दिखाई देने वाले क्लच भाग में खराबी दूर नहीं की गई। वाहन की मरम्मत में भी कमी रह गई। जांच और सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने पाया कि रेडक्रास समाज-सेवा से जुड़ी संस्था है। उसने वाहन का बहुत अधिक उपयोग भी नहीं किया। शिकायत पर एजेंसी की ओर से समुचित पहल भी नहीं की गई। अब एजेंसी रेडक्रास को इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (आइडीवी) यानी घोषणानुसार बीमित मूल्य के बराबर राशि वापस कर देगी। उसपर छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव झेलने के एवज में बतौर हर्जाना वाहन एजेंसी द्वारा रेडक्रास को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया में खर्च हुए 5000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा।

भिवाड़ी में शार्ट सर्किट से केमिकल टैंक में ब्लास्ट, चार श्रमिक जिंदा जले

संवाद सहयोगी, जागरण. भिवाड़ी

- हादसे में 13 से अधिक श्रमिक घायल, दमकल कर्मचारियों ने देर रात पाया आग पर काबू

राजस्थान के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में शार्ट सर्किट के कारण हुए ब्लास्ट में चार श्रमिक जिंदा जल गए। मंगलवार शाम हुए हादसे में 13 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि केमिकल टैंक के पास शार्ट सर्किट से आग लगी जिससे आग टैंक तक पहुंची और धमाका हुआ।

जानकारी के अनुसार, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वर्तिका केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे शार्ट सर्किट के कारण केमिकल प्लांट में आग लग गई। उस समय फैक्ट्री में 50 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे थे। श्रमिकों में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 16 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चार श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया गया। घायल श्रमिकों ने बताया कि वह सेफ्टी डिवीजन में काम कर रहे थे कि अचानक तेज धमाके साथ आग लग गई।

खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार को लगी आग में मरे चार श्रमिक। जागरण

मरने वालों में जम्मू-कश्मीर व उत्तर प्रदेश के रहने वाले : हादसे में मरने वालों की पहचान जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के राजकुमार व बंशीवाल और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के चंदोकी के रहने वाले विशाल, मिर्जापुर जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गांव गोगान के रहने वाले अजय कुमार व विकास के रूप में हुई है।

बायजूस के खिलाफ कार्रवाई जारी : कारपोरेट मंत्रालय

- वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करने वाली खबरें गलत और भ्रामक

नई दिल्ली, प्रेट्र : कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ कंपनी कानून के तहत शुरू की गई कार्रवाई अभी भी जारी है और फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस तरह की खबरें गलत और भ्रामक हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि बायजूस को उसके द्वारा चल रही जांच में वित्तीय धोखाधड़ी से मुक्त कर दिया गया है। मंत्रालय ने जुलाई, 2023 में हैदराबाद में क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय को बेंगलुरु में पंजीकृत बायजूस ब्रांड के तहत परिचालन करने वाली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की जांच करने के लिए कहा था।

इसी साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9,362.35 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन की जांच के सिलसिले में कंपनी के सर्वेसर्वा बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईडी की शिकायत पर फेमा ने रवींद्रन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ईडी ने अप्रैल, 2023 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के बेंगलुरु परिसर और रवींद्रन के आवास की तलाशी ली थी। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए थे। जांच एजेंसी के अनुसार, 'कंपनी और रवींद्रन भारत के बाहर भेजे गए पैसे के एवज में मंगाए गए सामान के दस्तावेज देने में विफल रहे थे। कंपनी को मिले एफडीआइ के साक्ष्य भी प्रस्तुत करने में देरी की। ईडी ने आरोप लगाया था कि कंपनी को 2011 से 2023 तक लगभग 28000 करोड़ का एफडीआइ मिला और इसी दौरान उसने विदेश स्थित कंपनियों को लगभग 9,754 करोड़ रुपये भेजे।

****

2022 में शुरू हुआ था रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की। भारत अभी भी अपनी सैन्य जरूरत का तकरीबन 55 प्रतिशत रूस से लेता

अमेरिका ने भारत के साथ वन स्टाप पैक्ट की इच्छा जताई

कहा, इससे सुरक्षा के साथ ही विमान यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी

यात्रा के दौरान बार-बार की सुरक्षा जांच से मिलेगी राहत

वाशिंगटन, प्रेट्र : विमान यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अमेरिका की यातायात सुरक्षा एजेंसी ने भारत के साथ वन स्टाप पैक्ट करने की आवश्यकता जताई है। इससे यात्री बार-बार की सुरक्षा जांच से बच सकेंगे और आसानी से अपना सफर पूरा कर सकेंगे। यह व्यवस्था अमेरिका सहित कई देशों में लागू हो चुकी है और इससे उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है।

डेविड पेकोस्क। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन में भारत-अमेरिका एविएशन समिट को संबोधित करते हुए अमेरिकी यातायात सुरक्षा प्राधिकरण (यूएसटीएसए) के प्रशासक डेविड पेकोस्क ने कहा, वन स्टाप सुरक्षा का प्रविधान दो देशों की सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यह सिस्टम भारत और अमेरिका के बीच यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। यह सिस्टम यात्रियों और उनके सामान के आगे बढ़ने की गति को बढ़ा देता है और उन्हें बार-बार जांच की प्रक्रिया से गुजरने से बचाते हुए जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाता है।

भारत और अमेरिका की विमानन सेवा। फाइल

हिसार में एविएशन हब बनाने में मदद देगा अमेरिका

वाशिंगटन : हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने के लिए अमेरिका तकनीक और आर्थिक सहायता देगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को अमेरिका की ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति से एयरपोर्ट पर खासतौर से माल लाने और भेजने की सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। इससे भारत की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। एजेंसी के निदेशक इनोह टी एबांग ने एविएशन समिट में इस आशय की घोषणा की।

उन्होंने कहा, वन स्टाप समझौता लागू होने पर अन्य देश के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्री को कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने के लिए फिर से सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना होता है। उसका सामान उसे लेकर आए विमान से घरेलू उड़ान वाले विमान में सीधे पहुंचाया जाता है। चूंकि यह सामान एक बार सुरक्षा जांच के बाद ही विमान में चढ़ाया गया होता है, इसलिए उसके दोबारा जांच की जरूरत नहीं होती है। यही व्यवस्था भारत में भी लागू होगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही यात्रा में कम समय लगेगा और पूरी प्रक्रिया तेज व सुरक्षित बनेगी।

पेकोस्क ने कहा, दोनों देशों की यात्री विमान व्यवस्था पूर्व में सुरक्षा संबंधी कई बड़े झटके झेल चुकी है। भारत ने 1985 में कनिष्क विमान हादसा झेला है तो अमेरिका ने 2001 में विमान से डब्ल्यूटीसी पर हमला देखा है। इसलिए सुरक्षा को बढ़ाने वाले इस सिस्टम को लागू किए जाने की जरूरत है।

समिट में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर माइकल व्हीटेकर ने कहा, भारत और अमेरिका को उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने की जरूरत है। इसमें विलंब करना उचित नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी।

भारत-रूस के रिश्तों पर अमेरिका को एतराज

जयप्रकाश रंजन, जागरण

- अमेरिकी उप-विदेश मंत्री कैम्पबेल ने कहा-हमने अपनी चिंताओं से भारत को अवगत कराया
- हिंद महासागर में भारत की ही होगी केंद्रीय भूमिका, अमेरिका करेगा हरसंभव मदद

नई दिल्ली : पीएम नरेन्द्र मोदी अगले दो हफ्तों के भीतर रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच अमेरिका ने कहा है कि रूस और भारत के बीच गहरे रिश्तों से भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देने की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत के समक्ष उच्च स्तर पर रूस के साथ उसके संबंधों को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया है और अमेरिकी प्रशासन यह मानता है कि भारत के साथ मिलकर इन चिंताओं को कम किया जा सकता है।

अमेरिकी उप-विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने भारतीय पत्रकारों के साथ वीडियो प्रेस कांफ्रेंस में उक्त बातें कहीं। उन्होंने दोहराया, अमेरिका भारत संग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहद मजबूत रिश्ते बनाने को प्रतिबद्ध है। रसेल पिछले हफ्ते भारत के एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए जैक सुलीवन की अध्यक्षता में हुई इनिशिएटिव आन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलाजीज की बैठक की जानकारी दे रहे थे।

कर्ट कैम्पबेल ने पीएम मोदी के साथ अमेरिकी एनएसए की अगुवाई में हुई बैठक के बारे में भी जानकारी दी और कहा, हिंद महासागर में भारत के साथ सहयोग ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारी काफी बात हुई है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका केंद्र में होगी और हमारी कोशिश है कि भारत की सामुद्रिक क्षेत्र में शक्ति (वायु सेना और नौ सेना दोनों में) बढ़ाई जाए। यह इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए जरूरी है। रूस के बारे में उन्होंने कहा, 'भारत और अमेरिका के बीच भारत-रूस के संबंधों को लेकर खुल कर बात होती है। जहां तक अमेरिका की बात है तो हम भारत के साथ बहुत ही गहरे व मजबूत प्रौद्योगिकी रिश्ते बनाने के पक्ष में हैं। हमने साफ तौर पर बताया है कि भारत-रूस के बीच सैन्य व प्रौद्योगिकी के स्तर पर संबंध बने रहे हैं तो इसका क्या-क्या असर हो सकता है। हमने अपनी चिंताओं से भारत को अवगत करा दिया है। हमारे संबंध कई क्षेत्रों में मजबूत हो रहे हैं और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ मुद्दों पर हमारे बीच मतभेद भी हों। जिन बिंदुओं पर सहमति नहीं है, उसे भी साफ तौर पर हम बताते हैं ताकि असहमति को कम किया जा सके।' कर्ट कैम्पबेल का यह बयान तब आया है जब पीएम मोदी के आठ जुलाई को मास्को जाने की सूचना है। इस दौरान मोदी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ भारत-रूस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले (फरवरी, 2022) के बाद अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद नहीं की। भारत अभी भी अपनी सैन्य जरूरत का तकरीबन 55 प्रतिशत रूस से लेता है।

भारत और अमेरिका के बीच हुई आइसीईटी की बैठक में सैन्य व अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर बात हुई है। कैम्पबेल ने बताया कि भारत उन बेहद चुनिंदा देशों में है जिनके साथ हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बहुत ही प्रगाढ़ बनाने के इच्छुक है। यह सभी क्षेत्रों में होगा। जैसे भारत को हथियारबंद वाहन 'स्ट्राइकर' को देने को लेकर बातचीत चल रही है। भारतीय सेना ने इसमें रूचि दिखाई है और हम जल्द ही भारतीय सेना को इसकी खासियत बताने जा रहे हैं। अमेरिका इसका भारत में सह-उत्पादन करने को तैयार है। इसी तरह से अमेरिका की तरफ से तैयार एंटी-टैंक मिसाइल जैवेलीन के निर्माण को लेकर भी बातचीत जारी है। लेकिन ये दोनों शुरुआती स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड (जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व भारत का संगठन) की अगली शीर्ष बैठक भारत में ही करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। संभवतः यह बैठक इस साल के अंत तक होगी।

हिंसा के बाद केन्या के राष्ट्रपति ने कदम पीछे किए

- राष्ट्रपति विलियम रुटो ने कहा-वित्त विधेयक वापस लिया जाएगा
- टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन में देशभर में 23 लोग मारे गए

नैरोबी, रायटर : केन्या में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने बुधवार को कदम पीछे खींच लिए। राष्ट्रपति ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा वह वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वित्त विधेयक वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अब केन्या के युवाओं के साथ बातचीत शुरू करेंगे और देश में आय ओर व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए मितव्ययिता पर काम करेंगे।

संसद पर द्वारा पारित वित्त विधेयक में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव था। वित्त विधेयक में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने से गुस्साए हजारों लोग मंगलवार को संसद परिसर में घुस गए थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में पांच प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, दर्जनों घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के कुछ हिस्सों में आग लगा दी थी। देशभर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में कुल 23 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिनका अस्पतालों में उपचार हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने सरकार द्वारा निर्णय वापस न लेने पर विरोध में प्रदर्शन और तेज करने की धमकी दी थी।

भारत ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाक को फिर फटकारा

- कश्मीर को लेकर निराधार व झूठी कहानियां फैलाने को लेकर की आलोचना
- भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, इसका जवाब देना मंच का समय बर्बाद करने जैसा

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर को लेकर निराधार और झूठी कहानियां फैलाने के लिए पाकिस्तान को फिर फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर ने मंगलवार को कहा कि मैं पाकिस्तान की टिप्पणियों पर कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रतिष्ठित मंच का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

भारतीय प्रतिनिधि प्रतीक माथुर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर महासभा की बहस में भाग ले रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र दूत मुनीर अकरम द्वारा बहस के दौरान महासभा मंच से अपनी टिप्पणी में कश्मीर का संदर्भ दिया गया था। इसके जवाब में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर पाकिस्तान प्रायः कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, भले ही चर्चा का विषय कुछ भी हो। हालांकि, वह इस पर समर्थन और

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर। वीडियोग्रैब/एएनआइ

लोगों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। भारत पहले ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों को खारिज कर चुका है। वह कह जा चुका है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख भारत के अभिन्न व अविभाज्य अंग रहे हैं और रहेंगे।

भारत ने की सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग: भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गठन के अगले वर्ष 80 साल पूरे हो जाएंगे। यह इसके लिए सुधार का उचित और एक बड़ा अवसर है कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों का विस्तार करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्था में व्यापक सुधार ही इसे प्रभावी बना सकता है। इससे वैश्विक संघर्षों पर विराम लगाया जा सकेगा। मालूम हो हो कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा करते हुए लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है।

रूस में वाल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार के विरुद्ध ट्रायल शुरू

येकातेरिनबर्ग, एपी : अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के 15 माह बाद बुधवार को येकातेरिनबर्ग में बंद दरवाजों के पीछे ट्रायल चला। आरोप का अमेरिकी सरकार और वाल स्ट्रीट जर्नल की ओर से विरोध किया जा रहा है। गेर्शकोविच के मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। कार्यवाही बंद होने से पहले पत्रकारों को कुछ मिनटों के लिए अदालत कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। अमेरिकी दूतावास के दो राजनयिकों को भी इसकी अनुमति दी गई थी।

जर्नल के प्रकाशक, डाव जोन्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष व जनरल काउंसिल जे कोंटी ने ट्रायल को दिखावा करार देते हुए कहा, यह फर्जी आरोप हैं। अधिकारियों ने गेर्शकोविच को तब पकड़ा था, जब वह यूराल पर्वत में येकातेरिनबर्ग की रिपोर्टिंग यात्रा पर थे। दावा किया गया था कि वह अमेरिका के लिए गुप्त जानकारी जुटा रहे थे। जर्नल ने इस मामले को लोगों के सामने रखने के लिए पूरी मेहनत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह मुद्दा बना हुआ है।

अमेरिकी कोर्ट से रिहाई के बाद आस्ट्रेलिया पहुंचे असांजे

- अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले में न्याय विभाग से समझौते से मिली राहत
- आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अलबनिजी बोले, सावधान, धैर्यवान और दृढ़ कार्य का परिणाम है रिहाई

कैनबरा, एपी: विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे बुधवार को अमेरिकी कोर्ट में पेशी के बाद रिहा हो गए। रिहाई के बाद वह अपनी मातृभूमि आस्ट्रेलिया लौट आए। इससे पहले उन्होंने कोर्ट में अमेरिका के गोपनीय सैन्य दस्तावेजों को लीक करने का दोष स्वीकार कर लिया। अमेरिकी न्याय विभाग से असांजे के समझौते के तहत ब्रिटिश जेल में बिताई गई 62 माह की अवधि को उनकी सजा पूरी मानते हुए साइपन कोर्ट ने रिहा कर दिया। इसके साथ असांजे की लंबी कानूनी लड़ाई का भी अंत हो गया।

असांजे लंदन कोर्ट से रिहा होने के बाद जिस चार्टर्ड विमान से साइपन कोर्ट पहुंचे थे। उसी से आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के लिए भी उड़ान भरी। विमान में असांजे के साथ अमेरिका में आस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रुड और ब्रिटेन में उच्चायुक्त स्टीफन स्मिथ भी थे। दोनों ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ उनकी रिहाई पर बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अलबनिजी ने संसद में बताया

आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में बुधवार को हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे। एपी

कि असांजे की रिहाई उनकी सरकार के सावधान व धैर्यवान और दृढ़ कार्य का परिणाम है।

कैनबरा एयरपोर्ट पहुंचने पर असांजे का भावपूर्ण स्वागत किया गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों का हाथ हिलाकर धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने रिहाई के लिए संघर्ष में साथ देने वाली पत्नी स्टेला को चूम लिया। इस प्रकार वर्षों से चल रहा अंतरराष्ट्रीय साजिश का आपराधिक मामला 52 वर्षीय असांजे के साथ सबसे असामान्य सेटिंग में आश्चर्यजनक रूप से समाप्त हो गया।

भारत से अमेरिका ले जाकर चचेरे भाई का शोषण करने पर भाई-भाभी को जेल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अपने रिश्तेदार(चचेरे भाई) को स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करने के बहाने अमेरिका लाकर तीन साल से अधिक समय तक अपने गैस स्टेशन व सुविधा स्टोर पर काम करने के लिए मजबूर करने वाले भारतवंशी दंपती को एक अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 साल के हरमनप्रीत सिंह को 135 माह और 43 साल की कुलबीर कौर को 87 माह की सजा सुनाई है। उन्हें पीड़ित (चचेरे भाई) को 1.87 करोड़ रुपये मुआवजा देने को भी कहा है।

न्याय विभाग के अटार्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क ने कहा, प्रतिवादी पीड़ित को झूठे वादे कर अमेरिका लाया था। इसके बाद पीड़ित के दस्तावेज जब्त कर लिए और न्यूनतम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित को बुनियादी मानवीय जरूरतों से वंचित कर दिया गया। इस फैसले से कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अमेरिका में जबरन श्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गाजा में इजरायल के हमले जारी, अभावों से नारकीय हालात

- राहत वितरण केंद्रों पर भी हो रही बमबारी
- रफाह में इजरायली टैंक नहीं बढ़ पा रहे आगे

यरुशलम, रायटर : इजरायल ने बुधवार को भी गाजा पट्टी के कई इलाकों में बमबारी की। रफाह शहर में टैंक गोलाबारी कर रहे हैं पर कड़े प्रतिरोध से उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। रफाह में डेढ़ माह से ज्यादा से इजरायली सेना के जमीन, आकाश व समुद्र से हमले जारी हैं पर शहर पर कब्जा करने में वह विफल है। यहां पर हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं।

मिस्र की सीमा पर बसा रफाह वह शहर है जहां पर इजरायली सेना ने पहले देश भर से बेघर 14 लाख फलस्तीनियों को वहां जाने के लिए कहा और उसके कुछ हफ्ते बाद ही जान बचाने के लिए अन्यत्र जाने के लिए कह दिया। बुधवार को जबालिया में राहत वितरण केंद्र के बाहर इजरायली हमले में तीन लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। नुसीरत में भी पांच लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की सूचना है। बीत लाहिया शहर में भी चार लोग मारे गए हैं। जबकि रफाह में मिसाइल के हमले में दो लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। सात अक्टूबर, 2023 से जारी इजरायली हमलों में अभी तक कुल 37,718 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। आठ महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के कारण फलस्तीनी खाना, पानी और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत से जूझ रहे हैं। राहत सामग्री की आपूर्ति भी गाजा में सभी इलाकों में नहीं हो पा रही है। इजरायली सेना अब राहत वितरण शिविरों में आने वाले लोगों को भी निशाना बना रही है। इसके लिए गाजा की स्थिति नारकीय हो गई है।

सैनिकों ने पहले गोलियां मारीं फिर जीप से बांधा

जेनिन, एपी : वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में जब मुजाहिद अबादी बगल में रहने वाले चाचा के घर में घुस रहे इजरायली सुरक्षाकर्मियों को देखने के लिए निकला तो उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। उसके हाथ व पैर में गोलियां लगीं। इसके बाद उसकी पिटाई कर उसे हिरासत में ले लिया गया। प्रताड़ना से बेहोश हुए 24 वर्षीय मुजाहिद कई घंटे बाद होश में आए तो उसने खुद को सेना की जीप के बोनट पर बंधा हुआ पाया। वह जीप सड़क पर चल रही थी। इसका वीडियो वायरल होने पर सेना ने सफाई दी है कि मुजाहिद संदिग्ध आतंकी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसे किन परिस्थितियों में इस तरह से अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसकी जांच की जाएगी। विदित हो कि वेस्ट बैंक पर इजरायल का अवैध कब्जा है।

भारतीय कामगार की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे इटली

लंदन, प्रेट्र : भारत ने बुधवार को 31 वर्षीय सतनाम सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इटली को त्वरित कार्रवाई करने कहा है। खेत में काम करने के दौरान कृषि मशीनरी से हाथ कटने के बाद उचित इलाज दिलाने की जगह सड़क पर छोड़ दिए जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी।

भारतीय दूतावास सतनाम सिंह के परिवार के संपर्क में है। इस बीच, इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने बुधवार को सतनाम सिंह की मौत को भयानक व अमानवीय बताया। पिछले हफ्ते, मेलोनी ने कहा था कि देश में खेतों में काम करने वाले हजारों भारतीय प्रवासियों में से एक सिंह अमानवीय कृत्यों का शिकार हुए हैं। ये अमानवीय कृत्य हैं जो इतालवी लोगों से संबंधित नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बर्बरता के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। इटली की श्रम मंत्री मरीना काल्डेरोन ने भी सिंह की मौत को बर्बरता का कृत्य बताया।

यूक्रेन पर तनाव के बाद अमेरिका-रूस के रक्षा मंत्रियों ने की फोन पर बात

- यूक्रेन द्वारा क्रीमिया में अमेरिकी मिसाइलों के प्रयोग पर रूस ने दी थी धमकी
- यूक्रेन युद्ध में इसे अमेरिका का सीधा दखल मानते हुए जताया था विरोध

वाशिंगटन, रायटर: यूक्रेन द्वारा रूस के विरुद्ध अमेरिकी मिसाइलों के प्रयोग से दो महाशक्तियों के बीच बढ़े तनाव के बाद अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों ने मंगलवार को टेलीफोन पर बात की है। रूस ने गत सप्ताह क्रीमिया में अमेरिका निर्मित मिसाइलों से यूक्रेनी हमले को युद्ध में अमेरिका का सीधा दखल बताते हुए परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

दोनों पक्षों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन व रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के बीच बातचीत के भिन्न-भिन्न विवरण दिए हैं। पेंटागन ने कहा कि आस्टिन और बेलौसोव ने संचार की खुली लाइनों के महत्व को लेकर वार्ता की। रूसी वायुसेना के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा, आस्टिन ने बातचीत शुरू की। मार्च, 2023 के बाद इस तरह का यह पहला संवाद था। वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बेलौसोव ने आस्टिन को चेतावनी दी कि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर खतरनाक खेल न खेले। मास्को के हथियार नियंत्रण प्रमुख उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने पश्चिमी देशों को हिदायत देते हुए कहा,अगर रूस की चेतावनी को हल्के में लिया गया तो परिणाम दुखद और घातक हो सकते हैं।

रूस और यूक्रेन ने की 90 युद्धबंदियों की अदला-बदली : रूस-यूक्रेन ने एक दूसरे के साथ 90 युद्धबंदियों की अदला-बदली की। इससे पहले 31 मई को भी दोनों पक्षों ने 75 युद्धबंदियों की अदला-बदली की थी। इधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनेस्क रीजन के पूर्वी अग्रिम मोर्चे के नए संयुक्त कमांडर की नियक्ति की है। ब्रिगेडियर-जनरल एंद्रीय हनातोव को लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडोल के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

लांचिंग के बाद उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइल में हुआ विस्फोट

सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पूर्वी तट से हाइपरसोनिक मिसाइल लांच की, पर यह कुछ समय बाद ही हवा में फट गई। दक्षिण कोरिया, अमेरिका व जापान के वरिष्ठ अधिकारियों ने लांचिंग की निंदा करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन और शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मिसाइल ने 100 किमी की ऊंचाई और 200 किमी से अधिक की दूरी तय की।

अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान ने कहा, हम स्थिति पर नजर रखना जारी रखेंगे। इससे पहले, उत्तर कोरिया ने 30 मई को मिसाइल का परीक्षण किया था। यह मिसाइल प्रक्षेपण कोरियाई युद्ध की शुरुआत की 74वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ है। पिछले हफ्ते, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक शिखर सम्मेलन में पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

सीरियाई राष्ट्रपति के अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की वैधता बरकरार

- पेरिस की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कही यह बात
- शिकायतकर्ता ने अदालत के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया

पेरिस, एपी : पेरिस की अपील अदालत ने बुधवार को कहा कि सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान युद्ध अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए फ्रांस द्वारा जारी सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट वैध है और कायम रहेगा। फ्रांस में सीरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले वादी और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जीन सुल्जर और क्लेमेंस विट ने फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया।

मई में फ्रांसीसी आतंकवाद विरोधी अभियोजकों ने पेरिस अपील अदालत से असद के लिए गिरफ्तारी वारंट हटाने पर फैसला देने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें देश के प्रमुख के रूप में पूर्ण इम्युनिटी प्राप्त है। वकीलों ने बयान में कहा, ''यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय अदालत ने माना है कि किसी सेवारत राष्ट्राध्यक्ष की व्यक्तिगत छूट पूर्ण नहीं है।'' फ्रांसीसी न्यायिक अधिकारियों ने पिछले वर्ष नवंबर में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ

बसर-अल- असद। फाइल

अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए असद के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पीड़ितों ने सीरिया के गृह युद्ध की भयावहता की याद दिलाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के फ्रांस के फैसले का स्वागत किया था। किसी सेवारत राष्ट्राध्यक्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट बेहद अचंभित करने वाला मामला है।

टीटीपी ने चीन पाकिस्तान गलियारे को नुकसान पहुंचाने की बात स्वीकारी

कराची, प्रेट्र: पाकिस्तान के एक नेता ने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के एक वरिष्ठ कमांडर ने माना है कि उसका संगठन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान में गैरकानूनी अलगाववादी समूहों के साथ काम कर रहा है। नसरुल्ला उर्फ मौलवी मंसूर को हाल ही में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया था।

प्रांतीय मंत्री लैंगरोव ने कहा,मौलवी मंसूर ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। प्रेस कान्फ्रेंस में दिखाए गए एक वीडियो में मंसूर को यह स्वीकार करते दिखाया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ टीटीपी अपहरण के मामले की साजिश रचता है। टीटीपी और बीएलए कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। हम फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करते हैं और पीड़ितों को अफगानिस्तान ले जाते हैं और फिर उन्हें लापता व्यक्तियों के रूप में दिखाते हैं।

****

पाकिस्तान के कराची शहर में लू से चार दिनों में 450 की मौत

- ज्यादातर शव बेघर लोगों और सड़कों पर नशा करने वालों के हैं
- अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भीषण गर्मी के कारण पिछले चार दिनों में 450 लोगों की मौत हो गई है। एक प्रमुख एनजीओ ईधी फाउंडेशन ने बुधवार को यह दावा किया है। पाकिस्तान का बंदरगाह शहर कराची शनिवार से लू की चपेट में है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री के पार रहा, जो तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक तापमान है। फाउंडेशन के प्रमुख फैसल ईधी ने कहा, ''कराची में चार मुर्दाघर हैं। वहां शवों को रखने के लिए जगह नहीं बची है।'' ज्यादातर शव बेघर लोगों और सड़कों पर नशा करने वालों के हैं।

उन्होंने कहा,मुर्दाघर में सोमवार को 128 व मंगलवार को 135 शव लाए गए थे। अधिकांश मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य दावा करने नहीं आया है। मौत के लगातार मामले सामने आने के बाद सिंध की सरकार ने कराची में 77 हीट वेव राहत केंद्र स्थापित किए हैं। यह कदम पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के दक्षिणी क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान को लेकर गंभीर चेतावनी के बीच उठाया गया है। कराची के अस्पतालों में हर दिन भारी संख्या में मरीज आ रहे हैं।

कराची में भीषण गर्मी के बीच बेहाल दोपहिया वाहन चालक के चेहरे पर पानी स्प्रे करता वालंटियर। एएफपी

पोप ने ड्रग तस्करों को हत्यारा बताया

रोम, एपी : संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम के मौके पर पोप फ्रांसिस ने बुधवार को ड्रग्स तस्करों को हत्यारा बताया। उन्होंने नशीले पदार्थों को लेकर उदारीकरण कानूनों को काल्पनिक करार देते हुए नशे की रोकथाम के प्रयासों व नशा करने वालों की देखभाल में वृद्धि का आह्वान किया। कहा कि सभी प्रभु के बच्चे हैं।

उन्होंने कहा, ''नशे की लत में कमी का लक्ष्य उपयोग को लेकर उदार बनने से हासिल नहीं किया जा सकता, जैसा कुछ देशों में प्रस्तावित किया गया है। यह एक कल्पना है। आप इसका जितना उदारीकरण करते हैं, वे और अधिक उपभोग करते हैं। 'मुझे विश्वास है कि इन खतरनाक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी को समाप्त करना एक नैतिक कर्तव्य है।'' फ्रांसिस ने ब्यूनस आयर्स की मलिन बस्तियों में लोगों की सेवा करते हुए वर्षों बिताए हैं, जहां कोकेन के अवशेषों से बनी ड्रग्स पाको ने समुदाय को तबाह कर दिया था। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान नशे से उबरने वालों से मिलने को प्राथमिकता दी है।

टी-20 विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा **सेमीफाइनल** पिच से स्पिनरों को मिलेगी सहायता, भारत के पास हिसाब चुकाने का मौका

स्पिन बनाम स्पिन की लड़ाई

कुलदीप यादव
अक्षर पटेल
रवींद्र जडेजा

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

13 विकेट भारतीय स्पिनरों ने चटकाए हैं, इनमें सात विकेट कुलदीप ने लिए हैं, अक्षर को तीन और जडेजा को एक सफलता मिली है

अभिषेक त्रिपाठी
गुयाना

टी-20 को बल्लेबाजों का खेल माना जाता है लेकिन गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच काफी धीमी और स्पिनरों के मुफीद है। इस विश्व कप में भी यहां स्पिनरों का जलवा रहा है। हालांकि यहां मंगलवार की शाम से बुधवार की सुबह तक लगातार बारिश होती रही। दोपहर होते होते धूप निकल आई, जिसके बाद पूरी भारतीय टीम ने यहां पर कड़ा अभ्यास किया। प्रोविडेंस स्टेडियम में गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैड से होगा। ये वही इंग्लिश टीम है जिसने 2022 टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल में एडिलेड के मैदान पर रोहित की टीम को 10 विकेट से हराया था। हालांकि यहां भारत का पलड़ा भारी है क्योंकि हम अजेय रहते हुए यहां पहुंचे हैं, जबकि जोस बटलर की टीम लुढ़कते हुए यहां तक आई है। भारतीय टीम के लिए 2013 के बाद कोई आइसीसी ट्राफी जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता।

पिच पर फोकस : यहां का पिच स्क्वायर बहुत दिन से रिले नहीं हुआ है जिस कारण ये काफी धीमी है। यहां टर्न भी काफी मिलता है जिस कारण स्पिनरों का बोलबाला रहता है। पिच में मिट्टी का प्रतिशत कम हो गया जिसका भी असर रहता है। विश्व कप के शुरुआती मैचों में यहां स्पिनर को बड़ा आनंद आया। ऐसे में भारत की तरफ से कुलदीप यादव, अक्षर पटेल व रवींद्र जडेजा और इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद, मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन का जलवा देखने को मिल सकता है।

ऐसा नहीं है कि यहां तेज गेंदबाजों को सफलता नहीं मिलती है। इसी मैदान पर अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दिलचस्प बात यह है कि आठ जून के बाद से यहां कोई मैच नहीं खेला गया है। इससे क्यूरेटर को इस हाई प्रोफाइल मैच के लिए उपयुक्त पिच तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया। मोइन की आफ स्पिन भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करेगी। लेग और आफ स्पिन दोनों करने वाले लिविंगस्टोन भी अपने कोटे के पूरे ओवर फेंक सकते हैं। आदिल के चार ओवर भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकते हैं।

रोहित फार्म में, कोहली को चलना होगा : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आक्रामक मूड में हैं। उन्होंने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं। चिंता का विषय पूर्व कप्तान विराट की फार्म है। ओपनर की भूमिका निभा रहे कोहली फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं। दोनों के लिए यह टी-20 विश्व कप जीतने का आखिरी मौका है। रोहित ने स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यक्तिगत उपलब्धियों की परवाह किए बिना पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करने का इरादा रखते हैं। 2023 विश्व कप हो या टी20 विश्व कप, ये खिलाड़ी अपने अर्धशतक या शतक की चिंता किए बिना टीम के लिए खेल रहा है।शिवम दुबे को मध्यक्रम में ताबड़तोड़ छक्के लगाने और कुछ ओवर गेंदबाजी करने के लिए रखा गया था। अब तक उन्हें फेंकने के लिए सिर्फ एक ओवर दिया गया है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके बस में नहीं दिख रही है। भारत के अंतिम एकादश में बदलाव नहीं करना चाहेगी ऐसे में उन्हें एक और मौका मिलेगा ही। जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और इंग्लैंड को उनके विरुद्ध रन बनाने के लिए कुछ विशेष करना होगा। हार्दिक पांड्या ने अपने आलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित किया है।

अंग्रेज कमजोर नहीं : इंग्लैंड के पास फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक और जानी बेयरस्टो जैसे दाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को धता बता सकते हैं। इस टीम का अभियान उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्हें सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये सब बीती बात है क्योंकि ये टीम नाकआउट में अलग दिखती है। कप्तान बटलर फार्म में आ गए हैं और साल्ट जख्मों में नमक छिड़कने में माहिर हैं। दोनों को पावरप्ले में आउट करना होगा। चोट से वापसी के बाद जोफ्रा आर्चर ने अब तक सात मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में हैट ट्रिक लेने के बाद क्रिस जार्डन का आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर होगा।

वर्षा से मैच रद हुआ तो क्या होगा

- वर्षा के कारण अगर मैच रद होता है तो भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। भारत सुपर-8 चरण में ग्रुप-1 में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा था।
- पहला सेमीफाइनल पूरा करने के लिए 250 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध है, जिसमें 26 जून को दिन के खेल के अंत में 60 मिनट उपलब्ध होंगे और 27 जून को 190 मिनट और उपलब्ध होंगे।
- 27 जून को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में निर्धारित दिन पर अतिरिक्त 250 मिनट उपलब्ध होंगे, जबकि 29 जून को होने वाले फाइनल के लिए 30 जून को रिजर्व डे होगा।

आदिल रशीद
लियाम लिविंगस्टन
मोइन अली

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जानी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, सैम कुर्रन, बेन डकेट, टाम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जार्डन, लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, रीस टाप्ली और मार्क वुड।

15 विकेट इंग्लैंड के तीनों स्पिनरों ने लिए हैं, इनमें सबसे अधिक नौ विकेट आदिल रशीद के हैं, जबकि मोइन और लिविंगस्टोन ने तीन-तीन बल्लेबाजों को आउट किया है

विराट कोहली *vs* आदिल रशीद

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों फार्म में नहीं हैं। हालांकि, सेमीफाइनल में सभी को उम्मीद है कि टीम के स्टार बल्लेबाज अपने रंग में दिखेंगे। आमने-सामने के रिकार्ड की बात करें तो इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद के सामने रिकार्ड बहुत खास नहीं है। नौ पारियों में विराट ने उनके विरुद्ध 72 रन बनाए हैं, हालांकि दो बार आदिल ने उनका शिकार भी किया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध उन्हें रशीद से सतर्क रहना होगा।

रोहित शर्मा *vs* जोफ्रा आर्चर

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध सुपर-8 मैच में 92 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी थी। इंग्लैंड के विरुद्ध एक बार फिर उनसे ऐसी ही पारी की आशा होगी। जोफ्रा आर्चर के विरुद्ध उनका रिकार्ड बहुत प्रभावित करने वाला नहीं है। तीन पारियों में रोहित शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनके विरुद्ध केवल 14 रन ही बनाए हैं। साथ ही एक बार जोफ्रा ने उन्हें पवेलियन की राह भी दिखाई है।

27 विकेट लिए हैं गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में स्पिनरों ने टी-20 विश्व कप के अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में

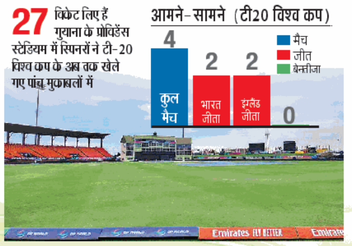

गुयाना का प्रोविडेंस स्टेडियम ● अभिषेक त्रिपाठी

जानी बेयरस्टो *vs* कुलदीप यादव

भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने सुपर-8 चरण में अपनी गेंदबाजी से लोहा मनवाया है। तीनों मैच में उन्होंने विकेट निकालकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया है। इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल में एक बार फिर उन पर दारोमदार होगा। इंग्लिश बल्लेबाज जानी बेयरस्टो के विरुद्ध उनका रिकार्ड अच्छा है। दो पारियों में बेयरस्टो ने उनके विरुद्ध केवल 16 रन ही बनाए हैं, जबकि एक बार कुलदीप ने उनको आउट किया है।

जोस बटलर *vs* जसप्रीत बुमराह

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने अमेरिका के विरुद्ध धुआंधार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जितवा दिया था। सेमीफाइनल में उन्हें इस पारी को दोहराने के लिए बुमराह की चुनौती को पार करना होगा। बुमराह ने एकबार फिर सभी को बहुत प्रभावित किया है। वहीं, बटलर के विरुद्ध उनका रिकार्ड भी शानदार है। अब तक तीन पारियों में बटलर ने उनके विरुद्ध केवल तीन रन ही बनाए हैं, जबकि दो बार बुमराह ने उनका शिकार किया है।

एक नजर में

ग्रैंड शतरंज टूर में भारत के गुकेश होंगे प्रबल दावेदार

बुखारेस्ट: विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश गुरुवार से होने वाले सबसे बड़े इनामी टूर्नामेंट ग्रैंड शतरंज टूर में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेंगे, जबकि आर प्रगनानंद की नजर भी सफलता हासिल करने पर होगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में विश्व के कुछ शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो अपनी बादशाहत साबित करने और अच्छी धनराशि हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। रोमानिया के बुखारेस्ट का शतरंज में समृद्ध इतिहास रहा है और इस टूर्नामेंट में करीबी मुकाबले होने की पूरी संभावना है। (प्रेट्र)

पेरिस ओलिंपिक के लिए हाकी टीम घोषित

नई दिल्ली : हाकी इंडिया ने आगामी पेरिस ओलिंपिक के लिए बुधवार को 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें हरमनप्रीत सिंह को कप्तान और हार्दिक सिंह को उपकप्तान बनाया गया। भारतीय टीम से पांच खिलाड़ी ओलिंपिक में पदार्पण करेंगे। भारतीय टीम को गत चैंपियन बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, 'हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा की गहराई के कारण ओलिंपिक टीम की चयन प्रक्रिया काफी कठिन थी।' (प्रेट्र)

जयवर्धने ने श्रीलंका के सलाहकार कोच पद छोड़ा

कोलंबो : पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने श्रीलंका के सलाहकार कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार को बताया कि श्रीलंका के टी-20 विश्व कप के पहले दौर से बाहर को जाने के बाद जयवर्धन ने इस्तीफा देने का फैसला किया जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा, जयवर्धने ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय टीम के तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करने में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका क्रिकेट भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है और अपनी सेवाएं देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। (प्रेट्र)

इंजमाम के आरोपों पर बोले रोहित शर्मा सभी टीमों को मिल रही रिवर्स स्विंग

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच के दौरान अर्शदीप पर लगाया था गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप

गुयाना : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उनकी टीम ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध टी20 विश्व कप सुपर-8 मैच में रिवर्स स्विंग प्राप्त करने के लिए गेंद से छेड़छाड़ की थी। इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मैच की पूर्व संध्या पर इंजमाम के आरोप के बारे में रोहित से जब पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज को अपना दिमाग खुला रखने की सलाह दी। रोहित ने कहा,'यहां के विकेट काफी शुष्क हैं। सभी टीमों को रिवर्स (स्विंग) मिल रही है। आपको अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत है। यह आस्ट्रेलिया नहीं है।'

भारत के कप्तान ने सेमीफाइनल मैच को लेकर कहा कि उनकी टीम यहां इंग्लैंड के विरुद्ध दबाव वाले टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल में शांत रहने और चीजों को सरल रखने पर फोकस कर रही है। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि टीम को अतीत में विफलता के डर से जूझना पड़ा है। रोहित से जब पूछा गया कि क्या विश्व खिताब के लिए उनकी टीम को विफलता के डर या पिछले प्रयासों में दुर्भाग्य के कारण हार का सामना करना पड़ा है तो उन्होंने कहा, 'यह थोड़ा-थोड़ा दोनों का रहा है।' उन्होंने कहा, 'हम इसे सामान्य मैच की तरह लेना चाहते हैं। हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि यह सेमीफाइनल है। हम एक दूसरे के साथ का लुत्फ उठा रहे हैं और हमें इसे जारी रखना है। यह नाकआउट मैच है। अगर आप बहुत सोचते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होता।'

भारतीय कप्तान ने कहा कि उन्हें आशा है कि उनके साथी गुरुवार को चतुराई भरा क्रिकेट खेलेंगे। रोहित ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो 2022 के बाद से बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है। हमने टी-20 और वनडे में खुले दिमाग से खेलने की कोशिश की है। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो पूरे टूर्नामेंट में चुनौतीपूर्ण रही है। हम एक 'स्मार्ट' क्रिकेट टीम बनना चाहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से और खिलाड़ियों के लिए भी चीजों को सरल रखा है। हमने भूमिका में स्पष्टता से अच्छा प्रदर्शन किया है और खिलाड़ियों पर भरोसा किया है कि वे मैदान पर अच्छे निर्णय लेंगे।'

रोहित ने कहा, 'हर कोई जानता है कि उन्हें अपना काम पूरा करना है। हमें 2022 से 2024 तक बदलाव की जरूरत नहीं है।' उन्होंने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध सुपर-8 चरण के महत्वपूर्ण मैच में 41 गेंद में 92 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम की अगुआई की थी। कप्तान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके लिए जो चीज कारगर रही है वो है शांत रहना।

'अजेय' दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से

पहले सेमीफाइनल में आज भिड़ेंगी दोनों टीमें, इतिहास रचने उतरेगी राशिद खान की टीम

तरुबा, प्रेट्र : बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में इतिहास रचने वाले अफगानिस्तान का सामना टी-20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में गुरुवार को जब 'अजेय' दक्षिण अफ्रीका से होगा तो यह मुकाबला परिणाम के बावजूद ऐतिहासिक होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टूर्नामेंट में अपने सातों मैच जीते हैं लेकिन इस विश्व कप का आकर्षण अफगानिस्तानी टीम रही है। अफगानिस्तानी टीम अपने देश में युद्ध की तबाही से ऊपर उठी और संघर्ष के जज्बे की बदौलत ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड के बाद सुपर-8 में 2021 के चैंपियन आस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था।

अफगानिस्तान के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कई नायक रहे हैं। कप्तान राशिद खान ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी और नवीन उल हक ने टीम को शुरुआती सफलताए दिलाई, गुलबदीन नईब ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध जादुई स्पैल डाला जबकि मोहम्मद नबी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। आरंभिक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन के साथ टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज जबकि फजलहक फारूकी 16 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज हैं। यह अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि कैसे अफगानिस्तान के दो खिलाड़ी कुछ बड़े नामों को पीछे छोड़कर आंकड़ों की तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। लेकिन यह सब बेकार हो सकता है अगर वे ब्रायन लारा अकादमी में लड़खड़ा जाए। इस स्थल का नाम वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने अफगानिस्तान का भरपूर समर्थन किया है।

राशिद खान

अफगानिस्तान : राशिद खान (कप्तान), गुरबाज, इब्राहिम जादरान, अजमतुल्लाह ओमरजई, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी और फरीद अहमद मलिक।

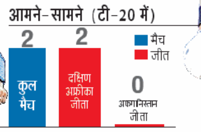

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करैम (कप्तान), बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्जे, क्विंटन डिकाक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसेन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिक नोर्त्जे, कैगिसो रबादा, रेयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी और ट्रिस्टन स्टब्स।

एडेन मार्करैम

अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और स्लोवेनिया नाकआउट में

लाउतारो मार्टिनेज के गोल से अर्जेंटीना ने चिली को हराया

ईस्ट रदरफोर्ड, एपी : लाउतारो मार्टिनेज ने 88वें मिनट में रिबाउंड पर गोल दागा जिससे गत चैंपियन अर्जेंटीना ने चिली पर 1-0 की जीत के साथ कोपा अमेरिका फुटबाल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दिग्गज खिलाड़ी लियोन मेसी की कार्नर किक पर लगाए शाट को चिली के गोलकीपर क्लाडियो ब्रावो ने रोक दिया, लेकिन रिबाउंड होकर आई गेंद को मार्टिनेज ने गोल में पहुंचाकर टूर्नामेंट का अपना दूसरा गोल किया। खिलाड़ी खड़े होकर तीन मिनट तक प्रतीक्षा करते रहे जिसके बाद वीडियो समीक्षा में गोल की पुष्टि हुई। मार्टिनेज का राष्ट्रीय टीम के लिए यह 26वां गोल है।

डेविड के गोल से कनाडा ने पेरू को हराया: जोनाथन डेविड के 74वें मिनट में दागे गोल की मदद से कनाडा ने पेरू को 1-0 से हरा दिया। कनाडा की 24 वर्षों में अपने दक्षिण अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध यह पहली जीत है। जैकब शैफेलबर्ग के विरुद्ध टैकल के लिए मिगुएल अराउजो को लाल कार्ड दिखाए जाने के कारण पेरू को 59वें मिनट के बाद 10 खिलाड़ी से खेलना पड़ा।

चिली के विरुद्ध गोल दागने के बाद लाउतारो मार्टिनेज ● एपी

आज के मैच

वेनेजुएला *vs* मेक्सिको	सुबह 6.30 बजे	स्थानः कैलिफोर्निया
पनामा *vs* अमेरिका	3.30 बजे	स्थानः जार्जिया

कोलोन, एपी : इंग्लैंड ने मंगलवार को यहां स्लोवेनिया के विरुद्ध गोल रहित ड्रा खेलकर ग्रुप सी के विजेता के रूप में यूरो 2024 फुटबाल टूर्नामेंट के नाकआउट चरण में जगह बनाई। कोलोन स्टेडियम में हुआ मुकाबला ड्रा खेलकर स्लोवेनिया की टीम भी अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रही जबकि क्रोएशिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

इंग्लैंड और स्लोवेनिया के बीच हुए मुकाबले में गोल करने में काफी अधिक मौके नहीं बने। इंग्लैंड के स्थानापन्न खिलाड़ी कोल पाल्मर के पास हालांकि इंजरी टाइम में टीम के जीत दिलाने का अवसर था लेकिन उनके शाट को स्लोवेनिया के गोलकीपर यान ओबलाक ने रोक दिया। इंग्लैंड की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में तीसरे स्थान पर रहने वाली एक टीम से भिड़ेगी।

सर्बिया के विरुद्ध मैच के दौरान डेनमार्क के क्रिश्चियन एरिकसन ● एएफपी

डेनमार्क ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

म्यूनिख, एपी : डेनमार्क ने मंगलवार को यहां सर्बिया के साथ गोल रहित ड्रा खेलकर यूरोपीय फुटबाल चैंपियनशिप (यूरो 2024) के अंतिम 16 में प्रवेश किया। डेनमार्क ने ग्रुप सी में तीन अंक हासिल किए जो स्लोवेनिया के बराबर थे लेकिन बेहतर क्वालीफाइंग रैंकिंग के कारण दूसरे स्थान पर रहा। ग्रुप विजेता इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रा खेलने वाला स्लोवेनिया भी नाकआउट चरण में पहुंच गया। डेनमार्क ने अधिकांश मौके बनाए लेकिन टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। सर्बिया को अगले दौर में पहुंचने के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन टीम नाकाम रही। डेनमार्क के लगभग सभी मौके क्रिश्चियन एरिक्सन के जरिए बने जो अपने देश के लिए रिकार्ड 133वीं बार खेल रहे थे।

रोबिंसन ने फेंका प्रथम श्रेणी का सबसे महंगा ओवर, 43 रन दिए

क्रिकेट डायरी

नई दिल्ली, जेएनएन : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रोबिंसन ने बुधवार को काउंटी चैंपियनशिप मैच में 43 रन लुटाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने का अनचाहा रिकार्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने होव में ससेक्स के लिए खेलते हुए लेस्टर के विरुद्ध डिवीजन दो मैच में अपना ओवर पूरा करने के लिए कुल नौ गेंद फेंकी जिन पर 43 रन बने।

लेस्टर के लुइस किंबर ने रोबिंसन पर पांच छक्के, तीन चौके और एक रन से 43 रन बनाए। रोबिंसन के इस ओवर के पूरा होने के बाद किंबर ने 65 गेंद में नाबाद 109 रन बना लिए थे। बेन काक्स दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे। यह रोबिंसन का 13वां ओवर था जिसमें 6, नोबाल पर 6, 4, 6, 4, नोबाल पर 6, 4, नोबाल पर 6 और एक रन बना। इस तरह ओली रोबिंसन ने सर्वाधिक रन लुटाने का रिकार्ड भी तोड़ दिया। 1998 में एलेक्स ट्यूडर ने और चार दिन पूर्व शोएब बशीर ने एक ओवर में 38 रन दिए थे।

सूर्य को पछाड़ कर हेड बने नंबर एक बल्लेबाज

नई दिल्ली : आस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड बुधवार को जारी आइसीसी की नवीनतम रैंकिंग में भारत के सूर्यकुमार यादव को पछाड़कर विश्व के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्यकुमार यादव दिसंबर 2023 से शीर्ष पर थे। हेड ने मौजूदा टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन की बदौलत नंबर एक रैंकिंग हासिल की। हेड ने टूर्नामेंट में दो अर्धशतक की मदद से 255 रन बनाए जिसमें सुपर आठ मुकाबले में भारत के विरुद्ध 76 रन की पारी भी शामिल है।

****

दैनिक जागरण सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का
गुरुवार, 27 जून, 2024

टेक टिप्स

सही करें मोबाइल का सिग्नल

आप इंटरनेट पर कुछ देख रहे हों या जरूरी काल करनी हो, लेकिन मोबाइल का सिग्नल गायब हो जाए तो झुंझलाहट होना स्वाभाविक है। अगर अक्सर ऐसा हो रहा है तो मोबाइल को एअरप्लेन मोड में या आफ करके सिग्नल को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य आसान उपायों से भी फोन के सिग्नल को दुरुस्त कर सकते हैं। हालांकि साफ्टवेयर वर्जन में अंतर होने के कारण कुछ डिवाइसेज की सेटिंग का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है।

कुछ आसान उपाय

सेल टावर सिग्नल जोन में रहें: मोबाइल और सेल टावर के सिग्नल के बीच व्यवधान आने से भी समस्या होती है। आसपास धातु की कोई वस्तु या कंक्रीट दीवार होने से भी सिग्नल बाधित होता है। ऐसे में खिड़की के पास या संभव हो तो बाहर निकल जाएं।

एंटीना अवरुद्ध न हो: बढ़िया सिग्नल प्राप्त करने के लिए प्रयास करें मोबाइल का एंटीना कवर से अवरुद्ध न हो।

पूरा चार्ज रखें: बैटरी लो है तो भी सिग्नल में परेशानी हो सकती है।

आवश्यक टिप्स

- सही सिग्नल मिलने के लिए स्थान बदलकर देखने के अलावा एअरप्लेन मोड, वाइ-फाइ और सेलुलर नेटवर्क को आफ-आन या फोन को री-स्टार्ट करने का विकल्प जरूर चुनें।
- वाइ-फाइ और सेलुलर कनेक्शन पूरी तरह डिस्कनेक्ट होने की प्रतीक्षा करें। एअरप्लेन आइकन पर दोबारा टैप करने के लिए कम से कम 15 सेकंड तक इंतजार करें।
- सिम कार्ड निकालकर साफ करें। अगर यह खराब है तो बदलें।

इन दिनों

देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल यूजीसी-नेट का प्रश्नपत्र लीक करने के संदिग्धों की भ्रष्ट गतिविधियों में 'डार्क वेब' के प्रयोग का दावा किया गया। क्या है डार्क वेब, इसके दुरुपयोग और सतर्कता जैसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र

फोटो : फ्रीपिक

डार्क वेब
इंटरनेट की काली दुनिया

ओपन वेब
- जिन वेबसाइट को आसानी से सर्च किया जा सके
- ई-कामर्स वेबसाइट
- न्यूज साइट
- पब्लिक ब्लाग एवं फोरम

डीप वेब
- जिन वेबसाइट के लिए लाग-इन की जरूरत हो
- ईमेल अकाउंट
- आनलाइन बैंकिंग अकाउंट
- सब्सक्रिप्शन सेवाएं

डार्क वेब
- जिन साइट्स को केवल 'टोर' से एक्सेस किया जा सके
- वेबसाइट जो सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं
- .onion डोमेन हो।
- डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस

डार्क वेब के खतरे: डार्क वेब पर चुराए गए क्रेडिट कार्ड नंबर और अन्य गोपनीय जानकारियां, ड्रग्स, हथियार, पोर्नोग्राफी कंटेंट, चोरी के अकाउंट, लाग-इन इन्फार्मेशन, फर्जी पासपोर्ट और मालवेयर आदि की मौजूदगी होती है। खास बात है कि डार्क वेब पर जाना अवैधानिक भले ही न हो, लेकिन यहां अवैध गतिविधियों में शामिल होना जोखिमभरा हो सकता है और आप कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।

यूजीसी-नेट होने के एक दिन बाद ही इसके रद करने की घोषणा कर दी गई। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी वक्तव्य आया कि मूल प्रश्नपत्र से मेल खाता एक प्रश्नपत्र 'डार्क वेब' पर है, जिसके कारण परीक्षा रद की गई। दरअसल, डार्क वेब इंटरनेट की अवैधानिक गतिविधियों का अड्डा है।

कैसे काम करता है डार्क वेब: आप डार्क वेब की कल्पना करें, जहां हैकर सेंध लगाए हुए, डाटा व अन्य गोपनीय जानकारियों को बेच रहे हैं और ड्रग तस्कर अपने उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसी ही अनेक अवैध गतिविधियां यहां होती हैं और सामान्य इंटरनेट यूजर इन सबसे आमतौर पर बेखबर होता है।

हालांकि डार्क वेब का प्रयोग निजी कम्युनिकेशन और वैध उत्पादों के सोर्सिंग टूल्स के तौर पर भी किया जाता है। आमतौर पर जब किसी महत्वपूर्ण डाटा में सेंध लगती है तो वह डार्क वेब पर बेची जाती है। यही कारण है कि बार-बार लोगों को आनलाइन सुरक्षा को लेकर आगाह किया जाता है।

डार्कवेब की दुनिया: आसान शब्दों में कहें तो डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है, जिसे नियमित सर्च इंजन (जैसे-गूगल, याहू, बिंग आदि) द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है। इसे 'टोर' जैसे विशेष तरह के ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। यह कानूनी और अवैध दोनों तरह की गतिविधियों को होस्ट करता है। चूंकि यहां पहचान छिपाने की सुविधा होती है इसलिए स्कैम और अवैध सामग्री जैसे जोखिम यहां हर समय बने रहते हैं। डार्क वेबसाइट एनक्रिप्शन साफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं जिससे उनके विजिटर और उसके ओनर एनानिमस दिखते हैं यानी उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं होती। सिक्योरिटी फर्म नोर्टन के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 27 लाख सक्रिय यूजर डार्क वेब को ब्राउज करते हैं।

समझें डिजिटल यूनिवर्स को

इसके तीन मुख्य घटक होते हैं-

ओपन वेब: इंटरनेट का दृश्यमान हिस्सा, जहां तमाम तरह की वेबसाइट और लिंक्स से लोग परिचित होते हैं। इसे आप अपने इंटरनेट ब्राउजर, जैसे-गूगल क्रोम, मोजिला आदि से सर्च करते हैं। यहां अवैध गतिविधियों का संचालन आसान नहीं है, जैसे यूजीसी नेट प्रश्नपत्र को यहां बेचने पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है।

डीप वेब: यह इंटरनेट का बड़ा हिस्सा (90 प्रतिशत) होता है। इसी के एक छोटे हिस्से में डार्क वेब की गतिविधियां भी संचालित होती हैं, लेकिन अधिकांशतः डीप वेब में वैध गतिविधियां ही होती हैं। यहां बड़े डाटाबेस होते हैं, खासकर फाइनेंशियल अकाउंट, ईमेल और सोशल मैसेजिंग अकाउंट, प्राइवेट इंटरप्राइजेज डाटाबेस, वैध फाइल्स आदि।

डार्क वेब: यह इंटरनेट की अवैध गतिविधियों का अड्डा है, जहां यूजीसी-नेट के प्रश्नपत्र के लीक होने का दावा किया गया है। इस तरह की साइट को किसी के द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता। गूगल केवल ओपन वेब से ही साइट को इंडेक्स करता है। सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्की की एक रिपोर्ट बताती है कि डार्क वेब पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, साइबर अपराधी अब 'एस्क्रो' सर्विसेज का प्रयोग करने लगे हैं। एस्क्रो एजेंट एक तरह के मध्यस्थ होते हैं, जो आनलाइन ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। कुल मिलाकर साइबर अपराधी जिस तरह नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, उससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक हैं।

वर्ग पहेली - 2673

बाएं से दाएं

2. ठसाठस, भरपूर (4)। 4. अलग करना, बेमेल करना (3)। 5. कारण, हेतु (3)। 7. काम निकल जाने पर उपेक्षा करना (2,3)। 10. धब्बा (2)। 11. बहुत लोगों का भोजन एक साथ पकाने का स्थान (3)। 14. दुखी, खिन्न (3)। 15. हमेशा, सर्वदा (2)। 16. सम्मानित व्यक्ति को अपशब्द कहना (5)। 20. इस रोग में रात में कुछ दिखाई नहीं देता (3)। 21. स्वाभाविक ढंग, तमीज, शिष्टता (3)। 22. मरने तक (4)।

ऊपर से नीचे

1. प्रतिस्पर्धा, सामना (4)। 2. होशियार (5)। 3. जोखिम, आशंका (3)। 6. तट, शर, वाण (2)। 8. बर्रे, भिड़ (3)। 9. एक प्राचीन विश्वविद्यालय (3)। 12. जकड़कर बांधना (3)। 13. बधिर (3)। 14. दृष्टांत (5)। 17. महीना (2)। 18. धमकी देना, डराना (4)। 19. अंतःपुर, रनिवास (3)।

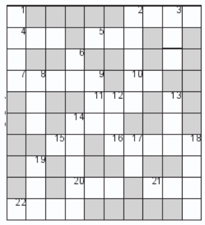

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

	द	ह	न			प्र	वी	ण	
म			ग			णे			ब
ध्य			र	च	यि	ता			ल
म	जा	क		र			स	म	य
		म		बां	हि	या	त		
		क	र्म	ही	न		ल		
मा	न	स			बा		जं	ल	क
त			प	ह	ना	वा			ल
म			सं			चा			ई
	मु	री	द			ले	की	र	

जागरण सुडोकू- 2673

		3			6	1		4
1		6	8				5	
7			3		1		6	9
	1		4			5		8
3	7	5			9		1	
		4		2		7		6
5	6		9				2	1
		9		1		6		
4			5		2		7	3

कल का हल

5	4	3	8	1	7	6	9	2
6	7	1	3	2	9	4	5	8
8	9	2	5	4	6	7	1	3
7	2	5	1	3	4	9	8	6
9	3	6	7	8	5	1	2	4
4	1	8	6	9	2	3	7	5
2	5	4	9	6	1	8	3	7
1	8	7	4	5	3	2	6	9
3	6	9	2	7	8	5	4	1

आज का भविष्यफल- 27 जून, 2024 गुरुवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी। आज का राहुकाल : दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक। आज का दिशाशूल : दक्षिण। विशेष : पंचक

कल 28 जून, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
विशेष : पंचक
भद्रा : प्रातः 05:34 बजे तक।
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तत्पश्चात अष्टमी पूर्वभाद्रपद नक्षत्र तत्पश्चात उत्तरभाद्रपद नक्षत्र सौभाग्य योग तत्पश्चात शोभन योग मीन में चंद्रमा।

- **मेष :** राहु-चंद्रमा की युति निजी सुख में व्यवधान देगी।
- **वृष :** रिश्तों में निकटता आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
- **मिथुन :** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। अधिकारी से सहयोग मिलेगा।
- **कर्क :** व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **सिंह :** आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी।
- **कन्या :** आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। आशातीत सफलता मिलेगी।
- **तुला :** स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अज्ञात भय मन को कलेश देगा।
- **वृश्चिक :** संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- **धनु :** निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। प्रियजन से पीड़ा मिल सकती है।
- **मकर :** व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। पुरुषार्थ सार्थक होगा।
- **कुंभ :** आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी।
- **मीन :** उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। मन पर नियंत्रण रखें।

टेक अपडेट

गूगल जेमिनी व मेटा एआइ

गूगल ने भारत में जेमिनी एआइ टूल पेश किया है, जिसकी मदद से अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि में सवाल पूछ सकते हैं। वहीं मेटा ने भी भारत में वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए मेटा एआइ फीचर को जारी करना शुरू कर दिया है। जानें, कैसे गूगल जेमिनी और मेटा एआइ का उपयोग कैसे कर सकते हैं...

गूगल जेमिनी

एंड्रायड व आइओएस यूजर्स जेमिनी एप को अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। यदि आपने चैटजीपीटी का उपयोग किया है तो जेमिनी में परेशानी नहीं होगी। चैटजीपीटी की तरह ही इससे भी सवाल-जवाब कर सकते हैं। इसमें टाइप कर, बोलकर और इमेज के जरिए सवालों के जवाब जान सकते हैं।

कैसे करें उपयोग: गूगल जेमिनी एप को एंड्रायड यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं आइओएस यूजर के लिए यह एपल एप स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा https://gemini.google.com/app लिंक की मदद से इसे लैपटाप या डेस्कटाप पर भी एक्सेस किया जा सकता है। यूज करने से पहले इसे डाउनलोड करना होगा। एप को ओपन करने के बाद गूगल असिस्टेंट से जेमिनी पर स्विच करने के लिए कहा जाएगा। फिर गूगल की शर्तों के साथ आगे बढ़ना होगा। इस तरह गूगल जेमिनी के साथ बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। इमेज से सर्च करना चाहते हैं तो गैलरी या कैमरे की मदद से क्लिक कर सकते हैं। वायस कमांड के जरिए बातचीत के लिए हे गूगल बोल सकते हैं या फिर होम बटन पर कुछ देर टैप करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे पहले गूगल असिस्टेंट को यूज करने के लिए किया करते थे। गूगल जेमिनी वे सभी कार्य कर सकता है, जो पहले गूगल असिस्टेंट करता था। यह इवेंट्स की प्लानिंग भी कर सकता है। इसकी मदद से इंटरनेट मीडिया

के लिए कैप्शन आदि भी लिखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ टाइमर सेट करने, काल करने आदि की सुविधा भी मिलती है। इसकी मदद से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्या है, उसे सर्च करने या अपनी गैलरी से फोटो का उपयोग करके सर्च करना शुरू कर सकते हैं। जेमिनी आपके लिए टेक्स्ट भी पढ़ सकता है। इसके लिए सबसे ऊपर दायीं तरफ प्ले और पाज बटन दिया गया है। खासकर जब आंखें थकी हुई हों तो यह बढ़िया विकल्प हो सकता है। गूगल जेमिनी आपके लिए सात दिनों का कैलेंडर बना सकता है और कवर लेटर भी लिख सकता है। इसके अलावा यह न केवल टेक्स्ट का अनुवाद कर सकता है, बल्कि यह आपको उस टेक्स्ट का स्रोत भी बताएगा। बता दें कि गूगल जेमिनी यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन जेमिनी एडवांस के लिए पैसा खर्च करना होगा। जेमिनी एडवांस को गूगल वन एआइ के माध्यम से 1,950 रुपये मासिक कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। फ्री ट्रायल के तहत दो महीने के लिए फ्री है। इसके बाद हर महीने भुगतान करना होगा। इसके साथ यूजर्स को दो टीबी की स्टोरेज भी मिलती है।

मेटा आइ

मेटा ने भारत में वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए मेटा एआइ को जारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। मेटा एआइ भी ओपनएआइ के चैटजीपीटी की तरह ही है। इससे भी तमाम तरह के सवाल पूछ सकते हैं।

कैसे करें उपयोग: मेटा एआइ को मेटा लामा 3 के सपोर्ट के साथ बनाया गया है जो कि मेटा का सबसे एडवांस लार्ज लैंग्वेज माडल है। इसका उपयोग फीड, चैट के अलावा कई सारे एप्स में कर सकते हैं। इसकी मदद से यूजर कंटेंट भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, इससे मैथ्स के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मेटा एआइ का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक या वाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट करना होगा। उदाहरण के लिए अगर इंस्टाग्राम पर मेटा एआइ का उपयोग करना चाहते हैं तो एप को अपडेट करने के बाद आपको दायीं ओर सबसे ऊपर टैप करके डायरेक्ट मैसेज सेक्शन खोलना है। इसके बाद दायीं तरफ तीन डाट्स पर टैप करने के बाद क्रिएट एन एआइ चैटबाट का विकल्प मिल जाएगा। यहां पर मेटा एआइ दिखने लगेगा। इसी पर टैप करके एआइ से बातें करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर से इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको meta.ai पर जाना होगा।

संतोष आनंद

राष्ट्रीय फलक

नए कानूनों में जीरो एफआइआर की अनिवार्य वीडियोग्राफी

- तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से होंगे लागू
- नए कानूनों के अमल के लिए 40 लाख लोग प्रशिक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र : आगामी एक जुलाई से लागू हो रहे तीन अहम कानून भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इन तीनों कानूनों के तहत जीरो एफआइआर, आनलाइन पुलिस शिकायत, इलेक्ट्रानिक माध्यमों से समन भेजना और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले साल यह नए कानून संसद में पारित किए गए और उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाने का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को सभी के लिए और सहज और सुलभ बनाना है। इस बीच अगले हफ्ते से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों के लिए बुनियादी स्तर पर 40 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें 5.65 लाख पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी भी

शामिल हैं। इन सभी को इन नए कानूनों के बारे में सबको जागरूक करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। नए कानूनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी दखल बढ़ने से नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो (एनसीआरबी) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। अब देश के हरेक पुलिस स्टेशन में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लिकेशन के तहत सभी केस दर्ज होंगे।

सहज-सुलभ जांच और त्वरित न्याय के दस अहम प्रविधान

- एक व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए बगैर भी इलेक्ट्रानिक माध्यमों से घटना की रिपोर्ट कर सकता है। इससे पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी
- नए कानून में जीरो एफआइआर की शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना में एफआइआर दर्ज करा सकता है। इसकी निशुल्क कापी मिलेगी
- सशक्त जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सुबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फारेंसिक विशेषज्ञों का जाना अनिवार्य। सुबूत एकत्र करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में जांच एजेंसियों को दो महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। 90 दिनों के अंदर पीड़ितों को केस में प्रगति की नियमित अपडेट देनी होगी
- अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड या इलाज निशुल्क मिलने की गारंटी होगी। चुनौती भरी परिस्थितियों में भी पीड़ित जल्द ठीक हो सकेंगे
- गवाहों की सुरक्षा व सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी। दुष्कर्म पीड़िताओं को आडियो-वीडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट
- नए कानून में मामूली अपराधों के लिए दंडस्वरूप सामुदायिक सेवा की विधा शुरू। दोषी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेगा
- सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत अधिकतम दो बार ही स्थगित कर सकेगी। सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रानिक माध्यमों से हो सकेगी
- महिला पीड़िता की अदालती सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट ही करे। अन्यथा संवेदनशील मामले में किसी महिला की उपस्थिति में बयान हो दर्ज
- 15 साल से कम आयु, साठ साल से अधिक और दिव्यांगो व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में पेश होने से छूट होगी।

गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में स्थापित की गई महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा

संवाद सूत्र, पंजाबी जागरण • अमृतसर

पंजाब के प्रथम सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में बुधवार को स्थापित कर दी गई है। विदित हो कि महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा एक वर्ष से गुरुद्वारा साहिब में रखी गई थी। प्रतिमा स्थापना समारोह में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तथा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा, पीएमयू करतारपुर के अधिकारी तथा भारत के सिख श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अरोड़ा ने कहा कि प्रतिमा को करतारपुर साहिब में इसलिए पुनः स्थापित किया गया है ताकि करतारपुर कारिडोर से आने वाले सिख श्रद्धालु तथा अन्य सैलानी इसे देख सकें। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की समाधि की मरम्मत भी जल्द शुरू होगी। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में स्थापित कांस्य प्रतिमा मूल रूप से महाराजा रणजीत सिंह जी के 180वीं बरसी पर

श्री करतारपुर साहिब में स्थापित की गई महाराजा रणजीत सिंह कि प्रतिमा। सौ. जागरण

जून, 2019 में लाहौर के शाही किले में स्थापित की गई थी, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे तीन बार नुकसान पहुंचाया। पहले यह रानी जिंदां की हवेली के सामने रखा गया था। यूके के एसके फाउंडेशन के चेयरमैन व सिख इतिहासकार बोबी सिंह बांसल की ओर से उपहार में दी इस प्रतिमा में महाराजा रणजीत सिंह को अपने अरबी घोड़े केहर बहार की सवारी करते दिखाया गया है। इसे फकीर खाना संग्रहालय के डायरेक्टर फकीर सैफूद्दीन की देखरेख में तैयार किया गया है।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डा. कुलपति तिवारी का निधन

जागरण संवाददाता, वाराणसी

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डा. कुलपति तिवारी का बुधवार को निधन हो गया। 70 वर्षीय डा. कुलपति न्यूरो की बीमारी से ग्रस्त थे और ओरियाना अस्पताल रवींद्रपुरी में इलाज के दौरान शाम लगभग पांच बजे अंतिम सांस ली। रात में मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र वाचस्पति तिवारी ने दी। डा. कुलपति तिवारी ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी महंत परिवार की लोक परंपराओं के साथ बाबा से जुड़े वार्षिक पर्वोत्सवों यथा वसंत पंचमी पर बाबा का तिलकोत्सव, महाशिवरात्रि पर विवाहोत्सव, रंगभरी एकादशी पर गौना महोत्सव, सावन पूर्णिमा पर बाबा का झूलनोत्सव, दीपावली के अगले दिन अन्नकूट पर्व आदि आयोजनों को निरंतर जारी रखते हुए भव्यता प्रदान की। डा. कुलपति तिवारी का जन्म 10 जनवरी 1954 को हुआ। उनकी वैभवशाली जन्मकुंडली देख उनके दादा तत्कालीन महंत ज्योतिषाचार्य पं. महावीर प्रसाद तिवारी ने कुलपति नाम दिया था। बीएचयू से बीकाम-एमकाम के साथ समाजशास्त्र से एमए किया। 'श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर की संरचना और प्रकार्य विषय पर शोध कर डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पिता डा. कैलाशपति तिवारी ने कुलपति तिवारी को सामवेद के दस अक्षरों वाले मंत्र से दीक्षा दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर शोक संवेदना जताते हुए लिखा कि डा. कुलपति जी आज बाबा के चरणों में लीन हो गए। उनका शिवलोकगमन काशी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

डा. कुलपति तिवारी।

दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च पुल पर रेलवे का ट्राली निरीक्षण शुरू

संवाद सहयोगी, जागरण • रियासी

- सब सफल रहा तो रियासी से श्रीनगर तक ट्रेन का मिल सकती है हरी झंडी
- कटड़ा से रियासी के बीच 16 किलोमीटर खंड का कार्य अंतिम चरण में

दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च पुल से ट्रेन से सफर का सपना जल्द पूरा हो सकता है। रियासी से रामबन के संगलदान के बीच 46 किलोमीटर तक के रेल खंड के लिए सुरक्षा ट्रायल बुधवार को शुरू हो गए। यह ट्रायल सफल रहते हैं तो इस ट्रैक से ट्रेन संचालन को हरी झंडी जल्द मिल सकती है। फिलहाल संगलदान से बनिहाल के रास्ते श्रीनगर और बारामुला तक ट्रेन चल रही है। ऐसे में जम्मू से श्रीनगर रेल संपर्क जुड़ने केलिए कटड़ा से रियासी के बीच का 16 किलोमीटर के रेल खंड पर ट्रैक का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है।

बुधवार को रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल ने रियासी स्टेशन से अपने तकनीकी व सुरक्षा निरीक्षण की शुरुआत की। इस दौरान रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि जम्मू संभाग के संगलदान से कश्मीर संभाग का रेल संपर्क जुड़ गया है। बहुत जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क जोड़ने का सपना भी साकार हो जाएगा। उन्होंने रियासी स्टेशन से मोटर ट्राली में सवार होकर ट्रैक के निरीक्षण की शुरुआत की।

रियासी रेलवे स्टेशन से संगलदान ट्रैक के निरीक्षण के दौरान टनल नंबर 36 से गुजरते रेलवे सुरक्षा आयुक्त व रेलवे के अन्य अधिकारी। जागरण

अमरनाथ यात्री भी उठा सकेंगे रेल सेवा का आनंद

रियासी से कश्मीर के लिए रेल सेवा आरंभ हो जाती है तो अमरनाथ यात्रियों के लिए तोहफा होगा और वह अदभुत नजारों का आनंद ले सकेंगे। अमरनाथ यात्रा 29 जून से आरंभ हो रही है और बहुत संभव है रियासी से जुलाई के पहले सप्ताह में नियमित संचालन आरंभ हो जाए।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त के दौरे से पहले कई सफल ट्रायल किए गए

सुरक्षा आयुक्त के दौरे से पहले इस रेल खंड पर कई सफल ट्रायल पूरे किए गए हैं। 16 जून को पहली बार संगलदान से इलेक्ट्रिक इंजन को सबसे पहले गुजारा गया था। 20 जून को आठ डिब्बों की ट्रेन को दौड़ाया गया। 24 व 25 जून को भी ट्रायल किए गए।

मुंबई और माता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए विशेष ट्रेन

वि, नई दिल्ली: इन दिनों कई रूट की ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने डा. अंबेडकर नगर से माता वैष्णो देवी कटड़ा और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।

आज के भारत में आपातकाल की पुनरावृत्ति नहीं होगी : उपराष्ट्रपति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 1975 में आपातकाल लागू होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अंधेरे में डूब गया था। आज के भारत में आपातकाल की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। गांव, राज्य और केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक रूप से लोकतंत्र सुदृढ़ है। बुधवार को वह गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सीईएल) के स्वर्ण जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने विज्ञानियों और प्रौद्योगिकीविदों की भूमिका की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भारत के निर्माता हैं। कुछ वर्ष पहले घाटे में चलने वाले उपक्रम सीईएल का विनिवेश करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए थे। हाल ही में सीईएल बहुत उत्साहजनक प्रदर्शन करके लाभ अर्जित करने वाली 'मिनीरत्न' कंपनी बन गई है। इलेक्ट्रानिक युद्ध तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विलांस व निगरानी जैसी तकनीक में सीईएल की अहम भूमिका है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 27 जून, 2024
आजकल
www.jagran.com

सोवियत संघ में सक्रिय हुआ पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1954 में आज ही के दिन सोवियत संघ में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 'ओबनिस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र' सक्रिय किया गया था। यह बड़ी उपलब्धि थी मास्को ग्रिड से जुड़ा यह संयंत्र पांच मेगावाट बिजली का उत्पादन करता था। आज दुनिया भर में लगभग 400 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं।

पहली बार पता चला धूमपान से हो सकता है फेफड़ों का कैंसर

1957 में आज ही ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट में पहली बार यह सामने आया था कि धूमपान से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। रिपोर्ट में पिछले 25 वर्षों में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया कि इसका मुख्य कारण धूमपान था।

ओलिंपिक में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं ऊषा

पूर्व ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी ऊषा का जन्म 1964 में आज ही केरल में हुआ था। कम उम्र से ही दौड़ में रुचि लेने लगीं। 1978 में नेशनल इंटर-स्टेट मीट में जूनियर एथलीट के रूप में सुर्खियों में आ गईं। 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक (रजत) जीता। 1984 के लास एंजिलिस ओलिंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में ऊषा चौथे स्थान पर रहीं और एक सेकेंड से भी कम समय से कांस्य से चूक गईं। 2022 में भारतीय ओलिंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं।

गोर्डोनिया बताता है इंसानी दिमाग के विकास यात्रा की गाथा

25 करोड़ साल पहले सूअर जैसे एक प्राचीन जीव में पहली बार स्तनधारियों में दिमाग का विकास शुरू होने के संकेत मिले हैं। विज्ञानियों ने इसे गोर्डोनिया नाम दिया गया। यह जीव करोड़ों साल पहले धरती से लुप्त भी हो चुके हैं। यह शोध लिनेयन सोसायटी की जूलाजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ।

25 करोड़ साल पहले यह धरती पर मौजूद था, डायनोसोर की तरह हो चुका है लुप्त

1997 में मिला पहला जीवाश्म, विकास मानव या स्तनधारियों का विकास

दुनिया में स्तनधारियों के दिमाग के विकास का क्रम का आकलन करने के लिए गोर्डोनिया के दिमाग का थ्री डी इमेज तैयार किया गया। इंटरनेट मीडिया

जीवाश्म से थ्रीडी इमेजिंग

गोर्डोनिया का जीवाश्म 1997 में स्काटलैंड के एक बलुआ पत्थर के ब्लाक में दबा मिला था। इसमें इसकी खोपड़ी और निचला जबड़ा था। इस प्राचीन जीव के एक जीवाश्म पर हाई-रेजाल्यूशन के थ्रीडी इमेजिंग का इस्तेमाल कर रिसर्चर इसकी दिमाग की कोटर को देख पाने में सफल हुए हैं।

गोर्डोनिया।

धरती के रेतीले हिस्से में रहता था

प्रमाणों के मुताबिक 25 करोड़ साल पहले धरती का एक हिस्सा रेतीले टीलों से भरे रेगिस्तान जैसा था। इस जमीन पर एक जीव पल रहा था जिसकी संरचना काफी हद तक सूअरों जैसी थी। विज्ञानी ने इसे शुरुआती दौर का स्तनधारी बता रहे हैं।

गोर्डोनिया के शरीर के अनुपात में बड़ा दिमाग

जार्ज के अनुसार गोर्डोनिया के दिमाग का सामने का हिस्सा यानी फोरब्रेन किसी भी स्तनधारी की तुलना में अनुपात के आधार पर छोटा है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी स्टीव ब्रुसेटे के अनुसार उसका दिमाग हमारे दिमाग से अलग दिखता है, यह बड़े बलून जैसा नहीं है बल्कि मोटे तौर पर लंबा है, किसी मोड़ वाले ट्यूब जैसा। इसकी आकृति थोड़ी बेमेल है, लेकिन जब हम आयतन मापते हैं तो पता चलता है कि यह इसके शरीर की तुलना में दिमाग काफी बड़ा है।

कुछ ऐसा रहा विकास क्रम

- करीब तीन फीट लंबा और लगभग 22 किलो वजनी था
- थूथन और दांतों के मेल ने शाकाहारी जीवन जीने में मदद दी। रेगिस्तान में रसीली जड़ों को खोद कर खाने में मददगार साबित हुआ।
- 26.5 करोड़ साल पहले संभवतः पहली बार धरती पर दिखने शुरू हुए
- 20 करोड़ साल पहले जब धरती पर बड़े पैमाने पर जीव लुप्त हुए तो ये जीव भी गायब हो गए।
- पहली बार धरती पर 23 करोड़ साल पहले डायनासोर पैदा हुए।
- स्तनधारी पृथ्वी पर 21 करोड़ साल पहले आए, वे डायनासोरों के कदमों के नीचे रहकर विकास करते रहे।
- 66 लाख साल पहले जब उल्कापिंडों के कारण डायनासोर खत्म हो गए तो स्तनधारियों के लिए रास्ता साफ हो गया।

जागरण : नेशनल डेस्क

वियना में विशाल भित्ति-चित्र...

आस्ट्रिया में वियना इंटरनेशनल सेंटर के 50 मीटर ऊंचे तथा 20 मीटर चौड़ाई वाले टावर पर बना विशाल भित्ति-चित्र। यह संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर 16वें लक्ष्य 'शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान' को समर्पित है। यह वियना में सबसे बड़ा भित्ति-चित्र भी है। आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध स्ट्रीट आर्टिस्ट फिंटन मैगी द्वारा बनाई गई यह कलाकृति संयुक्त राष्ट्र के मानवीय तत्वों तथा शांति की नाजुकता का भी अन्वेषण करती है। इसे संयुक्त राष्ट्र के संगठनों के समर्थन तथा कैले लिब्रे स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल के सहयोग से तैयार किया गया है। रायटर

इधर-उधर की

विश्व का सबसे बदसूरत कुत्ता बना वाइल्ड थांग

कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी की वजह से बदसूरत बना थांग। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका में वाइल्ड थांग नाम का आठ वर्षीय कुत्ता विश्व के सबसे बदसूरत कुत्ते की प्रतियोगिता जीतकर चर्चा में आ गया है। दरअसल, पेकिंगीज नस्ल के थांग को 10 हफ्ते की उम्र में कैनाइन डिस्टेंपर नाम की बीमारी हो गई थी, जिस कारण दांतों का विकास रुक गया। जीभ लटक गई और एक पैर की मांसपेशियों में विकार आ गया। आयोजन करने वाली संस्था ने बताया कि लोगों को थांग जैसे कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विजेता थांग के मालिक एन लुईस को पांच हजार डालर इनाम में मिलेंगे।

नासा ने मौसम की निगरानी के लिए लांच किया गोज-यू

उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचने में लगेंगे लगभग दो सप्ताह

उपग्रह 35,700 किमी ऊंचाई पर पृथ्वी की करेगा परिक्रमा

नई दिल्ली, आइएएनएस : नासा ने बुधवार को अंतरिक्ष और पृथ्वी पर मौसम के साथ-साथ बड़े सौर तूफानों की निगरानी के लिए गोज-यू (जियोस्टेशनरी आपरेशनल एनवायर्नमेंटल सेटेलाइट यू) को सफलतापूर्वक लांच किया।

गोज-यू, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) और नासा की गोज-आर उपग्रह श्रृंखला में चौथा और अंतिम है। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन राकेट से शाम 5:26 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के भूस्थैतिक कक्षा के लिए रवाना किया गया। उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचने में लगभग दो सप्ताह लगेंगे और पहुंचने के बाद इसका नाम बदलकर गोज-19 कर दिया जाएगा। नासा ने एक्स पोस्ट में कहा है कि एनओएए का गोज-यू भूस्थैतिक कक्षा की ओर बढ़ रहा है, जहां यह पृथ्वी और अंतरिक्ष में मौसम के अध्ययन में सहायता करेगा।

अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा ने बुधवार को गोज-यू उपग्रह को सफलतापूर्वक लांच किया। एएफपी

यह वायुमंडलीय गतिविधियों की माप, आकाशीय बिजली की रियलटाइम मैपिंग और मौसम संबंधी खतरों का पता लगाने के लिए सात उपकरणों से सुसज्जित है। पहली बार इसमें काम्पैक्ट कोरोनोग्राफ भी शामिल है, जो बड़े प्लाज्मा विस्फोटों के लिए सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करेगा, जो भू-चुंबकीय सौर तूफान पैदा कर सकता है। गोज-यू 35,700 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। इसे लेकर स्पेसएक्स ने कहा कि यह वास्तविक समय के उच्च-रिजाल्यूशन इमेजरी, गंभीर मौसम का पहले से पता लगाने और ट्रापिकल साइक्लोन के पूर्वानुमान के साथ मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं और जलवायु शोधकर्ताओं की सहायता करेगा।

शबाना, एसएस राजामौली समेत अकादमी ने बनाए 487 नए सदस्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी, "आरआरआर" के निर्देशक एसएस राजामौली, निर्माता रितेश सिधवानी व प्रसिद्ध सिनेमैटोग्राफर रवि वर्मन समेत कई भारतीय सितारे इस वर्ष एकेडमी आफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा आमंत्रित किए गए 487 नए सदस्यों में शामिल हैं।

अकादमी ने वेबसाइट पर मंगलवार देर रात नए सदस्यों की सूची साझा की। लास एंजिलिस स्थित संस्थान के अनुसार, सदस्यता चयन पेशेवर योग्यता पर आधारित है। अकादमी ने जिन लोगों को शामिल किया है उनमें स्वतंत्र फिल्म निर्माता रीमा दास, आरआरके कास्ट्यूम डिजाइनर रामा राजामौली, कास्ट्यूम डिजाइनर शीतल शर्मा, निर्देशक निशा पाहुजा, स्ट्रीट ब्वाय के सह-निर्देशक राघव सिधवानी व डाक्यूमेंटी फिल्म निर्माता हेमल त्रिवेदी शामिल हैं। मालूम हो कि अमिताभ बच्चन, एआर रहमान, शाह रुख खान, आमिर, सलमान खान, काजोल व एकता कपूर जैसे कलाकार पहले से अकादमी के सदस्य हैं।

बुजुर्गों में लंबे समय तक अकेलेपन से बढ़ सकता है स्ट्रोक का जोखिम

अनुसंधान

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि लंबे समय तक अकेले रहने वाले बुजुर्गों में स्ट्रोक का जोखिम 56 प्रतिशत अधिक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2023 में अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया, जो प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। शोध का निष्कर्ष ईक्लिनिकलमेडिसिन जर्नल में मंगलवार को प्रकाशित हुआ है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि पिछले शोध ने अकेलेपन को हृदय रोगों के विकास के उच्च जोखिम से जोड़ा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं, अमेरिका के हार्वर्ड टीएच चान स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नए शोध में समय के साथ अकेलेपन में बदलाव और स्ट्रोक के जोखिम के बीच संबंधों की जांच की गई है। सामाजिक और व्यवहार विज्ञान विभाग में अनुसंधान सहयोगी व शोध के प्रमुख लेखक येनी सोह ने कहा, अध्ययन से पता चलता है कि अकेलापन स्ट्रोक की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पहले से ही दुनिया भर में दीर्घकालिक दिव्यांगता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है।

शोध दल ने कहा कि यह अध्ययन 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 8,936 प्रतिभागियों पर आधारित था, जिन्हें कभी स्ट्रोक नहीं हुआ था।

शोध के नतीजों से पता चला कि कम समय के लिए अकेले रहने वाले प्रतिभागियों में स्ट्रोक का उच्च जोखिम 25 प्रतिशत था। हालांकि, कम समय तक अकेले रहने वालों की तुलना में लंबे समय से लगातार अकेले रहने वालों में यह जोखिम 56 प्रतिशत पाया गया। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

अर्जुन की जन्मदिन पार्टी में गायब दिखी मलाइका

पिछले कई वर्षों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे अर्जुन और मलाइका। इस्टाग्राम (@malaikaaroraofficial)

जब मौका जन्मतिथि जैसे किसी विशेष दिन का हो, तो अपने प्रियजनों और दिल के करीब रहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति उसे और विशेष बना देती है। अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा पिछले कई वर्षों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस बीच दोनों के बीच मनमुटाव और अलगाव की भी खबरें आईं, लेकिन हर बार अर्जुन या मलाइका ने उन्हें अफवाह सिद्ध किया। मंगलवार रात को मौका था अर्जुन के जन्मतिथि पार्टी का। अर्जुन की 39वीं जन्मतिथि की पार्टी में उनकी बहनें जान्हवी कपूर और शनाया कपूर के साथ उनके चाचा संजय कपूर पत्नी महीप कपूर के साथ उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। इसके अलावा अभिनेता वरुण धवन पत्नी नताशा के साथ और आदित्य राय कपूर भी पहुंचे। जबकि मलाइका इस पार्टी में नहीं शामिल हुई। इससे एक बार फिर से दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरों को हवा मिला। अर्जुन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मलाइका इंस्टाग्राम पर भी जन्मदिन पर विशेष पोस्ट साझा करती थी। इस साल मलाइका ने वहां भी अर्जुन को शुभकामनाएं नहीं दी। इसकी जगह उन्होंने स्टोरी में लिखा कि मैं उन लोगों को पसंद करती हूं, जिन पर मैं आंखें बंद करके और पीठ पीछे करके भरोसा कर सकती हूं। जिससे दोनों के ब्रेकअप की खबरों को और बल मिला।

मैंने किसी से छुपाया नहीं कि मैं आमिर खान का बेटा हूं : जुनैद

महाराज के एक दृश्य में शालिनी पांडे के साथ जुनैद ● टीम जुनैद

बीते दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म महाराज से आमिर खान के बेटे जुनैद ने अपने अभिनय सफर का आगाज किया है। विवादों की वजह से फिल्म अदालत में घसीटी गई। हालांकि अदालत ने उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। फिल्म की रिलीज के बाद जुनैद ने खास बातचीत की...

थिएटर से की शुरुआत : एक्टिंग से लगाव को लेकर जुनैद बताते हैं, '16-17 साल की उम्र में ही मैंने तय कर लिया था कि एक्टर बनना है। मुझे थिएटर का शौक था। पहले मैंने सोचा था कि नेशनल स्कूल आफ ड्रामा (एनएसडी) में कोशिश की जाए, लेकिन वहां पर एडमिशन नहीं मिला। फिर विदेश में कालेज खोजा। जब पापा को बताया तो वह बहुत खुश हुए। वह बहुत सपोर्टिव हैं। फिर अमेरिका के एक कालेज से कोर्स किया। 2017 में वापस आया उसके बाद नाटक किया। फिल्मों के लिए कभी-कभी फोन आ जाते थे कि इसके लिए आडिशन कर लो, तो चला जाता था। फिर आदि सर (निर्माता आदित्य चोपड़ा) और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किसी दूसरी फिल्म के लिए मेरा आडिशन देखा था। वहां से मुझे महाराज का प्रस्ताव मिला। हालांकि मैंने किसी से छुपाया नहीं कि मैं आमिर खान का बेटा हूं। दरअसल, पापा इतने यंग दिखते हैं तो किसी को अहसास नहीं होता कि उनका इतना बड़ा बेटा भी हो सकता है।'

ऐसे हुई थी पहली कमाई : पहली कमाई को लेकर जुनैद बताते हैं, 'मेरी पहली कमाई पापा की फिल्म पीके से हुई थी, जिसमें राजकुमार हिरानी जी (निर्देशक) के साथ दो साल बतौर असिस्टेंट मैंने काम किया था। उससे मिली कमाई मैंने अपनी मां को दी थी।'

कार में नहीं, आटो में चलते हैं

आमिर खान के बेटे होने के बावजूद जुनैद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना पसंद करते हैं। इसकी वजह बताते हुए वह कहते हैं, 'मुंबई जैसे शहर में आटो रिक्शा से बेहतर ट्रांसपोर्ट नहीं है। कई बार मैं लोकल ट्रेन से भी चलता हूं। उससे दो घंटे का ट्रैफिक का समय बच जाता है। गाड़ी में आने पर बहुत सारा ट्रैफिक झेलो, फिर पार्किंग के लिए जगह आसानी से नहीं मिलती। इसलिए आटो से चलना ज्यादा आरामदायक है।'

...इसलिए की डिजिटल प्लेटफार्म से शुरुआत

डिजिटल प्लेटफार्म से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने को लेकर जुनैद कहते हैं, 'यशराज बड़ा बैनर है। सिद्धार्थ सर की फिल्म हिचकी बहुत अच्छी लगी थी। विपुल (मेहता) भाई और स्नेहा (देसाई) ने बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी, तो लगा कि क्यों न करें। उसके अलावा जयदीप अहलावत जैसे मंझे कलाकार सामने हो रहे तो बहुत सपोर्ट मिलता है।'

पदार्पण से पहले ही मिली तीन फिल्में

फिल्म महाराज की रिलीज से पहले ही जुनैद ने दो और फिल्मों की शूटिंग आरंभ कर दी थी। इनमें एक फिल्म के निर्माता उनके पिता हैं। जुनैद कहते हैं, 'मुझे हमारी महाराज काफी अच्छी लगी थी। लोगों ने नहीं देखी थी, लेकिन मुझे पसंद आई थी। उससे भी आत्मविश्वास आता है। दूसरी फिल्मों की कहानियां अच्छी थी, निर्देशक बेहतरीन हैं तो मुझे रुकने की कोई वजह नहीं दिखी। महाराज की शूटिंग खत्म करने के दो साल बाद मैंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग आरंभ की।'

दुख होता है, जब कम मेहनत करने वालों को काम मिलता है : अंकित गुप्ता

यूं तो अभिनय के क्षेत्र में काम पाने का एक तरीका आडिशन भी है, जिससे काम मिलता है। लेकिन इंटरनेट मीडिया के दौर में यह चीजें बंट गई हैं। रील्स पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले कई कलाकारों को सीधे मौके मिल जाते हैं। कई लोगों को काम इसलिए मिल जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उनके फालोवर्स बड़ी संख्या में हैं। जब ऐसे मौके मिलते हैं, तो उन कलाकारों को बुरा लगता है कि जो कई वर्षों की मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस बात का मलाल अभिनेता अंकित गुप्ता को भी है। जब अंकित से पूछा गया कि क्या इंटरनेट मीडिया के फालोवर्स को देखकर, आपके आसपास लोगों को काम मिलता है, तो बुरा लगता है? इस पर दैनिक जागरण से बातचीत में वह कहते हैं कि हां, लगता है। आप किसी चीज के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और वह काम उसे मिल जाए, जिसने आपसे कम मेहनत की है, तो दुख होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं अब इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हूं। छह-सात साल पहले मैं इस पर नहीं था। मुझे कई बार कहा गया है कि आपके इंटरनेट मीडिया पर फालोवर्स कम हैं, हम आपको कास्ट नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने इसे गंभीरता से लिया।

इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं अंकित। (@6_ankitgupta)

काजोल और प्रभु देवा के साथ काम कर आदित्य का सपना हो गया सच

जिन कलाकारों को देखकर बड़े हुए हैं, अगर उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। ऐसे ही खुशनुमा माहौल में इस वक्त तुम बिन 2 और स्टूडेंट आफ द ईयर 2 के अभिनेता आदित्य सील हैं। दरअसल, आदित्य को मिल गई है फिल्म महारागिनी, जिसमें पहले से ही काजोल और प्रभु देवा जैसे दिग्गज मौजूद हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में काम करने को लेकर आदित्य अपनी खुशी जताते हुए कहते हैं कि इस फिल्म में काम मिलना सपना सच होने जैसा है। मैं बहुमुखी प्रतिभा वाली अभिनेत्री काजोल और डांस के भगवान प्रभु देवा को देखते हुए बड़ा हुआ हूं। दोनों के ही साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मेरे लिए अवास्तविक पल है। ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने के मौके को लेकर मैं बेहद खुश हूं। महारागिनी का निर्देशन दक्षिण भारतीय मेकर चरणतेज उप्पलपति कर रहे हैं। यह उनका बालीवुड डेब्यू भी होगा। काजोल और प्रभु देवा इस फिल्म से 27 साल बाद दोबारा साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने साल 1997 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिनसारा कनवु में एक साथ काम किया था। हिंदी में इसे सपना नाम से रिलीज किया गया था।

काजोल संग स्क्रीन साझा करेंगे आदित्य। (@adityaseal)

घाटे में चल रहे वासु भगनानी को मिला अक्षय का भरोसा

निर्माता वासु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट के अंतर्गत बनी मिशन रानीगंज, गणपत और बड़े मियां छोटे मियां तीनों फिल्में फ्लाप रहीं। ऐसे में हाल ही में खबरें आईं कि घाटे में चल रही प्रोडक्शन कंपनी को भरपाई करने के लिए आफिस समेत कुछ संपत्ति बेचनी पड़ी और कई लोगों का मेहनताना भी बाकी है। इस बीच अब निर्माता वासु भगनानी का स्पष्टीकरण आया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में वासु ने बताया कि उन्होंने अपना आफिस बेचा नहीं है, बल्कि उसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आगे वासु ने इस दौर में अभिनेता अक्षय कुमार का भरोसा मिलने की भी बात कही। उन्होंने कहा, 'अक्षय सर का मुझे फोन आया कि वासु तुम बिल्कुल भी परवाह मत करो। तो मैंने कहा कि सर मैं तो परवाह कर ही नहीं रहा हूं। मेरे घर का चूल्हा वो लोग नहीं चला रहे हैं, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अगर उनकी फिल्म चलती है तो अलग रूप देखने को मिलता है। अब अक्षय कुमार को ही देख लें, जैसे ही उनकी फिल्म (बड़े मियां छोटे मियां) नहीं चली, उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया कि वासु चिंता मत करो, जो भी होगा हम लोग मिल बांटकर करेंगे। मेरी अली अब्बास जफर (निर्देशक) से भी वही बात चालू है। हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे किसी का भी। हमें तो धंधा करना है न।

नहीं चल पाई थी वासु के प्रोडक्शन में बनी अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। फाइल

सहिष्णुता का प्रशंसक नहीं हूं

साल 1996 में प्रदर्शित फिल्म हिंदुस्तानी (तमिल में इंडियन) की सीक्वल फिल्म हिंदुस्तानी 2 : जीरो टालरेंस कई रुकावटों और उतार-चढ़ाव के बाद बनकर तैयार है। फिल्म में अभिनेता कमल हासन एक बार फिर से सेनापति की भूमिका में नजर आएंगे। 12 जुलाई को प्रदर्शित हो रही इस अखिल भारतीय फिल्म की टैगलाइन है जीरो टालरेंस यानी शून्य सहिष्णुता। मंगलवार को मुंबई में इसके ट्रेलर लांच के मौके पर समाज में जीरो टालरेंस वाले मुद्दों पर कमल हासन ने कहा, 'मैं गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। लोग कहते हैं कि उन्होंने सहिष्णुता सिखाई है, लेकिन मैं सहिष्णुता का प्रशंसक नहीं हूं। समाज में आपको जिन भी चीजों के लिए सहिष्णु रहना पड़ता है, वह एक सिरदर्द है। जो भी चीज समाज के लिए सिरदर्द हो उसके लिए जीरो टालरेंस होनी चाहिए। उसकी इलाज खोजो और उसे दूर करो।' इस दौरान कमल हासन ने भ्रष्टाचार पर शासन से सवाल पूछने वाली फिल्मों को लेकर कहा, 'स्थापित शासन के विरुद्ध सवाल उठाने वाली समस्या तो अंग्रेजों के जमाने से रही है। लोग तो तब भी ऐसी फिल्में बनाते थे। हम इस तरह की फिल्में बनाते रहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि शासन के शीर्ष पर कौन है।'

सेनापति की भूमिका में नजर आएंगे कमल ● मिडडे आर्काइव

अब रोहित बने ठग लाइफ का हिस्सा

नए काम की तलाश में अब अभिनेता रोहित सराफ चाकलेटी और रोमांटिक किरदारों से निकलकर दक्षिण भारतीय फिल्मों का रुख कर चुके हैं। बालीवुड गलियारों में चल रही खबरों के अनुसार निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइफ में रोहित को भी मौका मिला है। इस फिल्म की शूटिंग इस साल जनवरी से ही चल रही है। फिल्म में त्रिशा कृष्णन भी हैं। रोहित को इस फिल्म में एक अहम रोल करने का मौका मिला है। वह अपने हिस्से की शूटिंग शुरू भी कर चुके हैं। वह मणिरत्नम के प्रशंसक हैं, ऐसे में रोहित के लिए यह बड़ा मौका है। इस फिल्म को बड़े बजट में बनाया जा रहा है। फिलहाल फिल्म को लेकर कई जानकारियां गोपनीय रखी गई है। लेकिन मिली जानकारियों के अनुसार अगस्त तक ठग लाइफ की शूटिंग पूरी हो जाएगी। दिसंबर तक फिल्म रिलीज करने की योजना है। रोहित इसके अलावा करण जौहर निर्मित फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी होंगे। यह फिल्म अगले साल 19 अप्रैल को रिलीज होगी।

अब दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर बढ़ चले रोहित ● मिडडे आर्काइव

****